एक गांव से दो-दो मंत्री, पूरा प्रखंड उपेक्षित

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

भाजपा नेत्री शोभा पटेल का तीखा हमला, बोलीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से पुछा कि, "जहाँ एक ही गांव में सत्ता की बारिश हो रही हो और पूरा प्रखंड बूंद-बूंद विकास को तरस रहा हो, वहाँ लोकतंत्र नहीं, राजनीतिक पक्षपात पलता है।" भाजपा नेत्री शोभा पटेल ने राज्य की राजनीति पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि यह लोकतंत्र के इतिहास का सबसे विचित्र और दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य है कि एक ही गांव से दो-दो मंत्री बन जाते हैं, जबकि उसी प्रखंड के कई इलाके आज तक एक विधायक तक नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि यह केवल संयोग नहीं बल्कि सत्ता के केंद्रीकरण और राजनीतिक असंतुलन का जीवंत उदाहरण है। शोभा पटेल ने कहा कि जनता यह देखकर स्तब्ध है कि कुछ गांवों पर सत्ता इतनी मेहरबान हो जाती है कि मंत्री पद भी वहीं घूमता रहता है, जबकि पूरा प्रखंड सड़क, अस्पताल, कॉलेज, सिंचाई, रोजगार और मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करता रह जाता है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि "कुछ लोगों के गांव में मानो मंत्री पैदा करने की फैक्ट्री खुल गई है और बाकी जनता केवल ताली बजाने के लिए छोड़ दी गई है।" उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व का अर्थ पूरे क्षेत्र का सम्मान होता है, न कि कुछ खास परिवारों और गांवों का राजनीतिक साम्राज्य। यदि एक ही क्षेत्र विशेष को बार-बार सत्ता का केंद्र बनाया जाएगा तो बाकी समाज में उपेक्षा, असंतोष और राजनीतिक निराशा स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। भाजपा नेत्री ने कहा कि जिस प्रखंड के लोगों ने दशकों तक पार्टी और नेताओं के लिए संघर्ष किया, वहीं आज सबसे अधिक उपेक्षित हैं। गाँवों में न उद्योग पहुँचा, न शिक्षा की व्यवस्था सुधरी, न युवाओं को रोजगार मिला, लेकिन सत्ता के गलियारों में कुछ चेहरे लगातार चमकते रहे। यही कारण है कि जनता अब सवाल पूछ रही है कि आखिर लोकतंत्र जनता के लिए है या कुछ प्रभावशाली समूहों के लिए? उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि "जनता वोट दे, संघर्ष करे, लाठी खाए और पुरस्कार में मिले राजनीतिक उपेक्षा, यह कब तक चलेगा?" उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि राजनीति परिवार, गांव और गुट की सीमा से बाहर निकलकर पूरे क्षेत्र के समान विकास की बात करे। शोभा पटेल ने कहा कि जनता सब देख रही है। लोकतंत्र में जनता की चुप्पी को कमजोरी समझना सबसे बड़ी भूल होती है। आने वाले समय में वही जनता विकास, प्रतिनिधित्व और राजनीतिक न्याय का हिसाब मांगेगी, जिसे वर्षों तक केवल आश्वासन देकर शांत रखा गया।●

जब अपराध रूक नहीं रहा है तो पुलिस पर खर्च क्यों!

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

भाजपा मीडिया प्रभारी डॉ लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने कहा कि राज्य में अपराध की आग लगातार भड़क रही है। हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार और गोलीबारी की घटनाएँ रोज अखबारों की सुर्खियाँ बन रही हैं। ऐसा लगता है जैसे अपराधियों के मन से कानून का डर पूरी तरह समाप्त हो चुका है। सड़कों पर खून बह रहा है, घरों में मातम पसरा है और सरकार केवल बैठकों, घोषणाओं और दावों में व्यस्त है। जब अपराध नहीं रुक रहा, निर्दोष लोगों की लाशें लगातार गिर रही हैं, तब जनता के मन में स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि आखिर सरकार और पुलिस पर करोड़ों रुपये खर्च क्यों किए जा रहे हैं? यदि सुरक्षा देने वाली व्यवस्था ही असफल है, तो यह खर्च जनता के टैक्स की बर्बादी नहीं तो और क्या है? हर दिन किसी जिले से हत्या, कहीं व्यापारी से लूट, कहीं महिला से दुष्कर्म, कहीं युवक की गोली मारकर हत्या, कहीं अपहरण, ऐसी खबरें आम हो चुकी हैं। अपराध अब घटना नहीं, व्यवस्था की पहचान बनता जा रहा है। सरकार को अब जवाब देना होगा कि आखिर कब तक जनता भय के साये में जीती रहेगी? कब तक माताओं की गोद सूनी होगी? कब तक बच्चों के सिर से पिता का साया उठता रहेगा? यदि अपराध पर लगाम नहीं लगती, तो जनता का आक्रोश सड़कों पर उतरना तय है। मुजफ्फरपुर में माँ और दो मासूम की हत्या हुई। हलवाई संतोष की पत्नी रीता देवी 25 साल, तीन साल की बेटी वैष्णवी और सात माह का दुधमुँहा रुद्र। तीनों के गले में एक ही लाल फीते का फंदा लिपटा था। भागलपुर में नगर परिषद कार्यालय में कृष्ण कुमार की हत्या कर दी गई। धनरूआ में छत पर सोई बच्ची के पेट में गोली लगी। वह माँ के साथ शादी में आई थी। पुत्री की पहचान सौम्या कुमारी के रूप में हुई। भाजपा मीडिया प्रभारी डॉ लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने बिहार के मुख्यमंत्री से कहा कि यदि आपको अपराध रोकना है तो प्रधानमंत्री मोदी से हरेक जिले के लिए पटना के पूर्व एसपी किशोर कुणाल की तरह तथा हरेक थाना के लिए फतुहा के पूर्व थाना प्रभारी केके साहू, रघुनाथ सिंह की तरह अधिकारी माँगे या दोनों की तरह पुलिस अधिकारी बनाने के लिए गुरुकुल स्कूल में शिक्षा देनी होगी।●

पत्रकारों को महिला कारा गृह में प्रतिबंध क्यों?

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

पत्रकारों को जेल और महिला सुरक्षा गृह में एंट्री बंद करना आखिर किस सच को छिपाने की कोशिश है? भाजपा जिला मीडिया प्रभारी डॉ. लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, राष्ट्रपति तथा सुप्रीम कोर्ट से मांग करते हुए कहा कि पत्रकार किसी सरकार के विरोधी नहीं, बल्कि लोकतंत्र के सबसे सशक्त और मुफ्त के सहयोगी होते हैं। जो सच जनता तक पहुंचाता है, वही असली प्रहरी होता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज उसी प्रहरी के रास्ते में दीवारें खड़ी की जा रही हैं। डॉ. पटेल ने तीखे शब्दों में कहा कि जेलों में हजारों गरीब, निर्दोष और बेगुनाह लोग वर्षों से घुट-घुट कर जिंदगी काट रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। सरकारी फाइलों में सब कुछ "सामान्य" दिखाया जाता है, जबकि जेलों की दीवारों के पीछे इंसानियत कराह रही है। यदि पत्रकारों को सप्ताह में एक दिन भी जेल सर्वेक्षण की अनुमति मिल जाए, तो सरकार को मुफ्त में सच्चाई का आंकड़ा मिल जाएगा। तब पुलिस भी निर्दोष लोगों को झूठे मामलों में जेल भेजने से पहले सौ बार सोचेगी। उन्होंने कहा कि सत्ता का सबसे बड़ा डर कैमरा

और कलम से होता है, क्योंकि पत्रकार वही दिखाता है जिसे छिपाने की कोशिश की जाती है। अगर जेलों के दरवाजे पत्रकारों के लिए खुल जाएं, तो भ्रष्टाचार, अत्याचार और फर्जी मुकदमों की परतें खुद-ब-खुद खुलने लगेंगी। डॉ. पटेल ने Muzaffarpur Shelter Home Case का उल्लेख करते हुए कहा कि मुजफ्फरपुर महिला सुरक्षा गृह कांड ने पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया था। मासूम बच्चियों की अस्मिता को सत्ता और संरक्षण के दलालों ने बाजार बना दिया। यह केवल अपराध नहीं था, बल्कि व्यवस्था के चेहरे पर ऐसा काला धब्बा था जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। यदि उस समय पत्रकारों को सुरक्षा गृहों में नियमित रूप से जाने और सच्चाई उजागर करने की स्वतंत्रता होती, तो शायद इतनी भयावह घटनाएं जन्म ही नहीं लेतीं। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर पत्रकारों को रोकने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या सरकार को डर है कि सच्चाई बाहर आ जाएगी? क्या लोकतंत्र में अब सच बोलना भी अपराध माना जाएगा? जेल हो या महिला सुरक्षा गृह, जहां जनता के टैक्स का पैसा खर्च होता है, वहां जनता की आंख यानी पत्रकारों को रोकना लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा हमला है। क्योंकि जहां पत्रकार की पहुंच रुकती है, वहीं से भ्रष्टाचार और अमानवीयता का अंधेरा शुरू होता है।●

किसान की जमीन छीनकर शहर बसाने की जिद्द बंद करें

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

भाजपा मीडिया प्रभारी डॉ लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने कहा कि बिहार में विकास के नाम पर जो खेल चल रहा है, वह अब सवालों के घेरे में है। किसानों को उनकी ही जमीन के पास विकसित प्लॉट देने की बात सुनने में भले आकर्षक लगे, लेकिन असलियत यह है कि यह नीति किसान की जड़ों पर प्रहार है। जिस मिट्टी से अन्न उगता है, उसी को कंक्रीट में बदल देने की जल्दबाजी आखिर किसके हित में है? भाजपा मीडिया प्रभारी डॉ. लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल का यह कहना बिल्कुल सटीक है कि सरकार की प्राथमिकता तय करने में भारी चूक हो रही है। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या शहर का विस्तार ज्यादा जरूरी है या अन्न का उत्पादन? क्योंकि सच्चाई यह है कि "अन्न सिर्फ जमीन पर ही पैदा होता है, प्लॉट पर नहीं।" अगर खेत ही खत्म हो गए, तो कल भूख की मार से कौन बचाएगा? सरकार की नीति कहीं न कहीं किसानों को उनके अस्तित्व से अलग करने का प्रयास लगती है। जमीन छीनकर प्लॉट देने की नीति किसान को मजदूर बनाने की साजिश जैसी प्रतीत होती है। यह केवल जमीन का मामला नहीं, बल्कि किसान की पहचान, आत्मसम्मान और उसके भविष्य का प्रश्न है। अगर सरकार सच

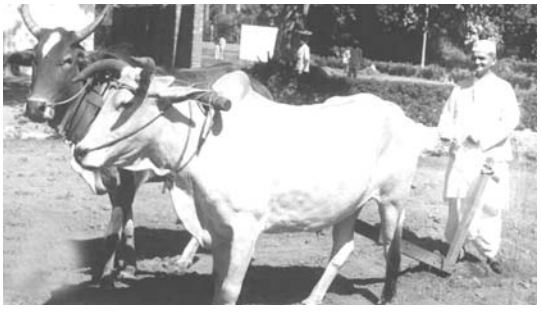

में किसानों का भला चाहती है, तो उन्हें मजबूर करने के बजाय विकल्प देना होगा। किसानों को नौकरी देने की बात कही जा रही है, लेकिन क्या हर किसान नौकरी के लिए बना है? क्या उसकी पीढ़ियों से जुड़ी खेती की परंपरा को यूं ही खत्म कर देना न्यायसंगत है? सरकार को चाहिए कि वह जमीन अधिग्रहण की जगह कृषि को मजबूत करने पर ध्यान दे। आधुनिक तकनीक, सिंचाई की सुविधा, उचित मूल्य और बाजार की व्यवस्था। ये सब कदम किसानों को सशक्त बनाएंगे, न कि उनकी जमीन छीनकर उन्हें मुआवजे के नाम पर शांत करना। आज जरूरत है एक स्पष्ट और कठोर निर्णय की, विकास का मतलब किसान को उजाड़ना नहीं हो सकता। अगर सरकार सच में विकास चाहती है, तो उसे "किसान बचाओ, देश बचाओ" की सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। वरना वह दिन दूर नहीं जब खेतों की जगह इमारतें खड़ी होंगी और थाली में अन्न के लिए लोग तरसेंगे। तब सवाल सिर्फ सरकार पर नहीं, पूरे सिस्टम पर उठेगा। क्या हमने विकास के नाम पर अपनी जड़ें ही काट दीं? पूर्वी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था जय जवान जय किसान। आज कि सरकार शायद नारा बदल दिया जय शहर जय सरकार? लाल बहादुर शास्त्री किसान थे स्वयं हल चलाते थे। आज तो टाई बेलट वाले भी अपने को किसान कहते हैं।●

एक घंटे के अंदर जेल भेजो : सरदार पटेल

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

भाजपा मीडिया प्रभारी डा लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने कहा कि देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सत्ता को कभी शाही तख्त नहीं, बल्कि जनता की चौखट माना था। कहा जाता है कि शपथ ग्रहण के तुरंत बाद उन्होंने घोषणा की थी कि प्रतिदिन एक घंटा आम जनता की समस्याएं सुनेंगे। यह केवल घोषणा नहीं थी, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा थी। सत्ता का अर्थ जनता की रक्षा, न्याय की स्थापना और निर्दोषों की सुरक्षा था। पहले ही दिन कानपुर से एक बुजुर्ग महिला अपनी फरियाद लेकर पहुंची। आंखों में आंसू, चेहरे पर दर्द और आवाज में करुण पुकार थी। उसने कहा, "मेरा बेटा निर्दोष है, एक महीने से जेल में सड़ रहा है, आप स्वयं चलकर देख लीजिए।" यह शब्द सुनते ही सरदार पटेल ने मामले को गंभीरता से लिया। तत्काल पुलिस अधिकारी को फोन लगवाया और कड़े स्वर में कहा, "यदि एक घंटे के भीतर निर्दोष युवक जेल से बाहर नहीं आया, तो अगला दिन तुम्हारे लिए भारी पड़ेगा।" यही था वह प्रशासन, जहां कुर्सी का डर अपराधियों में होता था, जनता में नहीं। जहां सत्ता जनता की नौकर

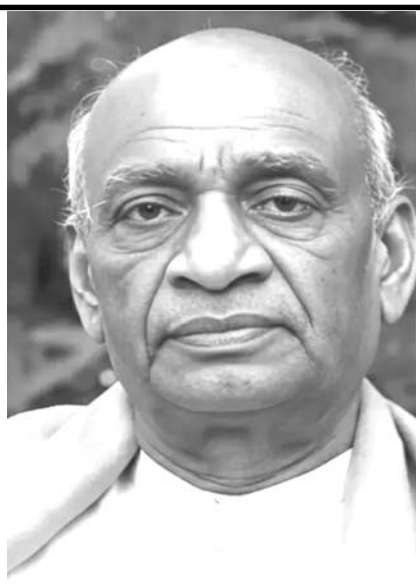

थी, मालिक नहीं। आज तस्वीर उलटी दिखाई देती है। आज गरीब, किसान, मजदूर, बेरोजगार और बेबस लोग थाने और अदालत के चक्कर काटते-काटते टूट जाते हैं, लेकिन सत्ता के वातानुकूलित कमरों में बैठी संवेदनहीन राजनीति को उनकी चीख सुनाई नहीं देती। आज देश की जेलों में हजारों नहीं, लाखों ऐसे लोग बंद हैं जिनका अपराध केवल गरीबी है, कमजोर होना है, सिफारिश और पैसा न होना है। वर्षों तक मुकदमे चलते हैं, परिवार बर्बाद हो जाते हैं, मां-बाप की आंखें रो-रोकर सूख जाती हैं, लेकिन सत्ता के मलाई चाटने वालों को यह दर्द दिखाई नहीं देता। नेताओं के भाषणों में न्याय की बातें होती हैं, लेकिन जमीन पर निर्दोष इंसाफ के लिए तड़पता रहता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सत्ता में बैठे लोग हर छोटी राजनीतिक घटना पर रातों-रात कार्रवाई कर सकते हैं, तो निर्दोषों की रिहाई के लिए उनकी आत्मा क्यों नहीं जागती? क्या गरीब की जिंदगी की कोई कीमत नहीं? क्या कानून केवल कमजोरों को कुचलने के लिए बचा है? क्या लोकतंत्र अब केवल चुनाव जीतने का माध्यम बनकर रह गया है? आज आवश्यकता है सरदार पटेल जैसी कठोर इच्छाशक्ति की, जहां अधिकारी जनता के सेवक बनें, सत्ता का भय अपराधियों में हो और निर्दोष व्यक्ति जेल की सलाखों के पीछे सड़ने को मजबूर न हो। अन्यथा इतिहास पूछेगा कि जिस देश ने लौह पुरुष पैदा किया, उसी देश की राजनीति इतनी कमजोर और संवेदनहीन कैसे हो गई कि निर्दोषों की चीख भी सत्ता के कानों तक नहीं पहुंची?●

बुढ़ापे में प्रोस्टेट का होम्योपैथिक में है कारगर ईलाज

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

भाजपा कार्यालय मां तारा उत्सव पैलेस गोविंद पुर फतुहा में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया जिसका अध्यक्षता भाजपा नगर के वरिष्ठ उपाधयक्ष अनील कुमार शर्मा तथा मुख्य अतिथि सुप्रसिद्ध होमियोपैथी चिकित्सक डॉ लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल। मुख्य अतिथि डॉ लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने कहा कि प्रोस्टेट एक ग्लैण्ड है, जो पेशाब के मुख्य मार्ग के चारों और की एक कड़ी ग्लैण्ड है जिसका स्थान पेशाब मुख्य मार्ग पर है। इसलिए इसे मूत्रशायी ग्रंथि कहा जाता है। किसी भी कारण स्वरूप सूजन आ जाती है। तब इसमें दर्द होता है और सूजन आने के कारण पेशाब रुक जाता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है जिसमें मवाद हो जाता है जिससे पेशाब में रक्त एवं मवाद आने लगता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि 60 वर्ष की आयु में कितने बुजुर्ग के प्रोस्टेट ग्रंथि वृद्धि होने के कारण पेशाब संबंधित नाना प्रकार की शिकायत उत्पन्न हो जाती है।

☞ **होम्योपैथिक चिकित्सा** :- दवा का नाम सैवाल सेरुलेटा-मदर टिंचर यह प्रोस्टेट वृद्धि की एक महत्वपूर्ण दवा है। यह नए और पुराने दोनों में उपयोगी है। पेशाब करने में कष्ट, आग के तरह जलन, यंत्रणा एकाएक पेशाब बंद, कैथिटर से पेशाब होना, ऐसा मालूम होता है कि जैसे नली में आकर कुछ फंसा हुआ है। इस प्रकार के लक्षणों में यह एक पेटेंट दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका मदर टिंचर पांच छ बुद पानी में मिलाकर दिन में तीन बार दिया जा सकता है। दूसरा दवा है हाइड्रेणिजया मदर टिंचर यह बजुर्गों का प्रोस्टेट ग्रंथि वृद्धि में चमत्कारी दवा है। मदर टिंचर 5/6 बुदं एक औंस पानी में तीन बार लेना है। तीसरा दवा है। सालिडेगा मदर टिंचर बुढ़ापे में प्रोस्टेट ग्रंथि की वृद्धि के कारण पेशाब रुकना, जिस कारण पेशाब कैथिटर से निकालना पड़ता है। तब इसकी मदर टिंचर की तीन-चार बूंद एक औंस जल में मिलाकर तीन बार देते रहने से तीन चार माह के अंदर आरोग्य हो जाता है। यह होम्योपैथिक का कैथिटर है। चौथा दवा है कोनियम मैक 30/200 बुजुर्ग के प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ने के कारण यदि रुक रुककर पेशाब आता है यह दवा सर्वोत्तम है। एक बुंद तीन बार रोज। तीन चार माह में ठीक हो जाता है। पांचवा दवा है कैलकेरिया फ्लोर 6X बायोकेमिक प्रोस्टेट ग्रंथि की वृद्धि की सबसे बढ़िया दवा है। इसका चार-पांच गोली जल के साथ तीन चार बार लें। यह महत्वपूर्ण दवा है। इस अवसर पर रेखा शर्मा, सीमा कुमारी, पुजा कुमारी, अकुश कुमार, अनिष कुमार, शीला पटेल, शोभा पटेल, ममता पटेल, जितेंद्र मिस्त्री आदि शामिल हुए कोई भी दवा चिकित्सक के सलाह से ही दवा लें।●

● **प्रो० रामजीवन साहु**

संयोग को सामान्यत: व्यक्ति दुर्लभ घटना मानते हैं, परन्तु ऐसा चिंतन करना मिथक जैसा प्रतीत होता है. संयोग शब्द में चार अक्षर और एक मात्रा है. स+न+य+ओ+ग=संयोग. ये चारों अक्षर और मात्रा संयोग को परिभाषित करता है. स से सत्यवादी, न से न्यायप्रिय, य से योग्यतापूर्ण, ओ से ओजस्वी वक्ता और ग से गरिमामई. अर्थात जो महामानव सत्यवादी, न्यायप्रिय, योग्यतापूर्ण ,ओजस्वी वक्ता और गरिमामई हो उसी के साथ संयोग बैठता है. संयोग सिर्फ कलियुग की ही आश्चर्यजनक घटना नहीं है, बल्कि चारों युगों में संयोग देखा गया है.

❖ **सतयुग :-** ऋषि-मुनियों में महर्षि कश्यप सबसे श्रेष्ठ ऋषि हुए हैं. इस सृष्टि के रचियता काश्यप ऋषि ही हैं. संयोग यह है कि इनको 17 पत्नी थी. उनमें से एक का नाम दिति थी. उसके हठधर्मिता के कारण उसके कोख से हिरण्यकशिपु नाम का एक पुत्र का जन्म हुआ, जो नाश्तिक था. इतना ही नहीं वह स्वयं को भगवान मानता था. यह भी एक संयोग है कि इस नाश्तिक हिरण्यकशिपु का पुत्र था भक्त प्रहलाद जो हमेशा भगवान का नाम रटते रहता था. हिरण्यकशिपु प्रहलाद से कहता था भगवान का नाम नहीं रटो. उसके स्थान पर मेरा नाम रटो .उसके आज्ञा का पालन नहीं करने पर उसे मरवाने का कोशिश किया गया. कभी पहाड़ पर से गिराया गया, कभी समुद्र में फेंका गया, कभी पागल हाथी के सामने रखा गया, तो कभी आग में बिठाया गया. संयोग है कि वह सभी जगहों से सुरक्षित लौट आया. हिरण्यकशिपु को वरदान प्राप्त था कि मैं न दिन में मरूं न रात में ,न आकाश में न जमीन पर, न घर में न बाहर ,न मनुष्य से न पशु से और न अस्त्र से न शत्र से मरूं .संयोग है कि इतना वरदान मिलने के बाद भी वह मारा गया. इसके लिए भगवान को नरसिंह अवतार लेना पड़ा .उसे संध्या के समय अपने जंघा पर बिठाकर चौखठ पर नाखून से उसके छाति को फाड़कर मौत दे डाली।

❖ **त्रेतायुग :-** जगत जननी सीता माता पहली बार अपने ससुराल अयोध्यापुरी आईं. एक दिन शुभ मुहुर्त देखकर योजना बनी कि सीताजी के हाथ का बना भोजन हम सबों को ग्रहण करना चाहिए. स्वादिष्ट खीर सीताजी ने बनाई. सर्वप्रथम महाराजा दशरथजी को सोने की थाली में खीर परोसकर दिया गया. यह संयोग है कि जैसे ही उनके पास थाली गई कि त्तक्षण उस थाली में एक छोटा सा तिनका गिर गया. सीताजी क्रोधित होकर उस तिनके को देखीं, फलस्वरुप वह तिनका तुरंत जलकर राख हो गया. दशरथजी इस घटना के पश्चात् सीताजी से बोले पुत्र बधु आज के बाद कभी किसी को इतना क्रोधि त होकर नहीं देखना. सीताजी विषम परिस्थिति में भी दशरथजी के दिये हुए आदेश का पालन करती रही, वरणा स्वर्णमयी लंकापति रावण जिस समय अपहरण के लिए आया था, उसी समय वह जलकर राख हो जाता.

❖ **द्वापरयुग :-** महाभारतकालीन पांडवों की पत्नी कुन्ती को सूर्य देवता की कृपा से एक पुत्र हुआ, जिसका नाम कर्ण था. कर्ण का जन्म कवच और कुंडल के साथ हुआ था. वह पांडव का सबसे बड़ा सहोदर भाई था. संयोग है कि पांडव का सबसे बड़ा भाई था फिर भी कर्ण महाभारत युद्ध में उसने पांडव का विरोधी कौरव के पक्षी में युद्ध किया. यह भी एक संयोग है कि कौरव सौ भाई थे, फिर भी वे युद्ध में पराजित हुए.

❖ **कलियुग :-** स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद बने. वे पढ़ने में कुशाग्रबुद्धि के थे. यह संयोग है कि विद्यार्थी जीवन में उनके उत्तर पुस्तिका के मुल्यांकन में एक शिक्षक महोय ने लिखा कि परीक्षार्थी परीक्षक से बेहतर है.

❖ **अमेरिका :-** अमेरिका में दो बड़े महामानव राष्ट्रपति हुए अलग -अलग कालखंड में एक मिस्टर अब्राहम लिंकन दूसरे मिस्टर जान एफ कैनेडी.

❖ **दोनों का क्या आश्चर्यजनक संयोग है:-**

☞ दोनों के उपनाम में 7-7 अक्षर हैं.

☞ कांग्रेस में प्रवेश एक 1846 दूसरे 1946.

☞ राष्ट्रपति बने एक 1860 दूसरे 1960.

☞ हत्या का दिन दोनों का शुक्रवार.

☞ गोली के स्थान दोनों के सिर के पिछले भाग में.

☞ दोनों के हत्यारे के नाम में 15-15 अक्षर एक John Wilkes Booth दूसरे Lee Harvey Oswald.

☞ दोनों के हत्या के समय उनकी पत्नी और एक दूसरा जोड़ा भी था.

☞ दोनों के हत्यारे पर मुकदमा नहीं चलाया गया और उसकी स्वभाविक मृत्यु हुई.

☞ दोनों के उत्तराधिकारी के उपनाम एक समान एक एंड्रयू जॉनसन दूसरे लिंडन जॉनसन.

☞ जन्म एक का 1808 दूसरे का 1908. ●

विकास कार्यों में तेजी आने से लोगों में बढ़ी उम्मीद

● श्रीकांत कुमार श्रीवास्तव

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जीत के बाद जहानाबाद डेवलपमेंट कमिटी (JDC) के एक प्रतिनिधिमंडल ने शहर की विभिन्न जनसमस्याओं एवं विकास कार्यों को लेकर स्थानीय विधायक श्री राहुल कुमार जी से विस्तृत मुलाकात की थी। इस मुलाकात में शहर में वर्षों से चली आ रही जलजमाव, जल निकासी, सीवरेज व्यवस्था, सड़क एवं आधारभूत संरचना से जुड़ी समस्याओं को गंभीरता से उठाया गया था। कमिटी द्वारा दिए गए सुझावों एवं मांगों पर विधायक जी द्वारा त्वरित पहल किए जाने के बाद अब कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिल रही है।

लगभग 2 वर्षों से लंबित 50 करोड़ रुपये की लागत से बन रही स्टॉर्म वॉटर ड्रेन परियोजना के कार्य में अब तेजी आई है तथा शहर के कई क्षेत्रों में चौड़े नालों का निर्माण कार्य स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। लंबे समय से धीमी गति से चल रही इस महत्वपूर्ण परियोजना के सक्रिय होने से शहरवासियों में उम्मीद जगी है कि भविष्य में जलजमाव एवं जल निकासी की समस्या का स्थायी समाधान संभव हो सकेगा।

इसके साथ ही विधायक श्री राहुल कुमार जी के प्रयासों से BUDCO का कार्यालय जहानाबाद में खोला गया है तथा कार्यालय में प्रोजेक्ट डायरेक्टर की नियुक्ति भी की गई है। स्थानीय स्तर पर कार्यालय खुलने एवं प्रोजेक्ट डायरेक्टर की तैनाती होने से परियोजनाओं की निगरानी, जनसमस्याओं के त्वरित समाधान तथा विकास कार्यों के बेहतर समन्वय में काफी सुविधा होगी। कमिटी ने इसे शहर के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है।

अमृत योजना 2.0 के अंतर्गत लगभग 317 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली STP (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट) परियोजना की टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है तथा शहर के विभिन्न वार्डों में सर्वे का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इस परियोजना के लागू होने के बाद आधुनिक सीवरेज एवं जल निकासी व्यवस्था विकसित होगी, जिससे प्रत्येक घर से निकलने वाले अपशिष्ट जल के समुचित निष्पादन की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी। इससे शहर की स्वच्छता व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

जहानाबाद डेवलपमेंट कमिटी के अध्यक्ष देवांशु दीपक ने कहा कि शहर के विकास एवं जनसमस्याओं के समाधान को लेकर कमिटी लगातार सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। उन्होंने विधायक जी द्वारा विकास कार्यों को प्राथमिकता देने एवं त्वरित पहल करने के लिए आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में शहर के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी इसी प्रकार सकारात्मक कार्रवाई जारी रहेगी।

प्रतिनिधिमंडल द्वारा विशेष रूप से राजा बाजार रेलवे अंडरपास के नीचे लगातार होने वाले जलजमाव एवं आवागमन की समस्या को भी विधायक जी के समक्ष प्रमुखता से रखा गया। इस पर विधायक जी ने आश्वासन दिया कि सरकार के वादे के मुताबिक जब तक रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए पानी निकासी की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए NH एवं RCD के कार्यपालक अभियंताओं को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस पहल से बरसात के दिनों में होने वाली कठिनाइयों में काफी कमी आएगी।

इन सभी विकास कार्यों एवं सकारात्मक पहलों के लिए जहानाबाद डेवलपमेंट कमिटी के अध्यक्ष देवांशु दीपक ने एक प्रतिनिधि मंडल के साथ विधायक श्री राहुल कुमार जी से मुलाकात कर धन्यवाद ज्ञापित किया तथा शहर के अन्य स्थानीय मुद्दों से भी उन्हें अवगत कराया।

इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल में श्री अमित कुमार, पंकज उपाध्याय, रौशन कुमार सहित जहानाबाद डेवलपमेंट कमिटी के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।●

बोधगया दौरे में मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणाएं

● मो० सईद

बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गयाजी और बोधगया का व्यापक दौरा कर धार्मिक आस्था के साथ-साथ विकास की बड़ी योजनाओं की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने गयाजी स्थित विष्णुपद मंदिर, बोधगया के महाबोधि मंदिर और बोधगया मठ में विधिवत पूजा-अर्चना कर राज्य की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने अपने दौरे की शुरुआत गयाजी के विष्णुपद मंदिर से की, जहां उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना की। इसके बाद उन्होंने फल्गू नदी घाट का निरीक्षण किया और मंदिर परिसर में प्रस्तावित विष्णुपद कॉरिडोर को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने स्पष्ट संकेत दिए कि इस कॉरिडोर के निर्माण से धार्मिक पर्यटन को नई दिशा मिलेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इसके पश्चात मुख्यमंत्री बोधगया पहुंचे, जहां उन्होंने महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध की पूजा की और पवित्र बोधि वृक्ष के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने "प्रज्ञा पुस्तक" का लोकार्पण भी किया। इसके बाद बोधगया मठ परिसर में पहुंचकर माता वराही, माता अन्नपूर्णा, शंकराचार्य गद्दी और ठाकुरबाड़ी में स्थापित देवताओं की पूजा-अर्चना की तथा वहां संरक्षित भगवान बुद्ध की प्राचीन मूर्तियों का अवलोकन किया। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री का जगह-जगह भव्य स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने सड़क मार्ग पर उनका अभिनंदन किया और उत्साहपूर्वक नारे लगाए। मुख्यमंत्री ने भी हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन स्वीकार किया। बोधगया मठ परिसर में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी सह सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि गयाजी में विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जबकि बोध गया मठ कॉरिडोर के लिए एक महीने के भीतर कार्य शुरू होगा। इसके अलावा राज्य में 1700 एकड़ में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और 22 हजार एकड़ में "मगध टाउनशिप" विकसित करने की योजना भी सामने रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार को समृद्ध बनाने के लिए बड़े स्तर पर निवेश लाया जाएगा और 20 नवंबर 2026 तक लगभग 5 लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने युवाओं को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ रुपये तक के सरकारी ठेके स्थानीय युवाओं को देने की बात कही। साथ ही यह भी घोषणा की कि राज्य में निर्मित 30 प्रतिशत उत्पादों की खरीद सरकार द्वारा की जाएगी, जिससे स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने गयाजी में विश्वस्तरीय

संग्रहालय (म्यूजियम) के निर्माण की भी घोषणा की, ताकि देश-विदेश से आने वाले पर्यटक भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित हो सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि "भारत तभी विकसित बनेगा जब बिहार समृद्ध होगा और बिहार तब समृद्ध होगा जब यहां के लोग समृद्ध होंगे।" अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने शिक्षा और रोजगार पर विशेष जोर देते हुए कहा कि राज्य में आधुनिक और उच्च गुणवत्ता वाले विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कानून-व्यवस्था को लेकर भी सख्त संदेश देते हुए कहा कि अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और बिहार को भयमुक्त बनाया जाएगा। इस मौके पर गया जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने मुख्यमंत्री को बुद्ध का स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर धार्मिक समन्वय और सांस्कृतिक एकता पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री के इस दौरे को धार्मिक आस्था और विकास के समन्वय के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें एक ओर उन्होंने पूजा-अर्चना कर आध्यात्मिक संदेश दिया, वहीं दूसरी ओर बड़े पैमाने पर विकास योजनाओं का खाका पेश कर बिहार के भविष्य की दिशा स्पष्ट की।●

सड़क हादसे ने उजाड़ा पूरा परिवार

● मो० सईद

आमस थाना क्षेत्र के तेतरिया गांव में हुए भीषण सड़क हादसे के बाद रविवार को अंतिम संस्कार के दौरान पूरा इलाका गम में डूब गया। एक ही परिवार के छह लोगों की मौत ने गांव को झकझोर कर रख दिया है। जब एक साथ चार चिताएं जलीं, तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं और माहौल पूरी तरह शोकाकुल हो गया। हादसे में शिवा भुइया उर्फ अशोक भुइया, उनकी पत्नी, दो बेटियां समेत परिवार के अन्य सदस्यों की मौत हो गई। सबसे मार्मिक पल तब आया जब इकलौते बेटे रंजीत कुमार ने अपने पिता, मां और दो बहनों को मुखाग्नि दी। इस दृश्य ने हर किसी को भावुक कर दिया। बताया जाता है कि शनिवार को पूरा परिवार एक साथ कार से गांव लौट रहा था। इसी दौरान झारखंड के हजारीबाग जिले के दनुआ जंगल के पास एक अनियंत्रित वाहन ने उनकी कार को टक्कर मार दी, जिससे कार खाई में गिर गई। हादसे में मौके पर ही छह लोगों की जान चली गई। घटना के बाद से तेतरिया गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। मृतक अशोक भुइया की मां बुधनी देवी का रो-रोकर बुरा हाल

है। गांव के लोग एक-दूसरे को सांत्वना देते नजर आ रहे हैं। बुजुर्गों का कहना है कि ऐसा हृदयविदारक दृश्य उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। घटना की सूचना मिलते ही शेरघाटी विधायक की पत्नी बबिता देवी गांव पहुंचीं और पीड़ित परिवार से मिलकर सांत्वना दी। उन्होंने सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। प्रशासन भी सक्रिय है और पीड़ित परिवार को सहायता देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों ने दुर्घटना के कारणों की जांच और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की है।●

● **मिथिलेश कुमार**

'बिना चढ़ावा, फाइल नहीं बढ़ेगी' यह वाक्य अब जिले के सरकारी दफ्तरों की पहचान बनता जा रहा है। कभी शिक्षा और ज्ञान की धरती रहा नालंदा आज भ्रष्टाचार के मामलों में सुर्खियों में है। वर्ष 2025 से मई 2026 के बीच निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की लगातार कार्रवाई ने इस सच्चाई को आंकड़ों में बदल दिया है। इन दो वर्षों में 11 बड़े ट्रैप ऑपरेशन में 14 अधिकारी और कर्मचारी रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए। पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व, बिजली और आंगनबाड़ी, शायद ही कोई विभाग बचा हो, जहां "कट कल्चर" ने जड़ न जमा ली हो।

❖ **सबसे बड़ा धक्काः स्वास्थ्य विभाग 'घूस का अड्डा''** :- स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े विभाग में भ्रष्टाचार का सबसे अधिक खुलासा हुआ है। आशा कार्यकर्ता बहाली से लेकर पोषाहार योजना तक, हर स्तर पर "रेट" तय होने के आरोप सामने आए हैं। नगरनौसा और इस्लामपुर में बीसीएम स्तर के अधिकारी तक इस जाल में पकड़े गए।

☞ आशा बहाली के नाम पर 20-30 हजार रुपये की मांग।

☞ पोषाहार पंजी और भुगतान के लिए कमीशन।

☞ योजनाओं के लाभ में हिस्सेदारी।

यह स्थिति उस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है, जिसका उद्देश्य सबसे निचले तबके तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना है।

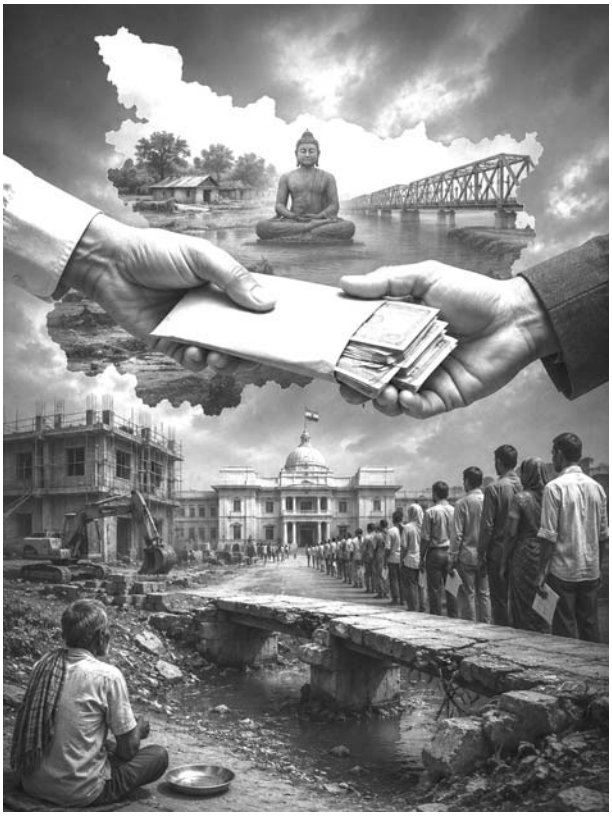

❖ **थाना और अंचलः 'सेटिंग' के बिना कुछ नहीं'** :- 25 अप्रैल 2026 को राजगीर थाना के दारोगा देवकांत कुमार की 90 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तारी ने पूरे सिस्टम को झकझोर दिया।

❖ **राजस्व विभाग में भी हालात कम गंभीर नहीं** :- जमीन से जुड़े हर काम दाखिल-खारिज, नापी, परिमार्जन के लिए "फिक्स रेट" की चर्चा आम है। स्थानीय लोगों का कहना है कि, "बिना दलाल और बिना पैसे के कोई काम समय पर होना अब असंभव हो गया है।"

❖ **शिक्षा और बिजली विभाग भी नहीं बचे** :- चंडी बीआरसी और हिलसा में हुई कार्रवाई ने शिक्षा विभाग की साख को चोट पहुंचाई है। वहीं इस्लामपुर में बिजली विभाग के जेई और कर्मचारी की गिरफ्तारी से यह साफ हो गया कि कनेक्शन से लेकर बिल सुधार तक, हर सेवा की एक "कीमत" तय है।

❖ **हॉटस्पॉट' बना नगरनौसा** :- नगरनौसा प्रखंड में मार्च से मई 2026 के बीच तीन बड़ी ट्रैप कार्रवाई हुई-बीसीएम, बीपीआरओ और महिला पर्यवेक्षिका। सूत्रों की मानें तो यहां "सिस्टमेटिक वसूली" का नेटवर्क काम कर रहा था, जिसमें निचले से ऊपरी स्तर तक हिस्सेदारी तय थी।

❖ **निगरानी तंत्र पर भी उठे सवाल** :- हर साल 70-90 शिकायतें आने के बावजूद कार्रवाई की गति धीमी मानी जा रही है।

☞ कई कार्यालयों में शिकायत नंबर तक प्रदर्शित

नहीं।

☞ लंबित फाइलें आम समस्या।

☞ राजनीतिक संरक्षण के आरोप।

विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रैप कार्रवाई केवल "आइसबर्ग का टिप" है, असली जाल इससे कहीं बड़ा है।

❖ **जमीनी सच्चाई : 'कट' का पूरा गणित:-**

☞ ठेके और योजनाओं में 5% से 15% तक कमीशन।

☞ फाइल क्लियर करने के लिए तय दर।

☞ बिचौलियों का सक्रिय नेटवर्क।

☞ नए कर्मचारियों पर भी "सिस्टम में ढलने" का दबाव।

नालंदा में बढ़ता भ्रष्टाचार केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक चुप्पी का भी परिणाम है। निगरानी की कार्रवाई यह जरूर दिखाती है कि कानून जिंदा है, लेकिन सवाल यह है कि 'क्या केवल गिरफ्तारी से व्यवस्था सुधरेगी, या फिर सिस्टम में गहराई तक बदलाव की जरूरत है?

❖ **प्रमुख ट्रैप कार्रवाई (2025-26) :-**

☞ 25 अप्रैल 2026 :- दारोगा 90 हजार घूस लेते गिरफ्तार।

☞ मार्च 2026 :- नगरनौसा बीसीएम 10 हजार लेते पकड़े गए।

☞ मार्च 2026 :- बीपीआरओ 12 हजार घूस लेते गिरफ्तार।

☞ अगस्त 2025 :- इस्लामपुर बीसीएम 40 हजार लेते गिरफ्तार।

☞ फरवरी 2026 :- राजस्व कर्मचारी 45 हजार घूस लेते पकड़े गए।

☞ नवंबर 2025 :- बिजली विभाग के जेई व कर्मी 20 हजार लेते गिरफ्तार।

☞ मई 2026 :- महिला पर्यवेक्षिका 3200 रुपये लेते रंगे हाथ पकड़ी गई।

बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने नालंदा जिले के नगरनौसा प्रखंड में बड़ी कार्रवाई की है। ब्यूरो की टीम ने आंगनवाड़ी महिला पर्यवेक्षिका (एलएस) सुषमा कुमारी को 3200 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई से प्रखंड कार्यालय में हड़कंप मच गया।

❖ **सरकारी कार्य कराने के बदले में मांगी रिश्वत :-** मामले की शुरुआत नगरनौसा क्षेत्र के कंचन भवन वन, केंद्र संख्या 28 (वार्ड संख्या-3) की सेविका बेबी कुमारी की शिकायत से हुई। उन्होंने निगरानी ब्यूरो को लिखित आवेदन देकर आरोप लगाया था कि पर्यवेक्षिका सुषमा कुमारी पोषाहार पंजी में हस्ताक्षर करने और अन्य जरूरी सरकारी कार्यों को आगे बढ़ाने के बदले रिश्वत की मांग कर रही हैं।

❖ **20 प्रतिशत कमीशन मांगा :-** शिकायत के अनुसार, आरोपित ने कुल 15,747 रुपये की राशि का 20 प्रतिशत हिस्सा कमीशन के रूप में मांगा था। इतना ही नहीं, हर महीने 3200 रुपये अतिरिक्त नजराना देने का भी दबाव बनाया जा रहा था। लगातार हो रही इस मांग से परेशान होकर सेविका ने निगरानी विभाग का दरवाजा खटखटाया।

❖ **सात सदस्यीय टीम गठित की गई :-** शिकायत मिलने के बाद निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने पूरे मामले का गुप्त सत्यापन कराया, जिसमें रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस उपाधीक्षक शशि शेखर चौधरी के नेतृत्व में सात सदस्यीय विशेष टीम गठित की गई। टीम ने योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया और बुधवार को जैसे ही सेविका ने तय रकम सुषमा कुमारी को सौंपी, पहले से तैयार टीम ने उन्हें मौके पर ही दबोच लिया। इस कार्रवाई में पुलिस निरीक्षक विनोद कुमार सहित कई अधिकारी शामिल थे। गिरफ्तारी के बाद टीम ने नगरनौसा स्थित उनके आवासीय परिसर में ही आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की। इसके बाद आरोपी को आगे की पूछताछ और कार्रवाई के लिए पटना ले जाया गया। इस अचानक हुई कार्रवाई से बाल विकास परियोजना कार्यालय (सीडीपीओ) समेत पूरे प्रखंड मुख्यालय में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय स्तर पर इस घटना को लेकर चर्चा का माहौल है और लोग इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देख रहे हैं।●

सूर्य मंदिर निर्माण हेतु भूमि पूजन संपन्न

● **रजनीश कांत झा**

नारदीगंज प्रखंड के आदर्श ग्राम नारदीडीह में सोमवार को भव्य सूर्य मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम धूमधाम से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिले के प्रख्यात शिक्षाविद् एवं समाजसेवी डॉ. अनुज सिंह उपस्थित रहे। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ गांव के पंडित धीरेंद्र पांडेय ने विधिवत पूजा-अर्चना कराई, जबकि मुख्य यजमान के रूप में राजाराम शर्मा शामिल रहे। इस दौरान डॉ. अनुज सिंह ने ईंट रखकर मंदिर निर्माण का शिलान्यास किया और मंदिर निर्माण के लिए तत्काल 51,000 का सहयोग प्रदान किया। साथ ही उन्होंने आगे भी हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र बनेगा, बल्कि क्षेत्र में पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न करेगा। सूर्य उपासना की परंपरा को आगे बढ़ाने में यह मंदिर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ग्रामीणों ने बताया कि मंदिर निर्माण से श्रद्धालुओं को पूजा-अर्चना के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और गांव में सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम में पूर्व प्रमुख गौरीशंकर सिंह, शिक्षक प्रवीण कुमार, पैक्स अध्यक्ष विपिन कुमार, गोपाल कुमार, राजेश कुमार, मनीष कुमार, रोहित कुमार, शैलेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह, अभय कुमार सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। पूरे गांव में इस आयोजन को लेकर उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला और सभी ग्रामीणों ने मंदिर निर्माण में बढ़-चढ़कर सहयोग देने का संकल्प लिया।●

हड्डी विभाग का ओपीडी अनिश्चितकालीन बंद

● रजनीश कांत झा

नवादा सदर अस्पताल में हड्डी विभाग (ऑर्थोपेडिक ओपीडी) को अनिश्चितकालीन अवधि के लिए बंद कर दिया गया है, जिससे हड्डी रोग से पीड़ित मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मरीज अब जनरल ओपीडी में इलाज कराने को मजबूर हैं। मिली जानकारी के अनुसार सदर अस्पताल में आर्थोपेडिक विभाग में डॉ विवेक कुमार राय एवं डॉ संतोष कुमार गौरव पदस्थापित हैं। बताया जा रहा है कि दोनों चिकित्सकों की लापरवाही की शिकायतें लगातार सामने आ रही थीं। सिविल सर्जन द्वारा सख्ती बरतने के बाद दोनों डॉक्टर आवेदन देकर लंबे अवकाश पर चले गए। दोनों चिकित्सकों के अवकाश पर जाने के बाद सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ एसडी अरैय्यर द्वारा हड्डी विभाग के बाहर एक नोटिस चिपकाया गया, जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि हड्डी रोग विशेषज्ञों के लंबे अवकाश पर रहने के कारण हड्डी विभाग का ओपीडी अनिश्चितकालीन के लिए बंद रहेगा। संबंधित मरीज जनरल ओपीडी में ही अपना इलाज कराएं। यह नोटिस 11 मई 2026 को लगाया गया था। तब से लगातार मरीज इलाज के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं रहने के कारण उन्हें या तो वापस लौटना पड़ रहा है या सामान्य ओपीडी में इलाज कराने को मजबूर होना पड़ रहा है।

बताते चलें कि सदर अस्पताल अपनी लचर व्यवस्था को लेकर पहले भी कई बार सुर्खियों में रह चुका है। पूर्व में भी हड्डी विभाग में डॉक्टरों की अनुपस्थिति को लेकर मरीजों द्वारा हंगामा किया जा चुका है। कुछ दिन पहले इसी विभाग में बाहरी व्यक्तियों द्वारा मरीजों का इलाज किए जाने का मामला भी सामने आया था, जिसे मीडिया ने प्रमुखता से उठाया था। बावजूद इसके अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इस संबंध में सिविल सर्जन डॉ विनोद कुमार चौधरी ने बताया कि सदर अस्पताल में आर्थोपेडिक के केवल दो डॉक्टर पदस्थापित हैं और दोनों लंबे अवकाश पर हैं। जिले में अन्य कोई आर्थोपेडिक विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं हैं। फिलहाल मरीजों का इलाज जनरल ओपीडी में किया जा रहा है। समस्या के समाधान के लिए विभाग को पत्र भेजा गया है।●

अभी कलम उठाइये

आपके सामने हो रहे भ्रष्टाचार एवं अपराध की खबर की समीक्षा करें और सरकार सहित पुलिस-प्रशासन तक उसको पहुंचाने के लिए केवल सच पत्रिका के साथ जुड़े। खबर की जानकारी इस नम्बर पर दें

सम्पर्क करें:- 9431073769/8340360961

ई-मेल:- editor.kstimes@rediffmail.com पर भेजें।

करोड़ों की जूट मिल जमीन पर खेल!

● धर्मेन्द्र सिंह

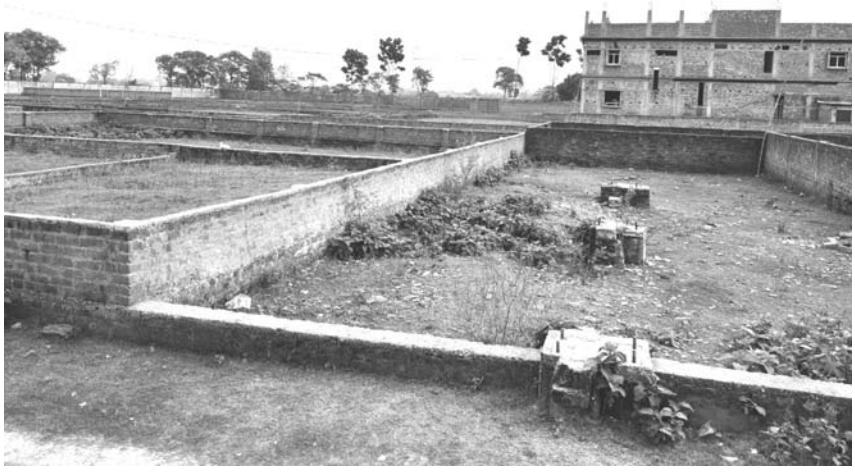

किशनगंज शहर से सटे टेउसा पंचायत के सिमलबाड़ी स्थित बहुमूल्य जूट मिल की जमीन इन दिनों जिले के सबसे चर्चित और संवेदनशील मामलों में शामिल हो चुकी है। करोड़ों रुपये मूल्य की इस औद्योगिक भूमि की कथित अवैध खरीद-बिक्री, फर्जी दाखिल-खारिज, सरकारी संपत्तियों के गायब होने और भू-माफियाओं की सक्रियता ने प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने जांच तेज कर दी है और पूरे प्रकरण की नए सिरे से पड़ताल शुरू हो गई है। प्रारंभिक जांच में यह संकेत मिले हैं कि जूट मिल की जमीन को नियमों को ताक पर रखकर अलग-अलग लोगों के नाम पर बेचा गया। सबसे गंभीर आरोप यह है कि उद्योग विभाग से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लिए बिना ही जमीन की खरीद-बिक्री की गई। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, कई मामलों में दाखिल-खारिज प्रक्रिया भी संदिग्ध परिस्थितियों में पूरी की गई, जिससे पूरे खेल में संगठित नेटवर्क की आशंका गहरा गई है। स्थलीय निरीक्षण के दौरान एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। बताया गया कि जूट मिल परिसर में सरकारी राशि से निर्मित कई भवन अब पूरी तरह गायब हैं। मौके पर केवल कुछ पिलर और ढांचे के अवशेष ही दिखाई दिए, जिससे सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग और बड़े पैमाने पर अनियमितता की आशंका और मजबूत हो गई है। इस बहुचर्चित मामले को लेकर जिला परिषद सदस्य इंजीनियर नासिक नादिर लगातार मुखर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भू-माफियाओं और कुछ जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत से पूरी जमीन को अवैध तरीके से बेच दिया गया। उनका कहना है कि यदि प्रशासन दोषियों पर कार्रवाई नहीं करता है तो जनआंदोलन शुरू किया जाएगा। इसी क्रम में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पूरे मामले में कई अहम खुलासे करने की घोषणा भी की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रमंडलीय आयुक्त पूर्णिया के निर्देश पर स्थलीय जांच कराई गई, जिसमें कई अहम तथ्य सामने आए। जांच में यह बात सामने आई कि जूट मिल अब अस्तित्व में नहीं है और उसकी जमीन विभिन्न खातों और व्यक्तियों के नाम पर दर्ज पाई गई है। कई मामलों में दाखिल-खारिज आवेदन खारिज किए जाने के बावजूद करेक्शन स्लिप जनरेट होने से भी संदेह गहरा गया है। जानकारी के अनुसार, यह पूरा मामला किशनगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत हल्का टेउसा, मौजा सिमलबाड़ी से जुड़ा है। खाता संख्या 104, 126, 22 तथा खेसरा संख्या 889, 890, 891, 894, 900 और 949 से संबंधित जमीन पर कथित रूप से अवैध हस्तांतरण किए जाने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि यह भूमि पूर्व में 'किशनगंज जूट मिल लिमिटेड' के नाम से दर्ज थी।

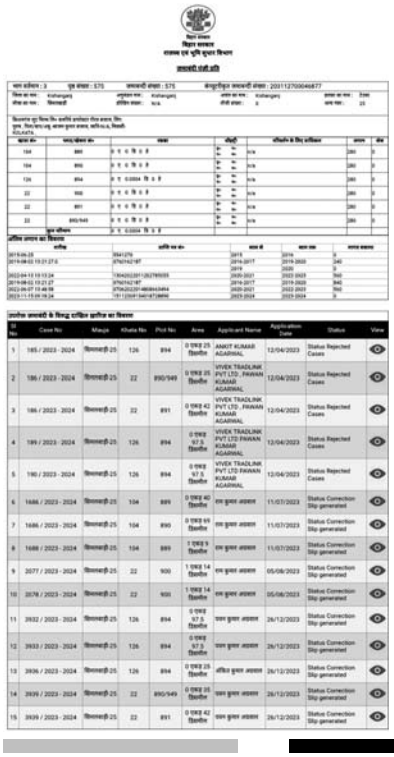

सूत्रों का दावा है कि संबंधित भूमि पर पहले से करोड़ों रुपये का ऋण भी लिया गया था।इसके बावजूद बिना विभागीय अनुमति के जमीन का निजी और व्यावसायिक उपयोग के लिए सौदा कर दिया गया। यदि यह आरोप सही साबित होते हैं तो यह न केवल राजस्व नियमों का उल्लंघन होगा, बल्कि सरकारी एवं औद्योगिक संपत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़ा प्रश्नचिह्न होगा। जिलाधिकारी विशाल राज ने पूरे मामले की पुष्टि करते हुए कहा है कि जांच नए एंगल से की जा रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जमीन से जुड़े सभी दस्तावेजों की बारीकी

Sl No	Case No	Mauja	Khata No	Plot No	Area	Applicant Name	Application Date	Status	View
1	185 / 2023 - 2024	सिमलबाड़ी-25	126	894	0 एकड़ 25 डिसमिल	ANKIT KUMAR AGARWAL	12/04/2023	Status Rejected Cases	
2	186 / 2023 - 2024	सिमलबाड़ी-25	22	890/949	0 एकड़ 25 डिसमिल	VIVEK TRADLINK PVT LTD , PAWAN KUMAR AGARWAL	12/04/2023	Status Rejected Cases	
3	186 / 2023 - 2024	सिमलबाड़ी-25	22	891	0 एकड़ 42 डिसमिल	VIVEK TRADLINK PVT LTD , PAWAN KUMAR AGARWAL	12/04/2023	Status Rejected Cases	
4	189 / 2023 - 2024	सिमलबाड़ी-25	126	894	0 एकड़ 97.5 डिसमिल	VIVEK TRADLINK PVT LTD PAWAN KUMAR AGARWAL	12/04/2023	Status Rejected Cases	
5	190 / 2023 - 2024	सिमलबाड़ी-25	126	894	0 एकड़ 97.5 डिसमिल	VIVEK TRADLINK PVT LTD PAWAN KUMAR AGARWAL	12/04/2023	Status Rejected Cases	
6	1686 / 2023 - 2024	सिमलबाड़ी-25	104	889	0 एकड़ 40 डिसमिल	[illegible]	11/07/2023	Status Correction Slip generated	
7	1686 / 2023 - 2024	सिमलबाड़ी-25	104	890	0 एकड़ 69 डिसमिल	[illegible]	11/07/2023	Status Correction Slip generated	
8	1688 / 2023 - 2024	सिमलबाड़ी-25	104	889	1 एकड़ 9 डिसमिल	[illegible]	11/07/2023	Status Correction Slip generated	
9	2077 / 2023 - 2024	सिमलबाड़ी-25	22	900	1 एकड़ 14 डिसमिल	[illegible]	05/08/2023	Status Correction Slip generated	
10	2078 / 2023 - 2024	सिमलबाड़ी-25	22	900	1 एकड़ 14 डिसमिल	[illegible]	05/08/2023	Status Correction Slip generated	
11	3932 / 2023 - 2024	सिमलबाड़ी-25	126	894	0 एकड़ 97.5 डिसमिल	[illegible]	26/12/2023	Status Correction Slip generated	
12	3933 / 2023 - 2024	सिमलबाड़ी-25	126	894	0 एकड़ 97.5 डिसमिल	[illegible]	26/12/2023	Status Correction Slip generated	
13	3936 / 2023 - 2024	सिमलबाड़ी-25	126	894	0 एकड़ 25 डिसमिल	[illegible]	26/12/2023	Status Correction Slip generated	
14	3939 / 2023 - 2024	सिमलबाड़ी-25	22	890/949	0 एकड़ 25 डिसमिल	[illegible]	26/12/2023	Status Correction Slip generated	
15	3939 / 2023 - 2024	सिमलबाड़ी-25	22	891	0 एकड़ 42 डिसमिल	[illegible]	26/12/2023	Status Correction Slip generated	

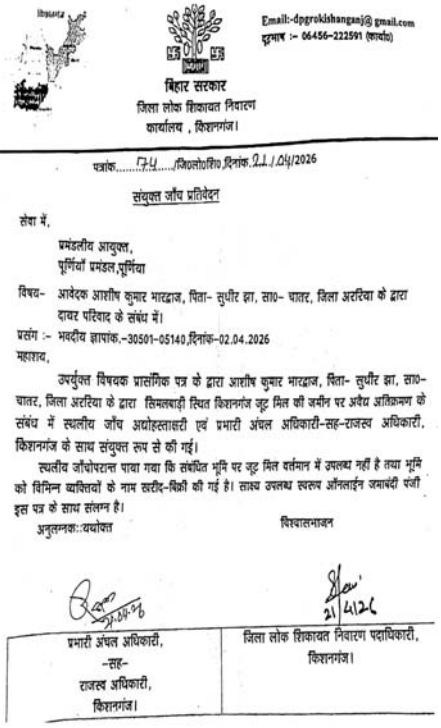

Email:-dpgrokishanganj@gmail.com
दूरभाष :- 06456-222591 (कार्या०)

बिहार सरकार
जिला लोक शिकायत निवारण
कार्यालय , किशनगंज।

पत्रांक......74...../जि०लो०शि० दिनांक 21/04/2026

संयुक्त जाँच प्रतिवेदन

सेवा में,

प्रमंडलीय आयुक्त,
पूर्णियाँ प्रमंडल,पूर्णिया

विषय- आवेदक आशीष कुमार भारद्वाज, पिता- सुधीर झा, सा0- घातर, जिला अररिया के द्वारा दायर परिवाद के संबंध में।

प्रसंग :- भवदीय ज्ञापांक.-30501-05140,दिनांक-02.04.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा आशीष कुमार भारद्वाज, पिता- सुधीर झा, सा0- घातर, जिला अररिया के द्वारा सिमलबाड़ी स्थित किशनगंज जूट मिल की जमीन पर अवैध अतिक्रमण के संबंध में स्थलीय जाँच अधोहस्ताक्षरी एवं प्रभारी अंचल अधिकारी-सह-राजस्व अधिकारी, किशनगंज के साथ संयुक्त रूप से की गई।

स्थलीय जाँचोपरान्त पाया गया कि संबंधित भूमि पर जूट मिल वर्तमान में उपलब्ध नहीं है तथा भूमि को विभिन्न व्यक्तियों के नाम खरीद-बिक्री की गई है। साक्ष्य उपलब्ध स्वरूप ऑनलाईन जमाबंदी पंजी इस पत्र के साथ संलग्न है।

अनुलग्नक::यथोक्त

विश्वासभाजन

प्रभारी अंचल अधिकारी, -सह- राजस्व अधिकारी, किशनगंज।	जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, किशनगंज।

जिला परिषद् क्षेत्र सं0- 10 (कोचाधामन)

जिला परिषद

मोबाइल नं0- 94722087

दिनांक 26-04-2026

सेवा में,

जिला पदाधिकारी महोदय,

किशनगंज।

विषय- जूट मिल की जमीन को भू माफियाओं के द्वारा कब्जा करने एवं खरीद बिक्री करने के संबंध में।

महाशय,

सविनय निवेदन यह है कि किशनगंज थाना अंतर्गत हल्का देउरा राजस्व ग्राम मौजा- सिमलबाड़ी थाना नं0 25 दाखिल खारिज वाद सं0 एवं वर्ष 3939/2023-2024 जिसका खाता नं0 104, 126, 22 खेसरा नं0 889, 890, 894, 900, 891, 890, 949 जिसका जमाबंदी सं0 575 है का अंचलअधिकारी के आदेश के उपरान्त निम्नलिखित भूमि दाखिल खारिज की गई है। तथा किशनगंज जूट मिल लि0 ... बजाज निवासी- कोलकाता के नाम ... जमाबंदी था। जिसमें जमीन माफियाओं एवं पदाधिकारी के मिली भगत से जूट मिल ... संलिप्त है। तथा जमीन विभिन्न ... जमाबंदी पायी गई है। पूर्व में पत्रांक सं0 174 (74) जि0प0कि0 ... 21/4/26 में अंकित है।

अतः श्रीमान् से आग्रह है कि जूट मिल की जमीन की खरीद बिक्री करने वाले व्यक्तियों के प्रोपर्टी का जाँच तथा ... कर जमीन को बेचना तथा पदाधिकारियों के ... दाखिल खारिज करवाना जाँच का विषय है।

प्रतिलिपि :

1. माननीय जिला भू- अर्जन पदाधिकारी, किशनगंज
2. माननीय पुलिस अधीक्षक, किशनगंज।
3. माननीयआयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ
4. माननीय सांसद महोदय, पूर्णियाँ
5. निगरानी विभाग, पटना।
6. आर्थिक अपराध ईकाई, बिहार पटना
7. माननीय राजस्व मंत्री, बिहार सरकार
8. माननीय उद्योग मंत्री, बिहार सरकार
9. माननीय उद्योग मंत्री, भारत सरकार
10. माननीय मुख्य मंत्री, बिहार सरकार
11. माननीय गृहमंत्री, भारत सरकार
12. माननीय प्रधान मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली

को आवश्यक कार्यार्थ समर्पित।

से जांच होगी तथा इसमें शामिल लोगों और अधिकारियों की भूमिका भी खंगाली जाएगी। प्रशासन का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि सिमलबाड़ी स्थित जूट मिल का उद्घाटन वर्ष 2004 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन द्वारा किया गया था। कभी रोजगार और औद्योगिक विकास की उम्मीद मानी जाने वाली यह परियोजना वर्षों से बंद पड़ी है। अब इसकी जमीन पर अवैध कब्जे और खरीद-बिक्री के आरोपों ने पूरे जिले की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हुई तो कई बड़े नाम बेनकाब हो सकते हैं। फिलहाल प्रशासन की सक्रियता से भू-माफियाओं में हड़कंप है और आने वाले दिनों में इस मामले में बड़े खुलासों की संभावना जताई जा रही है।●

पुलिस टीम पर हमला, सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त

● धर्मेन्द्र सिंह

जिले के खगड़ा माछमारा इलाके में फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस टीम पर हमला, सरकारी कार्य में बाधा और सरकारी वाहनों को क्षतिग्रस्त करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना 8 मई की देर रात की बताई जा रही है, जब किशनगंज थाना पुलिस एक पुराने कांड के फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने गई थी। इस दौरान स्थानीय लोगों की भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया, जिसमें महिला पुलिसकर्मियों समेत कई जवान घायल हो गए। पुलिस ने मामले में सात लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 14 नामजद और 40 से 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार किशनगंज थाना के पु.नि. सह अपर थानाध्यक्ष नेसार अहमद के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि किशनगंज थाना कांड संख्या-502/25 के फरार अभियुक्त मुसरफ उर्फ मुसरफ अंसारी और सकील उर्फ सहजादा को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम रात करीब 12:20 बजे थाना से निकली थी। पुलिस टीम में महिला पुलिसकर्मी, पुलिस अवर निरीक्षक, सशस्त्र बल एवं गृहरक्षक जवान शामिल थे। रात करीब 12:45 बजे पुलिस ने खगड़ा माछमारा इलाके से दोनों फरार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस टीम उन्हें माछमारा चौक के पास वाहन में बैठा रही थी, तभी अचानक 60 से 70 स्थानीय ग्रामीणों की

भीड़ वहां पहुंच गई। आरोप है कि भीड़ में शामिल महिला एवं पुरुषों ने पुलिस टीम के साथ गाली-गलौज और धक्का-मुक्की शुरू कर दी।इसके बाद ईंट, पत्थर और लोहे के रॉड से हमला कर दिया गया। इस हमले में महिला पुलिस पदाधिकारी प्रीति कुमारी समेत चार पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं दो सरकारी वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने वरीय अधिकारियों को सूचना दी। इसके बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-1 के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने इलाके में छापेमारी अभियान चलाते हुए सात लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में नसीम, अजीम अंसारी, जमशेद, सज्जाद उर्फ बिट्टू, रमजान, मो. मुन्ना और मौला अली शामिल हैं। पुलिस ने दावा किया है कि पूछताछ के दौरान सभी ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। मामले में पुलिस ने डोमा उर्फ खुरशेद, रोहित, नरगीस, कलुआनी उर्फ बेगम, कलुवा, अरमान, छोटू, नसीम, सहजादी, कैयुम, लाल बानो, निशा, अंजुम और मो. गुड्डू समेत कई अन्य लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है। साथ ही 40-50 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, जानलेवा हमला करने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और अन्य गंभीर धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। घटना के बाद इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। पुलिस की ओर से लगातार छापेमारी की जा रही है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।●

यात्री शेड या कमाई का शेड

● धर्मेन्द्र सिंह

किशनगंज नगर परिषद एक बार फिर सवालों के घेरे में है। इस बार मामला शहर में बनाए गए यात्री शेडों के निर्माण से जुड़ा है, जहां साधारण स्टील और टीन से बने ढांचों पर लगभग 13 लाख 98 हजार 300 रुपये खर्च दिखाए जाने के आरोपों ने प्रशासनिक व्यवस्था और विकास योजनाओं की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिस निर्माण कार्य की वास्तविक लागत मुश्किल से तीन से चार लाख रुपये होनी चाहिए थी, उसे कई गुना बढ़ाकर सरकारी रिकॉर्ड में दर्शाया गया है। अब यह मामला सिर्फ निर्माण कार्य तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि सरकारी राशि के कथित दुरुपयोग और जवाबदेही की परीक्षा बनता जा रहा है। शहर के अलग-अलग हिस्सों में बनाए गए इन यात्री शेडों को देखने के बाद आम लोगों के बीच चर्चा तेज हो गई है। लोगों का कहना है कि साधारण लोहे के पाइप, एंगल और टीन से बने छोटे ढांचे पर करीब 14 लाख रुपये खर्च होना समझ से परे है। कई स्थानीय नागरिक इसे "विकास के नाम पर खेल" बता रहे हैं। आम चर्चा यह भी है कि यदि इतनी राशि वास्तव में खर्च हुई होती तो निर्माण की गुणवत्ता और डिजाइन कहीं अधिक बेहतर दिखाई देती। मामले ने तब और तूल पकड़ा जब शिकायतकर्ता सैयद आबिद हुसैन उर्फ फूल बाबू ने नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव, आयुक्त और जिलाधिकारी को लिखित शिकायत भेजी। शिकायत के साथ सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त दस्तावेज भी संलग्न किए गए, जिनमें निविदा प्रक्रिया, स्वीकृति, भुगतान और लागत निर्धारण में कथित विसंगतियों का उल्लेख किया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि कई स्थानों पर बिना आवश्यकता और उपयोगिता का सही आकलन किए ही निर्माण कार्य करा दिए गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब दो लाख रुपये में गरीब परिवारों के लिए पक्का मकान तैयार हो जाता है, जबकि यहां कुछ और स्टील के यात्री शेडों पर लगभग 14 लाख रुपये खर्च दिखाया जाना जनता के पैसे के साथ मजाक जैसा प्रतीत होता है। लोगों के बीच यह सवाल लगातार उठ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी राशि कहां खर्च हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने जांच के आदेश तो दिए, लेकिन जांच प्रक्रिया की धीमी रफ्तार ने लोगों के संदेह को और बढ़ा दिया है। प्रारंभ में जांच के लिए दो सदस्यीय टीम गठित की गई थी, जिसमें सहायक कोषागार पदाधिकारी नौशाद आलम और स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण विभाग के सहायक अभियंता को शामिल किया गया था। बाद में टीम में बदलाव करते हुए एडीएम इरफान और ग्रामीण कार्य विभाग प्रमंडल-वन के कार्यपालक अभियंता को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। हालांकि टीम बदले जाने के बाद भी एक माह से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अब तक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। रिपोर्ट को लेकर बनी चुप्पी अब नगर परिषद की कार्यशैली पर और बड़े सवाल खड़े कर रही है। शिकायतकर्ता आबिद का कहना है कि प्रशासन ने उनसे शपथपत्र की मांग की थी, जिसे उन्होंने उपलब्ध करा दिया। इसके बावजूद अब तक कार्रवाई या जांच की स्थिति को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। इससे लोगों में यह धारणा मजबूत हो रही है कि कहीं न कहीं मामले को दबाने की कोशिश हो रही है। दूसरी ओर नगर परिषद के कार्यपालक अभियंता प्रवीण कुमार ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि निर्माण कार्य पूरी तरह नियमों के तहत कराया गया है और किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई है। वहीं जांच टीम का नेतृत्व कर रहे एडीएम इरफान के अनुसार जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंप दी गई है। लेकिन रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होने से मामला और अधिक रहस्यमय बनता जा रहा है। नगर परिषद की कार्यप्रणाली को लेकर यह पहला विवाद नहीं है। इससे पहले भी विभिन्न विकास योजनाओं में गुणवत्ता, लागत और पारदर्शिता को लेकर सवाल उठते रहे हैं। लेकिन इस बार मामला सीधे जनता की नजर में दिखाई देने वाले निर्माण कार्य से जुड़ा है, इसलिए लोगों की प्रतिक्रिया भी तीखी है। नागरिकों का कहना है

कि यदि छोटी-छोटी परियोजनाओं में इस तरह खर्च बढ़ाकर दिखाया जाएगा तो विकास योजनाओं का वास्तविक उद्देश्य प्रभावित होगा और सरकारी धन का दुरुपयोग बढ़ता जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी सार्वजनिक निर्माण कार्य में लागत निर्धारण, तकनीकी स्वीकृति और भुगतान प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए। यदि निर्माण की वास्तविक लागत और भुगतान में बड़ा अंतर पाया जाता है तो यह वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आ सकता है। ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच और समयबद्ध कार्रवाई बेहद जरूरी होती है ताकि जनता का विश्वास बना रहे। फिलहाल पूरा मामला जांच रिपोर्ट पर आकर टिक गया है। अब लोगों की नजर जिलाधिकारी स्तर पर होने वाली अगली कार्रवाई पर है। यदि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हुई तो यह मामला नगर परिषद में व्याप्त संभावित अनियमितताओं की परतें खोल सकता है। वहीं यदि रिपोर्ट को दबाने या मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश हुई तो जनता का अविश्वास और गहरा सकता है। यात्री शेड निर्माण से शुरू हुआ यह विवाद अब सरकारी योजनाओं में जवाबदेही, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के खिलाफ जनचर्चा का बड़ा मुद्दा बन चुका है। आने वाले दिनों में प्रशासन की कार्रवाई यह तय करेगी कि यह मामला सिर्फ आरोपों तक सीमित रहेगा या फिर किसी बड़े खुलासे का कारण बनेगा।●

अपराध गोष्ठी में एसपी ने दिए सख्त निर्देश

● धर्मेन्द्र सिंह

जिले में अपराध नियंत्रण, नशा तस्करी पर रोक और कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से आयोजित मासिक अपराध गोष्ठी इस बार कई अहम निर्णयों और सख्त निर्देशों के कारण चर्चा में रही। 10 मई की देर रात पुलिस सभागार में आयोजित पुलिस सभा एवं अपराध गोष्ठी की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने की, जिसमें जिले के सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अंचल पुलिस निरीक्षक, थानाध्यक्ष एवं विभिन्न शाखाओं के प्रभारी शामिल हुए। बैठक में अपराध अनुसंधान की गुणवत्ता, लंबित मामलों के निष्पादन, सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा और आगामी बकरीद पर्व को लेकर विशेष रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान सबसे महत्वपूर्ण घोषणा जिले में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) के गठन को लेकर हुई। एसपी संतोष कुमार ने कहा कि किशनगंज की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण बेहद जरूरी है। इसके लिए विशेष टीम गठित कर नशा तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाएगा। सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में संवेदनशील स्थानों की पहचान करें और नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। एसपी ने साफ कहा कि नशा केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं, बल्कि सामाजिक और युवा पीढ़ी के भविष्य से जुड़ा गंभीर खतरा है। इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षण संस्थानों में "ड्रग्स फ्री कैंपस" अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर छात्रों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया जाएगा। साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जनभागीदारी के माध्यम से नशा मुक्ति अभियान चलाने की रणनीति तैयार की गई है। बैठक में इंडो-नेपाल सीमा से जुड़े अपराधों पर भी गंभीर चिंता जताई

गई। एसपी ने सीमावर्ती थानों को फर्जी आधार कार्ड, फर्जी प्रमाण पत्र और फर्जी कंपनियों के नाम पर ठगी करने वाले गिरोहों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्र में सक्रिय साइबर और दस्तावेज आधारित अपराधियों पर तकनीकी निगरानी बढ़ाई जाएगी। यातायात व्यवस्था को लेकर भी सख्ती दिखाई गई। यातायात थाना को निजी वाहनों पर अवैध रूप से "पुलिस" और "प्रेस" लिखकर चलने वालों के खिलाफ अभियान चलाने तथा बिना हेलमेट वाहन चालकों पर कार्रवाई तेज करने का निर्देश दिया गया। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि इस तरह की अवैध गतिविधियां आम लोगों में भ्रम और कानून के दुरुपयोग की स्थिति पैदा करती हैं। महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर भी गोष्ठी में विशेष चर्चा हुई। महिला थाना को "पुलिस दीदी योजना" के तहत छात्राओं और कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष कार्य योजना तैयार करने को कहा गया। वहीं मानव तस्करी रोकने के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) को पुनर्गठित कर सक्रिय कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। साइबर थाना को साइबर अपराध से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई और लंबित कांडों के शीघ्र निष्पादन पर जोर देने को कहा गया। आगामी बकरीद पर्व को लेकर एसपी संतोष कुमार ने सभी पुलिस पदाधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने, सांप्रदायिक मामलों पर कड़ी निगरानी रखने और निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि त्योहार के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। गोष्ठी के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस पदाधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। बिजली तार चोरी मामले के सफल उद्भेदन के लिए पहाड़कट्टा थानाध्यक्ष फुलेन्दर कुमार तथा बेहतर कांड निष्पादन के लिए दिघलबैंक थानाध्यक्ष विपिन कुमार को पुरस्कृत किया गया। वहीं कोचाधामन, पाठामारी और विशनपुर थानाध्यक्षों के कार्य को असंतोषजनक पाते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया। पुलिस की इस व्यापक रणनीति और सख्त रुख से यह स्पष्ट संकेत मिला है कि आने वाले दिनों में जिले में अपराध और अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान और तेज होने वाला है।●

पोक्सो मामले में दोषी को 20 वर्ष की सजा

● धर्मेन्द्र सिंह

किशनगंज में पोक्सो अधिनियम के तहत दर्ज एक गंभीर मामले में अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी को कठोर सजा दी है। अनन्य विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम दीप चंद पाण्डेय की अदालत ने 11 मई को नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए आरोपी नूर आलम को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर 71 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अर्थदंड की राशि पीड़िता को दी जाएगी। यदि आरोपी अर्थदंड की राशि जमा नहीं करता है तो उसे अतिरिक्त छह माह की सजा भुगतनी होगी। यह मामला दिघलबैंक प्रखंड अंतर्गत सुल्तानगंज गांव से जुड़ा है, जहां दो वर्ष पूर्व नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई थी। घटना के बाद पीड़िता के परिजनों द्वारा दिघलबैंक थाना में कांड संख्या 79/24 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। बाद में मामला पोक्सो वाद संख्या 51/24 के रूप में विशेष अदालत में विचाराधीन रहा। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में कई महत्वपूर्ण साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। विशेष लोक अभियोजक मनीष कुमार साह ने अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी करते हुए घटना की गंभीरता को रेखांकित किया। उन्होंने अदालत के समक्ष यह दलील रखी कि नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले अपराध समाज के लिए अत्यंत गंभीर चुनौती हैं और ऐसे

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में ऐतिहासिक फैसला

किशनगंज व्यवहार न्यायालय से 13 मई को आया एक महत्वपूर्ण फैसला न केवल न्याय व्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है, बल्कि महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराध करने वालों के लिए कड़ा संदेश भी माना जा रहा है। अनन्य विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम दीप चंद पाण्डेय की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी शमशेर आलम उर्फ शम्स आलम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर एक लाख 75 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसकी राशि पीड़िता को दी जाएगी। बहादुरगंज थाना क्षेत्र के भाटाबाड़ी निवासी आरोपी के खिलाफ वर्ष 2023 में पोक्सो अधिनियम एवं अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया गया था। बहादुरगंज थाना कांड संख्या 120/23 एवं पोक्सो वाद संख्या 21/23 के तहत दर्ज इस मामले में नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया गया था।प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच करते हुए आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र समर्पित किया था। मामले की सुनवाई पिछले कई महीनों से अनन्य विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम की अदालत में चल रही थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पीड़िता, गवाहों तथा अनुसंधान से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य अदालत में प्रस्तुत किए। विशेष लोक अभियोजक मनीष कुमार साह ने अदालत में प्रभावी ढंग से पक्ष रखते हुए दोषी के खिलाफ कड़ी सजा की मांग की।अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी को पोक्सो अधिनियम के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अन्य धाराओं में भी सश्रम कारावास का आदेश दिया गया। न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि अर्थदंड की राशि पीड़िता को उपलब्ध कराई जाएगी। यदि दोषी अर्थदंड जमा नहीं करता है, तो उसे अतिरिक्त छह माह की सजा भुगतनी होगी। इस मामले में अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत पांच लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाए। इसे पीड़िता के पुनर्वास और मानसिक-सामाजिक सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कानूनी जानकारों का मानना है कि पोक्सो मामलों में त्वरित सुनवाई और कठोर सजा समाज में सकारात्मक संदेश देती है। इस फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराध करने वालों को कानून किसी भी सूरत में बख्शने वाला नहीं है। फैसले के बाद न्यायालय परिसर में मौजूद लोगों ने कहा कि इस तरह के मामलों में समयबद्ध न्याय से आम लोगों का न्यायपालिका पर विश्वास मजबूत होता है। साथ ही यह फैसला उन पीड़ित परिवारों के लिए भी उम्मीद की किरण है, जो न्याय की आस में वर्षों तक संघर्ष करते हैं।

मामलों में कठोर सजा आवश्यक है ताकि समाज में स्पष्ट संदेश जा सके। अभियोजन पक्ष की दलीलों और उपलब्ध साक्ष्यों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए कठोर दंड सुनाया। अदालत के फैसले के बाद न्यायालय परिसर में मौजूद लोगों के बीच इस निर्णय को लेकर चर्चा होती रही। कई लोगों ने इसे पीड़ित पक्ष के लिए न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। जानकारों का कहना है कि पोक्सो अधिनियम के तहत मामलों की त्वरित सुनवाई और दोषियों को कठोर सजा दिए जाने से बच्चों के खिलाफ अपराध पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है। गौरतलब है कि पोक्सो अधि नियम यानी 'प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट' बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया विशेष कानून है। इस कानून के तहत नाबालिगों के साथ दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न और अन्य अपराधों के मामलों में सख्त सजा का प्रावधान है। हाल के वर्षों में ऐसे मामलों में अदालतों द्वारा त्वरित सुनवाई और दोषियों को कठोर दंड दिए जाने के कई उदाहरण सामने आए हैं। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के मामलों में अदालतों का सख्त रुख समाज में अपराधियों के मन में कानून का भय पैदा करता है। साथ ही यह पीड़ित परिवारों को यह भरोसा भी देता है कि न्याय व्यवस्था उनके साथ खड़ी है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पोक्सो मामलों में न्यायिक प्रक्रिया को लेकर लोगों के बीच जागरूकता बढ़ी है और अब पीड़ित परिवार खुलकर कानूनी सहायता लेने लगे हैं। इस मामले में अदालत द्वारा पीड़िता को अर्थदंड की राशि देने का निर्देश भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे पीड़ित पक्ष को आर्थिक और मानसिक रूप से कुछ राहत मिलती है। हालांकि ऐसे मामलों में सामाजिक और मानसिक प्रभाव लंबे समय तक बने रहते हैं, इसलिए पीड़ित बच्चों के पुनर्वास और काउंसलिंग की आवश्यकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिलहाल अदालत के फैसले के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं अभियोजन पक्ष ने इसे न्याय की जीत बताते हुए कहा कि अदालत के इस फैसले से समाज में सकारात्मक संदेश जाएगा और बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों को कड़ी चेतावनी मिलेगी।●

19 मई से शुरू होगा 'सहयोग शिविर' अभियान

● धर्मेन्द्र सिंह

राज्य सरकार ने आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान और सरकारी सेवाओं को पंचायत स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने की दिशा में एक बड़ी पहल करते हुए "सहयोग शिविर" अभियान शुरू करने की घोषणा की है। सात निश्चय-3 के अंतर्गत "सबका सम्मान-जीवन आसान (Ease of Living)" कार्यक्रम को धरातल पर उतारने के उद्देश्य से यह अभियान आगामी 19 मई 2026 से पूरे बिहार में शुरू होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 11 मई को पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर इस अभियान के सफल संचालन को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाले सहयोग शिविरों का उद्देश्य आम नागरिकों को छोटी-छोटी समस्याओं के समाधान के लिए जिला मुख्यालय का चक्कर लगाने से राहत दिलाना है। उन्होंने कहा कि अब पंचायत का कार्य पंचायत स्तर पर ही निष्पादित किया जाएगा, ताकि आमजन को सरकारी सेवाएं सरल और सुलभ तरीके से उपलब्ध हो सकें। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को पंचायतों में "सहयोग शिविर" लगाए जाएंगे और शिविर में प्राप्त प्रत्येक आवेदन का निष्पादन 30 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी भी स्तर पर आवेदन अनावश्यक रूप से लंबित रखा जाता है तो 31वें दिन संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि सभी आवेदनों की रियल टाइम मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) द्वारा की जाएगी। साथ ही जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को कम-से-कम पांच पंचायतों का औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है, ताकि शिविरों की पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने "सहयोग पोर्टल" एवं हेल्पलाइन नंबर 1100 का भी लोकार्पण किया। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि शिविरों में प्राप्त शिकायतों एवं आवेदनों की जानकारी नियमित रूप से पोर्टल पर अपडेट की जाए। इसके साथ ही शिविर स्थल पर आमजनों के लिए बैठने, पेयजल एवं अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद जिलाधिकारी विशाल राज ने जिले के सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर अभियान की तैयारी की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक करीब 550 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। प्रखंड स्तर पर पोर्टल संचालन एवं आवेदन अपलोडिंग के लिए कर्मियों को प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। जिलाधिकारी ने जिला, प्रखंड, अंचल, पंचायत एवं थाना स्तर पर सहयोग शिविर गठन कर पंचायतवार रोस्टर तैयार करने का निर्देश दिया। बैठक में पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार, डीडीसी प्रदीप कुमार, एडीएम अमरेन्द्र कुमार पंकज, जिला पंचायत राज पदाधिकारी जफर आलम, जिला योजना पदाधि कारी सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी कुंदन कुमार सिंह सहित कई जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। प्रशासन का दावा है कि यह अभियान आमजनों को सरकारी सेवाओं से जोड़ने और प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में अहम कदम साबित होगा।●

खेल-खेल में शुरू हुआ विवाद बना मासूम की मौत की वजह

● धर्मेन्द्र सिंह

दिघलबैंक प्रखंड के कोढ़ोबारी थाना क्षेत्र स्थित दुर्गापुर गांव में आठ वर्षीय मासूम बच्ची की हत्या का मामला पूरे जिले को झकझोर देने वाला साबित हुआ। जिस घटना ने शुरुआत में अपहरण, हत्या और बड़े आपराधिक षड्यंत्र की आशंका पैदा कर दी थी, उसका खुलासा महज 48 घंटे के भीतर पुलिस ने कर दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि मासूम की हत्या किसी बाहरी अपराधी ने नहीं, बल्कि उसकी अपनी चाची यानी बड़ी मां ने ही की थी। पुलिस जांच में सामने आई सच्चाई ने न केवल परिजनों बल्कि पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। मृतका की पहचान दुर्गापुर गांव निवासी मो. शकील की आठ वर्षीय पुत्री सेली परवीन उर्फ शहरानी के रूप में हुई। वह गांव के सरकारी विद्यालय में दूसरी कक्षा की छात्रा थी। बताया गया कि 30 अप्रैल की सुबह करीब 11 बजे वह घर से खेलने के लिए निकली थी, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटी। परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलने पर पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद पुलिस और ग्रामीण लगातार बच्ची की खोजबीन में जुटे रहे। दो दिन बाद, 02 मई की सुबह गांव की एक बच्ची जब मक्के के खेत की ओर गई तो वहां जाल में लिपटा शव देखकर चीख पड़ी। सूचना फैलते ही गांव में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे परिजनों ने शव की पहचान सेली परवीन के रूप में की। शव की स्थिति देखकर हत्या की आशंका और गहरा गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि बच्ची का दाहिना हाथ टूटा हुआ था, जिससे घटना को लेकर लोगों में आक्रोश फैल गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए कोढ़ोबारी थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की समीक्षा की। एफएसएल एवं डॉग स्क्वॉड

टीम को भी जांच में लगाया गया। वहीं मामले के त्वरित उद्भेदन के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-2 मंगलेश कुमार सिंह के नेतृत्व में विशेष अनुसंधान दल (SIT) का गठन किया गया। शुरुआत में मामला पूरी तरह रहस्यमय बना हुआ था। परिवार और ग्रामीणों को किसी बाहरी अपराधी पर शक था। लेकिन पुलिस की तकनीकी एवं मानवीय जांच धीरे-धीरे परिवार के भीतर की ओर बढ़ने लगी। जांच के दौरान मृतका की चाची हैरून निशा का व्यवहार संदिग्ध पाया गया। पुलिस के अनुसार वह पूछताछ के दौरान बार-बार बयान बदल रही थी और घटना को लेकर भ्रमित करने की कोशिश कर रही थी। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो पूरा मामला सामने आ गया। आरोपी चाची ने स्वीकार किया कि घटना वाले दिन उसका बेटा और सेली परवीन आपस में झगड़ रहे थे। इसी दौरान गुस्से में उसने बच्ची को थप्पड़ मारकर धक्का दे दिया, जिससे वह गिरकर बेहोश हो गई। आरोपी के अनुसार, उसे लगा कि बच्ची की मौत हो चुकी है और पकड़े जाने के डर से उसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने शव को घर में ही छिपाकर रखा और अंधेरा होने पर मच्छरदानी के कपड़े से उसका मुंह ढंककर मकई के खेत में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर खून से सने कपड़े, मच्छरदानी का टुकड़ा तथा घटनास्थल से टूटा हुआ चप्पल बरामद

किया है। एफएसएल टीम ने विभिन्न स्थानों से वैज्ञानिक साक्ष्य भी जुटाए हैं। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि मामले में वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी विश्लेषण और लगातार पूछताछ के आधार पर पुलिस को सफलता मिली। उन्होंने कहा कि आरोपी परिवार की सदस्य होने के कारण जांच को भटकाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस ने तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले का खुलासा कर दिया। इस घटना ने पूरे इलाके को गहरे सदमे में डाल दिया है। गांव में अब भी मातम पसरा हुआ है। मृतका के पिता मो. शकील, जो दिल्ली में मजदूरी करते हैं, घटना की सूचना मिलते ही गांव पहुंचे। परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि परिवार के भीतर ही इतनी दर्दनाक घटना घट सकती है। पुलिस फिलहाल मामले के अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। वहीं मासूम बच्ची की हत्या ने एक बार फिर पारिवारिक तनाव, गुस्से और हिंसा के भयावह परिणामों को सामने ला दिया है।●

संगठित अपराध के खिलाफ विशेष अभियान

● धर्मेन्द्र सिंह

सीमावर्ती जिला किशनगंज में अवैध कारोबार, रंगदारी और संगठित अपराध के खिलाफ पुलिस ने अब निर्णायक लड़ाई छेड़ दी है। जिले में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों और विभिन्न माफिया गिरोहों की सक्रियता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने व्यापक स्तर पर विशेष अभियान शुरू किया है। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने साफ शब्दों में कहा है कि जिले में किसी भी प्रकार की अवैध वसूली, रंगदारी, दलाली या संगठित अपराध को अब किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपराध में शामिल लोगों की पहचान कर लगातार कानूनी कार्रवाई की जा रही है और आने वाले दिनों में अभियान को और तेज किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय से लेकर थाना स्तर तक चल रही इस सख्ती का असर अब जिले में साफ दिखाई देने लगा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, कई ऐसे गिरोह चिन्हित किए गए हैं जो लंबे समय से अवैध वसूली, प्रवेश शुल्क, तस्करी और अवैध कारोबार से जुड़े नेटवर्क को संचालित कर रहे थे। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि विशेष रूप से प्रवेश माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। इसके अलावा मवेशी तस्करी, शराब कारोबार, कोयला, गिट्टी और बालू माफिया सहित विभिन्न अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों पर भी पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। एसपी ने कहा कि सीमावर्ती इलाका होने के कारण किशनगंज में कई तरह के अवैध कारोबार पनपने की कोशिश करते हैं। ऐसे तत्वों के खिलाफ अब खुफिया तंत्र को और मजबूत किया गया है। पुलिस विभिन्न स्तरों पर सूचनाएं एकत्र कर रही है और तकनीकी निगरानी के माध्यम से संगठित अपराध से जुड़े लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि कई मामलों में पुलिस को महत्वपूर्ण सूचनाएं मिली हैं, जिनके आधार पर छापेमारी और गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने स्पष्ट कहा कि कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना और आम लोगों में सुरक्षा का भरोसा कायम करना पुलिस प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ केवल औपचारिक कार्रवाई नहीं, बल्कि साक्ष्य आधारित मजबूत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा रही है ताकि दोषियों को अदालत से सजा दिलाई जा सके। पुलिस लगातार गश्ती, छापेमारी और निगरानी अभियान चला रही है, जिससे आपराधिक तत्वों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है।

एसपी ने आम लोगों से भी पुलिस को सहयोग देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यदि किसी को कहीं भी अवैध वसूली, दलाली, रंगदारी, तस्करी या माफिया गतिविधियों की जानकारी मिलती है तो तत्काल पुलिस को सूचित करें। सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि अपराध पर प्रभावी नियंत्रण तभी संभव है जब पुलिस और समाज मिलकर काम करें। जिले के सभी थाना प्रभारियों को विशेष रूप से सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। थाना स्तर पर नियमित निगरानी, सूचना संकलन और क्षेत्र भ्रमण बढ़ाने को कहा गया है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि अपराधियों के खिलाफ लगातार दबाव बनाए रखना ही कानून व्यवस्था को मजबूत करने का सबसे प्रभावी तरीका है। इधर, पुलिस की इस सख्ती का असर अवैध कारोबार से जुड़े लोगों पर भी दिखाई देने लगा है। सूत्रों के अनुसार, कई संदिग्ध गतिविधियों में अचानक कमी आई है और कुछ लोग भूमिगत हो गए हैं। जिले में यह चर्चा भी तेज है कि पुलिस आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर और कार्रवाई कर सकती है।गौर करे कि किशनगंज जैसे सीमावर्ती जिले में संगठित अपराध पर नियंत्रण हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। लेकिन हाल के दिनों में पुलिस द्वारा अपनाई गई आक्रामक रणनीति ने यह संकेत दिया है कि प्रशासन अब अपराध और अवैध नेटवर्क के खिलाफ किसी भी प्रकार की नरमी बरतने के मूड में नहीं है। आम लोगों को भी उम्मीद है कि यदि यह अभियान इसी तरह जारी रहा तो जिले में कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा।●

भवन निर्माण विभाग में फिर उठा 'टेंडर मैनेज' का मामला

काम पूरा होने के बाद निकाली गई निविदा से बढ़े सवाल

● धर्मेन्द्र सिंह

जिले के भवन निर्माण विभाग में टेंडर प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।अल्पकालीन निविदा संख्या-03/2026-27 को लेकर उठे विवाद ने विभागीय कार्यप्रणाली, पारदर्शिता और सरकारी निर्माण कार्यों की निगरानी व्यवस्था पर नई बहस छेड़ दी है। आरोप है कि विभाग ने पहले निर्माण कार्य पूरा कराया और बाद में उसे वैध रूप देने के लिए निविदा जारी की। मामले ने प्रशासनिक हलकों से लेकर स्थानीय संवेदकों और जनप्रतिनिधियों के बीच हलचल तेज कर दी है। जानकारी के अनुसार 7 मई को भवन निर्माण विभाग द्वारा जारी अल्पकालीन निविदा में कुल पांच कार्य शामिल किए गए हैं। इनमें से तीन कार्यों को लेकर दावा किया जा रहा है कि संबंधित निर्माण पहले ही करीब चार महीने पूर्व पूरा कराया जा चुका था। अब उन्हीं कार्यों के लिए बाद में टेंडर प्रकाशित किए जाने पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय स्तर पर यह चर्चा तेज है कि विभागीय अधिकारियों और कुछ चुनिंदा संवेदकों की मिलीभगत से पहले काम कराया गया और अब कागजी प्रक्रिया पूरी कर भुगतान का रास्ता तैयार किया जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार जिन कार्यों को लेकर विवाद सामने आया है, उन्हें विभाग के एक करीबी संवेदक द्वारा पहले ही पूरा कर लिया गया था। आरोप है कि बाद में टेंडर निकालकर पूरी प्रक्रिया को वैधानिक रूप देने का प्रयास किया गया। यदि यह आरोप सही

बिहार सरकार

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल किशनगंज

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना–03/2026–27

1. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता :– कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल किशनगंज
2. परिमाण विपत्र बिक्री तिथि एवं समय :– दिनांक–को–06.05.2026 को 3:00 बजे अपराह्न तक।
3. निविदा जमा करने की तिथि एवं समय :– दिनांक–को–07.05.2026 को 3:00 बजे अपराह्न तक।
4. निविदा खोलने की तिथि एवं समय :– दिनांक–को–07.05.2026 को 3:30 बजे अपराह्न।
5. परिमाण विपत्र बिक्री एवं खोलने का स्थान :– (क) कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल किशनगंज। (ख) अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, पूर्णियाँ। (ग) सहायक अभियंता, भवन अवर प्रमण्डल, किशनगंज/बहादुरगंज एवं ठाकुरगंज।
6. निविदा प्राप्ति का स्थान :–क्रमांक 5 के अनुसार।
7. कार्य की विवरणी (योजना/शीर्ष/मद का नाम):

क्र0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि	अग्रधन की राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य	कार्य समाप्ति की अवधि
01	Construction of Boundary wall in Mahila Perisoner in Mandal Kara, Kishanganj for the year 2026-2027	1030200.00	21000.00	2500.00	02 माह
02	Provision of Grill in Passage of First floor in different ward in Mandal Kara district Kishanganj for the year 2026-2027	643000.00	13000.00	1250.00	01 माह
03	व्यवहार न्यायालय किशनगंज परिसर के प्रधान न्यायाधीश, ए0सी0जे0एम0–01, 02 एवं 03, एस0डी0जे0एम0, मुंशीफ–01 एवं 02, न्यायिक दण्डाधिकारी–01 (03 अदद) एवं 02 के चेम्बर तथा परिवार न्यायालय एवं अन्य भवनों में एल्युमिनियम स्लाईडिंग दरवाजा एवं खिड़की अधिष्ठापन कार्य।	1311206.00	26500.00	2500.00	01 माह
04	व्यवहार न्यायालय किशनगंज के परिसर विकास कार्य।	469300.00	9500.00	750.00	01 माह
05	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, किशनगंज के डुमरिया स्थित आवास के परिसर विकास कार्य।	1490800.00	30000.00	2500.00	02 माह

निविदा की विस्तृत जानकारी state.bihar.gov.in/prdbihar से प्राप्त की जा सकती है।

कार्यपालक अभियंता
भवन प्रमण्डल किशनगंज

PR- 001538 (BCD) 2026-27

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार।

साबित होते हैं तो यह न केवल सरकारी नियमों का उल्लंघन माना जाएगा, बल्कि वित्तीय अनियमितता और कमीशनखोरी जैसे गंभीर सवाल भी खड़े करेगा। मामले को लेकर स्थानीय संवेदकों और आम लोगों में भी नाराजगी है। उनका कहना है कि यदि कार्य पहले ही पूरा हो चुका था तो बाद में निविदा जारी करने का औचित्य क्या है। कई छोटे ठेकेदारों ने आरोप लगाया कि विभागीय स्तर पर लंबे समय से "टेंडर मैनेज" का खेल चल रहा है, जिसमें कुछ खास संवेदकों को लाभ पहुंचाया जाता है। इससे निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा खत्म हो रही है और योग्य छोटे संवेदकों को काम मिलने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। इस पूरे मामले को और गंभीर इसलिए माना जा रहा है क्योंकि जिलाधिकारी द्वारा पूर्व में सभी विभागों को टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने तथा नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। इसके बावजूद भवन निर्माण विभाग पर लगातार अनियमितता के आरोप लगना प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल

खड़े कर रहा है। जानकारों का मानना है कि यदि पूरे मामले की तकनीकी एवं वित्तीय जांच कराई जाए तो कई बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। इधर, जिला परिषद सदस्य ई. नासिक नादिर ने भी मामले को लेकर खुलकर विभाग पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि विभागीय पदाधिकारी अपने चहेते संवेदकों से पहले ही कार्य करवा लेते हैं और बाद में औपचारिकता निभाने के लिए टेंडर जारी किया जाता है। उन्होंने कहा कि यह पूरी प्रक्रिया सरकारी राशि की निकासी और कमीशनखोरी का माध्यम बन चुकी है। नासिक नादिर ने कहा कि इससे सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता समाप्त हो रही है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने जिलाधिकारी से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने तथा दोषी अधिकारियों और संवेदकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो जनहित में आंदोलन शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं में अनियमितता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हालांकि भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता पंकज कुमार ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि टेंडर प्रक्रिया पूरी तरह नियमानुसार की गई है और विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती गई है। बावजूद इसके, पूरे मामले ने विभाग की कार्यशैली को एक बार फिर सवालों के घेरे में ला दिया है। अब सबकी नजर जिला प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है।●

बरेली में मौलाना तौसीफ रजा की संदिग्ध मौत

● **धर्मेन्द्र सिंह/फरीद अहमद**

उत्तर प्रदेश के बरेली में बिहार के एक युवा मौलाना की ट्रेन यात्रा के दौरान हुई मौत ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। 30 वर्षीय मौलाना तौसीफ रजा मजहरी का शव 26 अप्रैल को बरेली रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक किनारे मिला था। परिवार इसे हत्या बता रहा है, जबकि पुलिस शुरुआती जांच में इसे दुर्घटना मान रही है। मौलाना तौसीफ रजा बरेली शरीफ में वार्षिक उर्स में शामिल होने गए थे। उर्स समाप्त होने के बाद वे बिहार वापस लौट रहे थे। परिवार के सदस्यों का कहना है कि ट्रेन में कुछ यात्रियों ने उनके साथ बदसलूकी और मारपीट की, जिसके बाद उन्हें चलती ट्रेन से बाहर धकेल दिया गया। सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप तेजी से वायरल हो रही है। इसमें मौलाना अपनी पत्नी से बात करते हुए घबराए स्वर में मदद मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ लोग उन्हें मार रहे हैं। इस ऑडियो के सामने आने के बाद मामले की

गंभीरता बढ़ गई है।

☞ **परिवार की मांग :-** परिजनों ने निष्पक्ष जांच, दोषियों की गिरफ्तारी और उचित मुआवजे की मांग की है। किशनगंज के ठाकुरगंज और आसपास के इलाकों में स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर न्याय की अपील की। कई सामाजिक संगठनों और नेताओं ने भी उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।

☞ **पुलिस की स्थिति :-** बरेली पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह ट्रेन से गिरने की घटना लग रही है। गर्मी के कारण मौलाना ट्रेन के दरवाजे के पास बैठे हो सकते हैं। हालांकि, परिवार की शिकायत और वायरल ऑडियो के आधार पर अब विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। रेलवे पुलिस भी मामले की छानबीन कर रही है।

☞ **सामाजिक प्रतिक्रिया :-** यह घटना ट्रेन यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। बिहार और उत्तर प्रदेश में चर्चा तेज है। स्थानीय प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि जांच पूरी होने के बाद सच्चाई सामने आएगी। मामला अभी भी जांच के अधीन है। मामले को लेकर सांसद डॉ मोहम्मद जावेद आजाद ने बिहार के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड निवासी मौलाना मो. तौसीफ रजा की ट्रेन में हुई संदिग्ध मौत की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपये मुआवजा और पत्नी को सरकारी नौकरी देने का भी अनुरोध किया है। सांसद ने मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात करने की भी मांग की।●

डॉ॰ मोहम्मद जावेद
Dr. Mohammad Jawed
Member of Parliament, Lok Sabha

Member
Standing Committee on Rural Development
Consultative Committee on Health and Family Welfare

पत्रांक 951/KNF/2026 दिनांक 01/05/2026

सेवा में,
माननीय मुख्यमंत्री जी,
बिहार सरकार, पटना।

Dear Sir,

[illegible]

भवदीय

(डॉ मोहम्मद जावेद)
सांसद-10, किशनगंज।

Address :- Line Mohalla, Kishanganj (Bihar) - 855107 [illegible]

अवैध गैस सिलेंडर भंडारण के विरूद्ध बड़ी कार्रवाई

● धर्मेन्द्र सिंह/फरीद अहमद

जिला पदाधिकारी विशाल राज के निर्देशानुसार जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध उपयोग, जमाखोरी एवं बिना अनुज्ञप्ति गैस भंडारण के विरुद्ध लगातार सघन जांच अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में प्राप्त गोपनीय सूचना के आधार पर जियापोखर थाना क्षेत्र अंतर्गत मालिनगांव पंचायत के ग्राम गिल्हाबाड़ी स्थित M/S NIHAR BRICKS ईंट भट्टा में व्यापक छापेमारी कार्रवाई की गई। प्राप्त सूचना में बताया गया था कि उक्त ईंट भट्टा परिसर में बड़ी मात्रा में घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध रूप से भंडारण एवं उपयोग किया जा रहा है। सूचना मिलते ही प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों की संयुक्त टीम का गठन कर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की गई। छापेमारी टीम में एसडीओ अनिकेत कुमार, एसडीपीओ, खनिज विकास पदाधिकारी प्रणव कुमार प्रभाकर, राजस्व अधिकारी ठाकुरगंज राहुल कुमार, जियापोखर थाना अध्यक्ष, पौआखाली थाना अध्यक्ष, श्रम अधीक्षक किशनगंज, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी ठाकुरगंज सहित पुलिस बल एवं अन्य प्रशासनिक कर्मी शामिल थे। टीम द्वारा ईट भट्टा परिसर में पहुंचकर विधिवत जांच प्रारंभ की गई।

जांच के दौरान ईट भट्टा स्वामी एकरामुल हक मौके पर उपस्थित नहीं पाए गए। इसके बाद भट्टा परिसर में मौजूद कर्मी/मुंशी अमित कुमार की उपस्थिति में विधिसम्मत छापेमारी की गई। तलाशी अभियान के दौरान भट्टा परिसर से कुल 62 गैस सिलेंडर बरामद किए गए। बरामद सिलेंडरों में इंडेन कंपनी के 54 घरेलू गैस सिलेंडर (14.2 किलोग्राम) शामिल हैं, जिनमें 49 खाली तथा 05 भरे हुए पाए गए। इसके अतिरिक्त 04 कॉमर्शियल गैस सिलेंडर भी बरामद किए गए, जो भरे हुए थे। छापेमारी के दौरान मौके पर मौजूद कर्मियों से गैस सिलेंडरों के उपयोग, भंडारण एवं वैध कागजात के संबंध में पूछताछ की गई, किंतु उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तथा न ही किसी प्रकार का वैध दस्तावेज प्रस्तुत किया जा सका। इसके उपरांत उपस्थित दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों की मौजूदगी में सभी गैस सिलेंडरों को विधिवत जब्त किया गया तथा जब्ती सूची तैयार कर उसकी प्रति संबंधित कर्मी को उपलब्ध कराई गई। जब्त सभी गैस सिलेंडरों को सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए पुलिस बल की सहायता से वाहन पर लादकर पौआखाली स्थित मेसर्स आयशा रहमान एचपी गैस एजेंसी के गैस गोदाम में सुरक्षित जमा कराया गया।

प्राथमिक जांच में यह स्पष्ट रूप से सामने आया कि बिना विस्फोटक अनुज्ञप्ति के बड़ी मात्रा में एलपीजी गैस सिलेंडरों का भंडारण किया जा रहा था, जो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश, 2000, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं विस्फोटक अधिनियम का गंभीर उल्लंघन है। प्रशासन ने इसे जन सुरक्षा के लिए अत्यंत संवेदनशील एवं खतरनाक माना है, क्योंकि इस प्रकार का अवैध भंडारण किसी भी समय बड़े हादसे का कारण बन सकता था। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग एवं अवैध जमाखोरी पूरी तरह गैरकानूनी है तथा इससे आम उपभोक्ताओं की गैस आपूर्ति भी प्रभावित होती है। ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा संलिप्तता पाए जाने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में ईंट भट्टा स्वामी एकरामुल हक, पिता स्व० जमशेद अली, निवासी बन्दरझुला, थाना-जियापोखर, जिला-किशनगंज के विरुद्ध जियापोखर थाना कांड संख्या 32/26, दिनांक 12.05.2026 दर्ज किया गया है। प्राथमिकी Essential Commodities Act, 1955 की धारा-7, 9B Explosive Substances Act एवं भारतीय न्याय संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दर्ज की गई है। जिला प्रशासन द्वारा कहा गया है कि जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध उपयोग, भंडारण एवं जमाखोरी के विरुद्ध आगे भी लगातार अभियान जारी रहेगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।●

पौआखाली अस्पताल में औचक निरीक्षण

बदहाली देख बिखरे विधायक

● फरीद अहमद

जिले के ठाकुरगंज प्रखंड के नगर पंचायत पौआखाली स्थित शहरी सरकारी अस्पताल पौआखाली मूलभूत सुविधाओं की बदहाली को लेकर खूब चर्चाओं में हैं। 6 मई को ठाकुरगंज विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल ने जब अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, तो वहां की बदहाली देख वे दंग रह गए। अस्पताल में चारों ओर व्याप्त गंदगी और अव्यवस्था ने सरकारी दावों की पोल खोल कर रख दी है।

☞ **न पीने का पानी, न साफ शौचालयः नरकीय स्थिति में मरीज :-** निरीक्षण के दौरान विधायक ने पाया कि अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों के लिए पेयजल (पीने के पानी) तक की बुनियादी सुविधा उपलब्ध नहीं है। सबसे भयावह स्थिति अस्पताल के शौचालयों की दिखी, जो पूरी तरह गंदगी से भरे पड़े थे। साफ-सफाई के नाम पर अस्पताल में खानापूर्ति की जा रही है, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है।

☞ **इमरजेंसी वार्ड का हालः बिखरा सामान और खाली बेड :-** अस्पताल की लापरवाही का आलम यह है कि इमरजेंसी सेवाओं के लिए इस्तेमाल होने वाले जरूरी उपकरण और सामान जैसेः रुई और बैंडेजः फर्श पर इधर-उधर बिखरे पाए गए।

☞ **बेड की स्थिति :-** वार्डों में बेड पर चादर तक नहीं बिछी थी। इमरजेंसी वार्ड में जरूरी सामग्रियां सुरक्षित रखने के बजाय कूड़े की तरह फेंकी हुई मिलीं।

☞ **विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल का बयान :-** अस्पताल की स्थिति अत्यंत चिंताजनक और घोर लापरवाही का उदाहरण है। जहाँ गरीबों को इलाज मिलना चाहिए, वहाँ बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हैं। मैंने इस पूरे मामले की जानकारी किशनगंज के सिविल सर्जन को दे दी है और जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की मांग की है। लोगों का कहना है कि पौआखाली और आसपास के गरीब ग्रामीण इसी अस्पताल के भरोसे रहते हैं। लेकिन जब अस्पताल में पीने का पानी और साफ शौचालय तक नहीं है, तो वहां इलाज की गुणवत्ता क्या होगी, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। विधायक के इस कड़े रुख के बाद अब सबकी नजरें स्वास्थ्य विभाग पर टिकी हैं। क्या सिविल सर्जन लापरवाह कर्मियों और अस्पताल प्रबंधन पर कोई बड़ी कार्रवाई करेंगे? या फिर पौआखाली के गरीब मरीज इसी तरह बदहाली के बीच इलाज कराने को मजबूर रहेंगे? ●

सड़क निर्माण कार्य में अनियमितता

● धर्मेन्द्र सिंह/फरीद अहमद

जिले के ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत जिरनगाछ क्षेत्र में हाल ही में बनी सड़क की गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। तारा बाड़ी चौक से महेशपुर तक जाने वाली यह सड़क करीब पांच गांवों को जोड़ती है और चार पंचायतों के बीच आवागमन का मुख्य रास्ता है, लेकिन निर्माण के कुछ ही दिनों बाद इसकी हालत बदतर हो गई है। ग्रामीणों के अनुसार, सड़क बने अभी लगभग एक सप्ताह ही हुआ है, लेकिन जगह-जगह से गिट्टियां उखड़ने लगी हैं। हैरानी की बात यह है कि सड़क के बीचों-बीच घास तक उग आई है, जो निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। सड़क की सतह भी समतल नहीं है, जिससे खासकर दोपहिया वाहन चालकों के लिए यह रास्ता खतरनाक बन गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्य में मानकों की अनदेखी की गई और घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि अधिकतर काम रात के समय किया गया, जिससे गुणवत्ता पर संदेह और गहरा गया है। ग्रामीणों ने बताया कि इस मामले की जानकारी संबंधित जेई को मौखिक रूप से दी गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे लोगों में प्रशासन के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों की मांग है कि सड़क निर्माण की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, दोषी ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई हो और जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत कराई जाए, ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। अब देखना यह है कि प्रशासन इस पुरे मामले में क्या कार्रवाई करती है?●

ठाकुरगंज प्रखंड कार्यालय में बैठक

● फरीद अहमद

जिले प्रखंड कार्यालय ठाकुरगंज के सभागार में प्रखंड विकास पदाधिकारी अहमर अब्दाली की अध्यक्षता में स्थानीय मुखिया एवं पंचायत समिति सदस्यों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई योजनाओं और सरकारी अभियानों की विस्तृत जानकारी साझा की गई। सबसे पहले 'ज्ञान भारतम मिशन' पर चर्चा करते हुए बीडीओ ने बताया कि इस मिशन के तहत लगभग 70-75 वर्ष पुरानी पांडुलिपियों को डिजिटल माध्यम से संरक्षित किया जाएगा। कागज, ताम्र पत्र या कपड़े पर लिखी किसी भी भाषा की पुरानी सामग्री को ऐप के जरिए सुरक्षित किया जाएगा। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से इस अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का आग्रह किया। नेपाल सीमा से जुड़े क्षेत्र होने के कारण भारतीय नागरिक से विवाह करने वाली नेपाली महिलाओं के नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया पर भी विस्तार से जानकारी दी गई। बताया गया कि इस संबंध में पहले ही प्रखंड स्तर पर जागरूकता शिविर आयोजित किए जा चुके हैं।

बैठक में 'सहयोग शिविर' के आयोजन की भी जानकारी दी गई। इसके तहत प्रत्येक माह के प्रथम और तीसरे मंगलवार को आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए शिविर लगाए जाएंगे। 19 मई 2026 को कुकरबाघी, पथरिया और रसिया पंचायतों में यह शिविर आयोजित होगा, जहां पंचायत भवन/मनरेगा भवन में आवेदन लेकर समस्याओं का निष्पादन किया जाएगा। इसके अलावा भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण कार्य की जानकारी देते हुए बीडीओ ने बताया कि यह कार्य 31 मई 2026 तक चलेगा। इस दौरान प्रगणक घर-घर जाकर 33 प्रकार के प्रश्न पूछेंगे और पूरा कार्य डिजिटल माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने लोगों को आगाह किया कि OTP के नाम पर किसी भी तरह की धोखाधड़ी से सावधान रहें और केवल अधिकृत प्रगणक को ही जानकारी दें।

अंत में पंचायत निर्वाचन 2026 के तहत प्रारूप प्रपत्र-01 के प्रकाशन की जानकारी दी गई। यह प्रपत्र 4 मई 2026 से प्रखंड व पंचायत कार्यालयों में उपलब्ध है, जिस पर 18 मई 2026 तक दावा एवं आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। बैठक में सभी जनप्रतिनिधियों से सरकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने और लोगों को जागरूक करने की अपील की गई।●

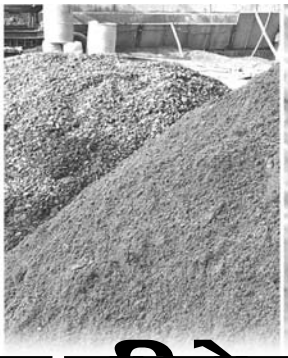

करोड़ों की बायपास परियोजना पर उठे सवाल

● धर्मेन्द्र सिंह/फरीद अहमद

जिले के ठाकुरगंज शहर को ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के उद्देश्य से बनाई जा रही बहुप्रतीक्षित बायपास सड़क अब निर्माण गुणवत्ता को लेकर विवादों में घिर गई है। सड़क निर्माण विभाग (आरसीडी) मद से लगभग 39 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रही इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पुल निर्माण कार्य में कथित अनियमितताओं को लेकर सोमवार को स्थानीय ग्रामीणों का आक्रोश खुलकर सामने आया। सुबह निर्माण स्थल पर पहुंचे ग्रामीणों ने कार्य में इस्तेमाल हो रही निर्माण सामग्री पर गंभीर सवाल उठाए। स्थानीय निवासी मो. शब्बीर, मुख्तार, औरंगजेब समेत अन्य ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुल निर्माण में निर्धारित तकनीकी मानकों की अनदेखी की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि मजबूत और टिकाऊ निर्माण के लिए जहां पीली बालू का उपयोग होना चाहिए,

वहां स्थानीय स्तर की बालू का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि निर्माण कार्य में पीपीसी सीमेंट का उपयोग किया जा रहा है, जबकि पुल निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में सामान्यत: ओपीसी सीमेंट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ग्रामीणों का कहना है कि ठाकुरगंज लंबे समय से ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझ रहा है। बाजार क्षेत्र में अक्सर घंटों जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे आम लोगों, व्यवसायियों और स्कूली बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इस बायपास परियोजना को इलाके के विकास और यातायात व्यवस्था में सुधार की बड़ी उम्मीद के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन निर्माण के शुरुआती चरण में ही गुणवत्ता को लेकर उठे सवालों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। स्थानीय लोगों ने आशंका जताई कि यदि अभी से निर्माण कार्य में लापरवाही बरती गई तो आने वाले समय में सड़क और पुल की मजबूती प्रभावित हो सकती है। लोगों का कहना है कि करोड़ों रुपये की यह परियोजना यदि घटिया सामग्री और मानकों से समझौता कर तैयार की गई तो भविष्य में यह आम जनता के लिए परेशानी और खतरे का कारण बन सकती है। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि सरकारी योजनाओं में अक्सर निर्माण कार्य पूरा होने के कुछ वर्षों बाद ही सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त होने लगते हैं, जिसका मुख्य कारण निर्माण में गुणवत्ता की अनदेखी और निगरानी की कमी होती है। लोगों का कहना है कि इस परियोजना में ऐसी स्थिति दोबारा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह केवल सड़क निर्माण नहीं बल्कि ठाकुरगंज के भविष्य और विकास से जुड़ा मामला है।

मामले को लेकर जब सड़क निर्माण

विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया गया तो विभागीय एसडीओ गोपाल मंडल ने कहा कि संवेदक को गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि निर्माण स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। विभाग का कहना है कि कार्य तकनीकी मानकों के अनुरूप कराया जा रहा है और यदि कहीं कोई कमी पाई जाती है तो उसे तत्काल दुरुस्त कराया जाएगा। हालांकि ग्रामीण विभागीय आश्वासनों से पूरी तरह संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। उनका कहना है कि केवल निर्देश देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि निर्माण कार्य की नियमित निगरानी और सामग्री की तकनीकी जांच भी जरूरी है। ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा कि वे अब निर्माण कार्य पर लगातार नजर रखेंगे और किसी भी प्रकार की अनियमितता सामने आने पर प्रशासन एवं विभाग के समक्ष आवाज उठाते रहेंगे। इधर, परियोजना को लेकर इलाके में राजनीतिक और सामाजिक चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। लोगों का कहना है कि करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद यदि निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं तो यह सरकारी व्यवस्था और निगरानी तंत्र पर गंभीर प्रश्नचिह्न है। आम लोगों की मांग है कि निर्माण सामग्री की स्वतंत्र तकनीकी जांच कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। फिलहाल बायपास परियोजना निर्माणाधीन है, लेकिन गुणवत्ता को लेकर उठे सवालों ने शुरुआत में ही विभाग की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि विभाग ग्रामीणों की शिकायतों को कितनी गंभीरता से लेता है और निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।●

नूरी चौक चोरी कांड का खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार

● फरीद अहमद

किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत पौआखाली थाना क्षेत्र के नगर पंचायत स्थित नूरी चौक में किराना दुकान में हुई चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में सिमलबाड़ी निवासी कलाम (23) पिता- मोहमद्दीन एवं सज्जाद आलम उर्फ पनडुब्बा (25) पिता- साबिर आलम को गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि नूरी चौक स्थित खालिद रजा की किराना दुकान में चोरों ने अहले सुबह धावा बोलकर करीब 30 हजार रुपये नकद समेत अन्य सामान चोरी कर लिया था। घटना के बाद पीड़ित दुकानदार ने पौआखाली थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संदिग्धों को चिन्हित कर पूछताछ की, जिसके बाद दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी निशानदेही पर चोरी किए गए 5500 रुपये नकद, 06 पैकेट सिगरेट और 05 पाउच रजनीगंधा-तुलसी बरामद किया गया है।

पीड़ित दुकानदार

थानाध्यक्ष अंकित सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी सज्जाद आलम उर्फ पानीडुब्बा का आपराधिक इतिहास रहा है। उसके खिलाफ पूर्व में पौआखाली थाना कांड संख्या-37/21, 14/25 तथा बहादुरगंज थाना कांड संख्या-382/25 दर्ज हैं। वहीं, कलाम के खिलाफ भी पहले से एक मामला दर्ज है। मामले को लेकर पौआखाली थानाध्यक्ष अंकित सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों अभियुक्त स्मैक का सेवन करते थे और स्मैक की लत के चपेट में आ गये थे नशा सामाग्री खरीदने के लिए चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम देने लगे थे। गौर करें कि एक खामोश लेकिन खतरनाक संकट तेजी से गहराता जा रहा है। यहां की युवा पीढ़ी "सूखा नशा" और स्मैक जैसे घातक पदार्थों की गिरफ्त में फंसती जा रही है। यह सिर्फ एक कानून- व्यवस्था का मुद्दा नहीं, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक ताने-बाने को तोड़ने वाली गंभीर समस्या बन चुकी है।●

कालीबाग में मिली दुर्लभ एवं प्राचीन पांडुलिपियां

● रवि रंजन मिश्र

पश्चिम चम्पारण जिले के काली बाग क्षेत्र में स्थित श्री देवप्रकाश पांडेय के आवास से दुर्गा सहस्रनाम स्तोत्र सहित कई दुर्लभ एवं प्राचीन पांडुलिपियों के मिलने की सूचना जिला प्रशासन को प्राप्त हुई। इस महत्वपूर्ण सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण को लेकर जिला पदाधिकारी श्री तरनजोत सिंह स्वयं उनके आवास पहुंचे और पांडुलिपियों का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान जिला पदाधिकारी ने पांडुलिपियों की ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्ता पर विशेष चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की प्राचीन पांडुलिपियां हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की अमूल्य धरोहर हैं, जिनका संरक्षण और डिजिटलीकरण अत्यंत आवश्यक है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ सकें। डीएम ने मौके पर उपस्थित संबंधित अधिकारियों एवं तकनीकी कर्मियों को निर्देश दिया कि पांडुलिपियों का सुरक्षित तरीके से डिजिटलीकरण सुनिश्चित किया जाए। इसी क्रम में दुर्गा सहस्रनाम स्तोत्र एवं अन्य प्राचीन पांडुलिपियों को भारत सरकार की महत्वपूर्ण डिजिटल पहल 'ज्ञान भारतम ऐप' पर अपलोड कराया गया, जिससे इन ऐतिहासिक दस्तावेजों को व्यापक स्तर पर संरक्षित एवं अध्ययन योग्य बनाया जा सके। जिला पदाधिकारी ने कहा कि पश्चिम चम्पारण ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध जिला रहा है।

यहां समय-समय पर ऐसी कई महत्वपूर्ण धरोहरें सामने आती रही हैं, जो भारतीय सभ्यता और ज्ञान परंपरा की गहराई को दर्शाती हैं। उन्होंने आम लोगों से भी अपील की कि यदि उनके पास किसी प्रकार की प्राचीन पांडुलिपि, हस्तलिखित ग्रंथ या ऐतिहासिक दस्तावेज उपलब्ध हों, तो उसकी जानकारी प्रशासन को दें, ताकि उनका संरक्षण एवं डिजिटलीकरण कराया जा सके। इस अवसर पर जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी श्री राकेश कुमार सहित संस्कृताचार्य श्री कृष्णमोहन प्रसाद, श्री प्रशांत कुमार सहित स्थानीय गणमान्य लोग उपस्थित रहे।●

कुख्यात अपराधी संजीव उर्फ पुट्टू मिश्रा की हत्या

पश्चिम चंपारण के बगहा अनुमंडल अंतर्गत रामनगर क्षेत्र एक बार फिर दहशत के साए में है, जहां कुख्यात अपराधी संजीव मिश्रा की हत्या ने इलाके में सनसनी फैला दी है। बताया जा रहा है कि संजीव मिश्रा अपराध की दुनिया का बड़ा नाम था और उस पर हत्या, रंगदारी, आर्म्स एक्ट और जमीन विवाद से जुड़े दर्जनों गंभीर मुकदमे दर्ज थे। स्थानीय सूत्रों के अनुसार वह लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय था और इलाके में दबदबा बनाए हुए था। घटना के बाद पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जानकारी में यह सामने आया है कि वारदात रामनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई, जहां पहले से ही भूमि विवाद और आपसी रंजिश की घटनाएं सामने आती रही हैं। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि हत्या के पीछे आपसी गैंगवार है या किसी पुराने जमीन विवाद की कड़ी। स्थानीय लोगों में इस घटना के बाद डर का माहौल है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं पर जांच जारी है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। **रिपोर्ट :-● रवि रंजन मिश्र**

अविलंब करें नगर निगम क्षेत्र की सम्पूर्ण साफ सफाई : गरिमा

● रवि रंजन मिश्र

नगर निगम के सशक्त स्थायी समिति की महत्वपूर्ण बैठक में गुरुवार को आयोजित की गई। महापौर गरिमा देवी सिकारिया की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में आयोजित बैठक में अपने सफाई कर्मियों के साथ नगर निगम क्षेत्र की सम्पूर्ण साफ सफाई व्यवस्था अविलंब आउट सोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से सुनिश्चित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। महापौर श्रीमती सिकारिया ने कहा इसके लिए नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा आदेश जारी करते हुए आरएफपी अर्थात रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के आधार पर आउट सोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से सफाई व्यवस्था जारी रखने का आदेश जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व में

बीते सालों भी बोर्ड एवं सशक्त के स्तर से इसका निर्देश दिया गया था, लेकिन उसका अनुपालन अब तक नहीं किया गया है। इसके साथ अन्य पारित प्रस्तावों के बाबत महापौर गरिमा सिकारिया ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बंदोबस्ती से बचे सैरातों यथा विज्ञापन होर्डिंग और शौचालयों की बंदोबस्ती के लिए अविलंब निविदा जारी करने का प्रस्ताव पारित किया गया है इसके अलावा नगर निगम बोर्ड से पारित अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं यथा ऐतिहासिक कालीबाग मंदिर, न्यू बस स्टैंड और महारानी जानकी कुंवर नगर भवन आदि के लिए नगर निगम बोर्ड द्वारा पारित प्रस्तावों के आलोक में निविदा जारी करने के साथ संत घाट और खिरिया घाट मुहल्ले में स्थित नगर निगम की सरकारी जमीन पर सामुदायिक भवन निर्माण की पारित योजनाओं की निविदा अविलंब जारी करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। बैठक का संचालन नगर आयुक्त शिवाक्षी दीक्षित द्वारा किया गया। ●

चनपटिया एवं मझौलिया प्रखण्ड के विद्यार्थियों को मिली राहत

● रवि रंजन मिश्र

जिले के चनपटिया एवं मझौलिया प्रखंड के विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर सात निश्चय-3 के तहत डिग्री कॉलेज स्थापना की सूची में संशोधन करते हुए दोनों प्रखंडों को शामिल कर लिया गया है। इससे पहले जारी सूची में चनपटिया और मझौलिया का नाम नहीं था, जिसे लेकर स्थानीय स्तर पर लगातार मांग उठ रही थी। दरअसल चनपटिया विधायक अभिषेक रंजन की पहल पर यह निर्णय संभव हो सका। विधायक ने 24 अप्रैल को मुख्यमंत्री के निजी आवास पर मुलाकात कर दोनों प्रखंडों में डिग्री कॉलेज की आवश्यकता को प्रमुखता से रखा था। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के समक्ष भी इस मांग को उठाया था। इसके बाद सरकार ने संशोधित अधिसूचना जारी कर दोनों प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने की स्वीकृति दे दी। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, स्थायी भवन निर्माण होने तक अस्थायी व्यवस्था के तहत 1 जुलाई से शैक्षणिक सत्र प्रारंभ किया जाएगा। चनपटिया में राजकीय +2 उच्च विद्यालय, कुमारबाग तथा मझौलिया में राजकीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय, सेनुअरिया में कक्षाएं संचालित होंगी। विधायक

अभिषेक रंजन ने बताया कि शीघ्र ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर चनपटिया नगर एवं मझौलिया के तिरवा क्षेत्र में डिग्री कॉलेज का स्थायी भवन निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने इस निर्णय के लिए बिहार सरकार एवं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। स्थानीय लोगों और छात्र-छात्राओं ने इस निर्णय का स्वागत किया है। उनका कहना है कि अब क्षेत्र में ही उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध होने से उन्हें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिससे समय और खर्च दोनों की बचत होगी। ●

अभी कलम उठाइये

आपके सामने हो रहे भ्रष्टाचार एवं अपराध की खबर की समीक्षा करें और सरकार सहित पुलिस-प्रशासन तक उसको पहुंचाने के लिए केवल सच पत्रिका के साथ जुड़े। खबर की जानकारी इस नम्बर पर दें

सम्पर्क करें:- 9431073769/8340360961

ई-मेल:- editor.kstimes@rediffmail.com पर भेजें।

कर्तव्यनिष्ठता की कब्र में दफन होता

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

● बिन्ध्याचल सिंह

'दुगो फुटले फुटल एगो के पेनीय नाही' भोजपुरी कहावत तब आप चरितार्थ होते पायेगें जब जिलाधिकारी श्रीमति साहिला के द्वारा 12/12/2025 के बैठक के दौरान दी गई निर्देश का अवलोकन करेगें। 12/12/2025 को समाहरणालय सभाकक्ष मे जिला स्तरीय समीक्षा सह निर्देश बैठक आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान कई निर्देश था जिसमें ''आर टी आई'' मामलों एवं न्यायालयीन पत्राचार पर समयबद्ध कर्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था। परन्तु वर्तमान समय में जिला शिक्षा पदाधिकारी बक्सर, पुलिस उपाधीक्षक/मुख्यालय बक्सर व पिछडा वर्ग एवं अन्य पिछडा वर्ग कल्याण पदाधिकारी बक्सर, कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, बक्सर पर जिलाधिकारी के निर्देश का कोई असर नही दिख रहा है। जिसकी जानकारी भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या-69एफ 738411, 738410, 738409 दिनांक-29/11/2025 जिसके माध्यम से दिनांक-03/02/2026 को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत सूचना की मॉग की

To लोक सूचना पदाधिकारी
सह
जिला पिछडा वर्ग एवं अति पिछडा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, बक्सर
समाहरणालय परिसर
जिला - बक्सर
बिहार

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER
69F 738411

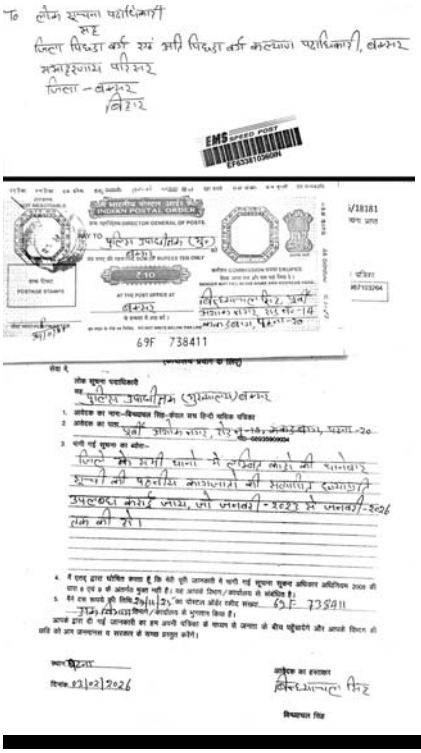

To लोक सूचना पदाधिकारी
सह
प्रभारी महाप्रबंधक
जिला उद्योग केन्द्र, बक्सर
बिहार औद्योगिक क्षेत्र, बक्सर
जिला - बक्सर
बिहार-

From विन्ध्याचल सिंह
ब्यूरो
केवल सच (हिन्दी मासिक पत्रिका)
बक्सर
प्रधान कार्यालय
पूर्वी अशोक नगर, रोड नं०-14
मकान संख्या 14/28
कंकड़बाग, पटना -20
मो० - 8935909034
8987103264

Buxar HO 802101
EF762586488IN, IVR No1: 69707625864[illegible]
14/03/2026 11:31:20, Counter No: 1,
To: INCHARGE JILA UDYOG KENDRA
BUXAR, BUXAR, 802101
From: VINDHYACHAL SINGH
[illegible] PATNA, PATNA, 800020
Base Amt: 19.00
Wt:20gms(Phy.)
P.Mode: Cash
POD:No, www.indiapost.gov.in

कार्यालयः महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, बक्सर।

पत्रांक - 110 [illegible] दिनांक - 06/04/2026

प्रेषक,
प्रभारी महाप्रबंधक
जिला उद्योग केन्द्र
बक्सर।

सेवा में,
श्री विन्ध्याचल सिंह
पता-आदीपुर, पो०-महुऑव
जिला-भोजपुर आरा पिन-802183
मो०-8935909034

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अध्याय 2 के कंडिका 8 के उपनियम (त्र) के अनुसार व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है। जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नही रखता है, या जिससे व्यक्ति की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा।

विश्वासभाजन
प्रभारी महाप्रबंधक,
जिला उद्योग केन्द्र,
बक्सर।

गई थी, परन्तु खबर लिखे जाने तक सूचना उपलब्ध नही कराई गई है। इसी कड़ी में प्रिय पाठकगण जानकारी के लिये बताते चले कि प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र बक्सर के द्वारा पत्रांक-110 के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सूचना के बारे में कुछ रोचक जानकारी इस प्रकार है। जिला उद्योग केन्द्र बक्सर के पत्रांक-377 दिनांक-17/03/2025 को लगभग 150 यूनिट की जानकारी प्राप्त हुई, जिसमें अधिकतम राशि-1279999/ -रू0 गोल्डी कुमारी भारतीय स्टेट बैक सरेजा के सहयोग से स्वावलम्बी बनने की प्रयास कर रही है, जिसके डी आर पी चन्दन कुमार यादव है।

श्रीमती शाहिला
जिलाधिकारी, बक्सर

वही सबसे कम राशि 63000/-रू0 किशन यादव इडियन बैक चक्की से प्राप्त किये है। जिसके डी आर पी अभय कुमार दुबे जी है। इस प्रकार औसतन यूनिट लागत खर्च-671499/-रू0 है। पत्रांक-377 को आधार मानकर यूनिट की धरातल की जॉच की गई तो पता चला कि पीएमएफएमई योजना मे ऐसे भगदड मची हुई है जैसे आज से लगभग 60-70 वर्ष पहले हैजा, प्लेग जैसे बिमारियो से भगदड हुआ करती थी। पीएमएफई योजना में भगदड मचाने वाले मे महाप्रबंधक जिला अग्रणी बैक बक्सर की भूमिका संदिग्ध रहती है। जिला उद्योग केन्द्र बक्सर के पत्रांक-110 दिनांक 06/04/2026 जिलाधिकारी बक्सर के निर्देश का पालन तो किया गया परन्तु भोजपुरी वाक्य:- ''राउर बात मानतानी लेकिन खुटा एहीजे गढाईं''। महोदया के द्वारा दिनांक 19/02/2026 को पीएमएफएमई योजनान्तर्गत 08 लाभुको की ऋण की स्वीकृति एवं 04 लाभुको को राशि की भुगतान कराई गई थी। जिससे बेरोजगार व्यक्ति रोजगारयुक्त बन सके, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वितीय वर्ष-2024-2025 और 2025-2026 मे करोडो रू0 की यूनिट की राशि बैक से निकाल कर यूनिट धरातल पर स्थापित ही नही की गई है जिसकी जानकारी केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका द्वारा दी जा चुकी है। जानकारी के लिये बताते चले कि जिस वितिय वर्ष में राशि की घोटाला हो चुकी है उस समय तत्कालीन जिलाधिकारी श्री अंशुल अग्रवाल, जबकि प्रभारी महाप्रबंधक मनीषा कुमारी थी। लेकिन यक्ष प्रश्न यह है कि प्रभारी महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र

बक्सर ज्योतिषा वर्मा जी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के माध्यम से मॉगी गई सूचना के अनुसार सूचना उपलब्ध क्यो नही कराई जाती है। क्या है उनकी मजबुरी? क्या किसी उद्योग विस्तार पदाधिकारी या दबंग जिला संसाधन सेवी या एल डी एम या नोडल पदाधि कारी के दबाव में विभागीय कार्य निष्पादित करती है? ये जॉच का विषय है परन्तु दावे के साथ कहा जा सकता है कि ईमानदार पदाधि कारी में से एक स्थान रखती है। हालाकि केवल सच प्रतिनिधि के पास इसकी प्रमाण नही है,परन्तु ऐसी चर्चाए उद्योग विभाग के लाभार्थीयो से अक्सर सुनने को मिलती-रहती है। लेकिन सबसे बडा सवाल यह है कि करोडो रू0 की घोटाला यूनिट के नाम हो चुकी है तो इसकी जानकारी जिलाधिकारी श्रीमति साहिला को क्यो नही दी गई? यदि करोडो रू0 की घोटाला नही हुई तो यूनिट की जॉच क्यो नही की जा रही है। 13 मार्च 2026 को महोदया के द्वारा जिले के सभी नगर परिषद्/नगर पंचायतो में कुछ पदाधिकारीयो को आदेश दिया गया था कि स्वच्छता की प्रत्येक वार्डो की नियमित जॉच करेगे, जिसमें पदाधि कारीगण को वार्ड की संख्या निंधारित की गई थी। लेकिन पदाधिकारी के द्वारा नियमित जॉच की बात छोडिये कभी-कभी भी जॉच होती है या नही वार्ड की जनता से जानकारी ली जा सकती है। सूचीबद्ध खबर आईपीआरडी ग्रुप, बक्सर आम-जनता के साथ विशेष सूत्रो की जानकारी में की गई है। लेकिन उपरोक्त खबर की धरातल पर जॉच की जाय तो जिलाधिकारी श्रीमति साहिला की आदेश-निर्देश जिले के कुछ पदाधिकारी के लिये मात्र एक संदेश है, न कि निर्देश।●

धनवानों की बक्सर पुलिस, गरीबों व अंधों की नही : सुदामा शर्मा

● **बिन्ध्याचल सिंह**

'अरे तु भाग यहॉ से। तु तो पागल है, यहॉ कौन लाया तुझे' इस वाक्य का प्रयोग थानाध्यक्ष राजपुर ने दिनांक-07/02/2026 को सुदामा शर्मा को कही। इसकी जानकारी केवल सच प्रतिनिधि को 02 अप्रैल 2026 को नगर पंचायत चौसा अन्तर्गत बक्सर-चौसा मार्ग पर जानकारी सुदामा शर्मा ने दी। श्री शर्मा ने जानकारी दी कि मै सुदामा शर्मा पिता-स्व रामअवतार शर्मा ग्राम-सोनपा, पो.-सोनपा, थाना-राजपुर जिला-बक्सर,बिहार के रहने वाला हुँ। मेरी उम्र-32 वर्ष और 90 प्रतिशत नेत्रहीन हुँ। थानाध्यक्ष, राजपुर व पुलिस अधीक्षक बक्सर के दिये आवेदन में लिखे है कि मेरी मॉ सरस्वती देवी व भाई कृष्णा शर्मा ने मेरे साथ बार-बार मारपीट कर घर से भगा रहे है। मै दिव्यांग व्यक्ति कहा जाउ। आवेदन में श्री शर्मा ने श्रीमान से निवेदन पूर्वक मॉ सरस्वती देवी व भाई कृष्णा शर्मा की सच्चाई की जानकारी प्राप्तकर न्याय की मॉग करते है। श्री शर्मा लगभग 25 मिनट की बातचीत में कहा कि मेरा भाई कृष्णा शर्मा बक्सर जिला में अवैध रूप से बिकने वाली नशा का सेवन के साथ बिक्री भी करता है। जिसमें शराब का नशा उसका प्रमुख है। यही मुख्य कारण है कि मेरे भाई का थाना परिसर में आना-जाना रहता है। अपनी शिक्षा व शिष्टाचार का परिचय देते हुए श्री शर्मा ने अपनी मॉ सरस्वती देवी व भाई कृष्ण शर्मा के साथ थानाध्यक्ष राजपुर पर नियमानुसार

कारवाई करने के लिये पुलिस अधीक्षक से आवेदन के माध्यम से गुहार 23/02/2026 को लगा चुके है। परन्तु खबर लिखने जाने तक श्री शर्मा की सुरक्षा से सम्बन्धित कोई भी कार्य बक्सर पुलिस के द्वारा नही की गई है। जैसा कि शर्मा जी ने केवल सच प्रतिनिधि को जानकारी दे चुके है। प्रिय पाठकगण अगर सूत्रो की माने तो जिला में शान्ति व्यवस्था अन्य जिले की तुलना में बेहतर है इसको नकारा नही जा सकता है, लेकिन जिले के मुख्यत: तीन थाना क्रमश: बगेन, सिकरौल, राजपुर की बात को नजर अंदाज किया जाय तो बक्सर पुलिस की कार्य प्रणाली व कर्तव्यनिष्ठता को जितनी भी सराहना की जाय कम ही होगी। ●

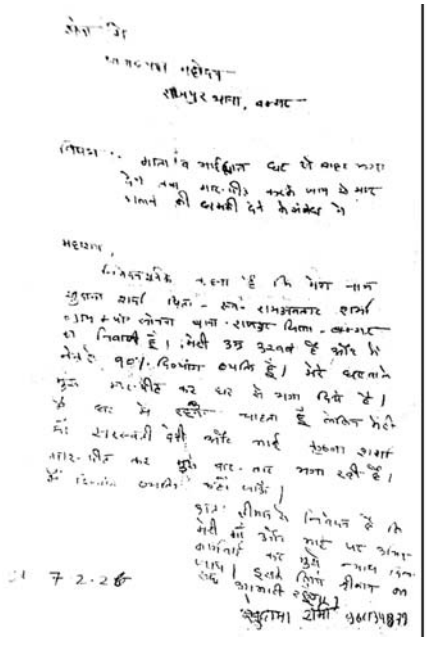

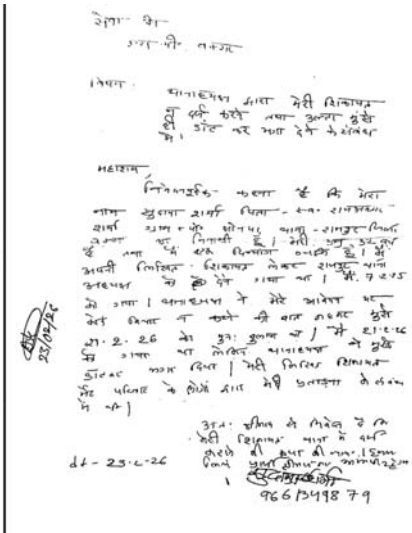

● **भारती मिश्रा**

झारखंड की राजनीति इन दिनों कथित ट्रेजरी घोटाले को लेकर उबाल पर है। सरकारी खजाने से करोड़ों रुपये की अवैध निकासी के आरोपों ने न सिर्फ प्रशासनिक तंत्र की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि सत्ता और सिस्टम के बीच संभावित गठजोड़ की आशंकाओं को भी हवा दे दी है। विपक्षी भाजपा इस मुद्दे को लगातार आक्रामक तरीके से उठा रही है और पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से कराने की मांग कर रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद आदित्य प्रसाद साहू ने मुख्यमंत्री को एक विस्तृत पत्र लिखकर इस कथित घोटाले को "राज्य की वित्तीय व्यवस्था पर सबसे बड़ा दाग" बताया है। उन्होंने दावा किया कि यह मामला केवल कुछ कर्मचारियों की हेराफेरी नहीं, बल्कि वर्षों से चल रहे एक संगठित भ्रष्टाचार नेटवर्क की ओर इशारा करता है। भाजपा ने यहां तक कहा कि यह मामला संयुक्त बिहार के चर्चित चारा घोटाला से भी बड़ा साबित हो सकता है।

❖ **कैसे सामने आया मामला? :-** जानकारी के अनुसार, ट्रेजरी और ई-कुबेर भुगतान प्रणाली में कथित तकनीकी हेरफेर कर सरकारी राशि की अवैध निकासी की गई। अब तक सामने आई जांच और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस कथित ट्रेजरी घोटाले की शुरुआती परत सबसे पहले बोकारो जिले से खुली मानी जा रही है। शुरुआती जांच में मामला मुख्य रूप से झारखंड पुलिस के वेतन भुगतान और कोषागार निकासी से जुड़ा बताया गया था। बाद में हजारीबाग में भी इसी तरह की अनियमितताएं सामने आईं। इसके बाद जांच का दायरा बढ़ने पर रांची में पशुपालन विभाग से जुड़ी लगभग 3 करोड़ रुपये की संदिग्ध निकासी का मामला भी सामने आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, घोटाले का तरीका यह था कि सेवानिवृत्त या मृत कर्मचारियों के नाम पर फर्जी वेतन, एरियर और अन्य भुगतान दिखाकर राशि निकाली जाती रही। जांच एजेंसियों को शक है कि यह खेल कई वर्षों से चल रहा था और इसमें वित्तीय प्रबंधन प्रणाली तथा ई-कुबेर व्यवस्था का दुरुपयोग किया गया है। जांच में घोटाले की मामले की शुरुआत बोकारो से होते हुए हजारीबाग, रांची, चाईबासा और पलामू समेत कई जिलों के नाम सामने आए हैं। आरोप है कि फर्जी भुगतान, डेटा में बदलाव और इंप्लॉयर मास्टर डेटाबेस में छेड़छाड़ कर सरकारी धन निजी खातों तक पहुंचाया गया। मामले की गंभीरता तब और बढ़ गई जब प्रधान महालेखाकार कार्यालय द्वारा वित्त विभाग को अनियमितताओं की जानकारी दिए जाने की बात सामने आई। इसके बाद राज्य सरकार ने सीआईडी की एसआईटी जांच शुरू कराई, कुछ प्राथमिकी दर्ज हुई और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई। लेकिन भाजपा का आरोप है कि कार्रवाई सिर्फ निचले स्तर के

कर्मचारियों तक सीमित रखी जा रही है, जबकि असली जिम्मेदारों तक जांच पहुंच ही नहीं रही।

❖ **भाजपा ने उठाए पांच बड़े सवाल :-**

☞ **जांच सिर्फ चुनिंदा जिलों तक क्यों? :-** भाजपा का पहला सवाल जांच के दायरे को लेकर है। पार्टी का कहना है कि जब रांची और चाईबासा जैसे जिलों में भी प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है और गिरफ्तारियां हुई हैं, तो फिर सीआईडी जांच को मुख्य रूप से बोकारो और हजारीबाग तक सीमित क्यों रखा गया है? विपक्ष का आरोप है कि सरकार जानबूझकर जांच का दायरा सीमित कर रही है ताकि बड़े अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों के नाम सामने न आएं। भाजपा का यह भी कहना है कि यदि कई जिलों में समान तरीके से अनियमितताएं हुई हैं, तो यह किसी "स्थानीय स्तर की गड़बड़ी" नहीं बल्कि राज्यव्यापी नेटवर्क का संकेत हो सकता है।

☞ **ई-कुबेर में छेड़छाड़ बिना ऊंचे स्तर की जानकारी कैसे? :-** भाजपा ने अपने पत्र में सबसे गंभीर सवाल ई-कुबेर प्रणाली को लेकर उठाया है। पार्टी का कहना है कि भारतीय रिजर्व बैंक से जुड़ी इस डिजिटल वित्तीय प्रणाली में बदलाव या फर्जी प्रविष्टियां बिना उच्च स्तर की प्रशासनिक जानकारी के संभव नहीं हो सकतीं। भाजपा ने पूछा है कि अब तक कितने डीडीओ, ट्रेजरी अधिकारियों, वित्तीय पदाधिकारियों और आईटी सिस्टम से जुड़े कर्मचारियों से पूछताछ हुई है। यदि इंप्लॉयर मास्टर डेटाबेस में बदलाव किए गए, तो संबंधित विभागों और निगरानी एजेंसियों को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? यह सवाल इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि ई-कुबेर जैसी प्रणाली में हर भुगतान का डिजिटल रिकॉर्ड होता है और कई स्तर की स्वीकृति प्रक्रिया शामिल रहती है।

☞ **ऑडिट सिस्टम आखिर करता क्या रहा? :-** भाजपा ने सरकार के ऑडिट और मॉनिटरिंग सिस्टम पर भी तीखा हमला बोला है। विपक्ष का कहना है कि यदि वर्षों तक करोड़ों रुपये की गड़बड़ी होती रही, तो इसका मतलब है कि वित्तीय निगरानी तंत्र या तो पूरी तरह विफल रहा या फिर जानबूझकर आंखें मूंदे रखा गया। भाजपा ने पूछा है कि पिछले छह वर्षों में कितनी बार ट्रेजरी ऑडिट हुआ, कितनी अनियमितताएं पकड़ी गईं और उन पर क्या कार्रवाई हुई। पार्टी ने JAP-IT और लेखा निदेशालय की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष का आरोप है कि जिन संस्थाओं पर सरकारी भुगतान और डेटा की निगरानी की जिम्मेदारी थी, उन्हीं की भूमिका अब संदेह के घेरे में है।

☞ **जांच समितियों की समयसीमा क्या है? :-** इस पूरे मामले में एक ओर सीआईडी एसआईटी जांच कर रही है, वहीं दूसरी ओर वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में गठित समिति भी वित्तीय लेन-देन की समीक्षा कर रही है। भाजपा ने सरकार से पूछा है कि दोनों एजेंसियों को रिपोर्ट सौंपने की क्या समय सीमा दी गई है। साथ ही 2020 से 2026 तक के सभी ट्रेजरी रिकॉर्ड और भुगतान विवरण कब तक सार्वजनिक किए जाएंगे। भाजपा का कहना है कि यदि सरकार पारदर्शिता को लेकर गंभीर

है, तो जांच की प्रगति और समय सीमा स्पष्ट रूप से सार्वजनिक की जानी चाहिए।

☞ **ट्रेजरी निरीक्षण की जिम्मेदारी किसने निभाई? :-** ट्रेजरी कोड के अनुसार उपायुक्तों को समय-समय पर ट्रेजरी और सब-ट्रेजरी का निरीक्षण करना होता है। भाजपा ने सवाल उठाया कि पिछले छह वर्षों में कितने जिलों में नियमित निरीक्षण हुआ और उसकी रिपोर्ट क्या कहती है। विपक्ष का दावा है कि यदि निरीक्षण व्यवस्था सही तरीके से लागू होती, तो इतनी बड़ी वित्तीय अनियमितता लंबे समय तक छिपी नहीं रह सकती थी। भाजपा ने इसे प्रशासनिक लापरवाही ही नहीं, बल्कि "सिस्टमेटिक फेल्योर" बताया है।

❖ **श्वेत पत्र जारी करे सरकार :-** विभिन्न समाचार पत्र के माध्यम से डेढ़ सौ से 1000 करोड़ कि अवैध निकासी का मामला सामने आया है, भाजपा ने सरकार से मांग की है कि पूरे मामले पर श्वेत पत्र जारी किया जाए। पार्टी चाहती है कि सरकार स्पष्ट करे कि किन जिलों में कितनी राशि की अवैध निकासी की पुष्टि हुई है और अब तक कितनी रकम की जांच चल रही है। भाजपा नेताओं का दावा है कि अलग-अलग माध्यमों से डेढ़ सौ करोड़ से लेकर एक हजार करोड़ रुपये तक की वित्तीय गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में सरकार को आधिकारिक स्थिति सार्वजनिक करनी चाहिए ताकि अफवाहों और राजनीतिक आरोपों पर विराम लग सके।

❖ **सत्ता पक्ष का बचाव :-** हालांकि सरकार का कहना है कि मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से चल रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सत्ता पक्ष के नेताओं का तर्क है कि जैसे-जैसे तथ्य सामने आ रहे हैं, कार्रवाई भी की जा रही है। सरकार यह भी कह रही है कि तकनीकी और वित्तीय स्तर पर पूरे सिस्टम की जांच की जा रही है तथा दोषी चाहे किसी भी स्तर के हों, उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन विपक्ष इस दावे से संतुष्ट नहीं दिख रहा।

❖ **राजनीतिक असर भी गहरा :-** ट्रेजरी घोटाले का असर अब केवल प्रशासनिक या कानूनी दायरे तक सीमित नहीं है। यह मुद्दा तेजी से राजनीतिक रूप ले चुका है। भाजपा इसे सरकार की प्रशासनिक विफलता और भ्रष्टाचार के प्रतीक के रूप में पेश कर रही है, जबकि सत्ता पक्ष विपक्ष पर राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि जांच में बड़े अधिकारियों या राजनीतिक संरक्षण की बात सामने आती है, तो यह मामला आने वाले समय में झारखंड की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है।

❖ **सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी :-** फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह मामला कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत तक सीमित है, या फिर राज्य की वित्तीय व्यवस्था में लंबे समय से सक्रिय किसी बड़े नेटवर्क की कहानी धीरे-धीरे सामने आ रही है? सीआईडी जांच, संभावित सीबीआई जांच की मांग और लगातार बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच अब सबकी नजर सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी है। आने वाले दिनों में जांच की दिशा ही तय करेगी कि यह मामला सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी बनकर रह जाएगा या झारखंड के सबसे बड़े वित्तीय घोटालों में दर्ज होगा।●

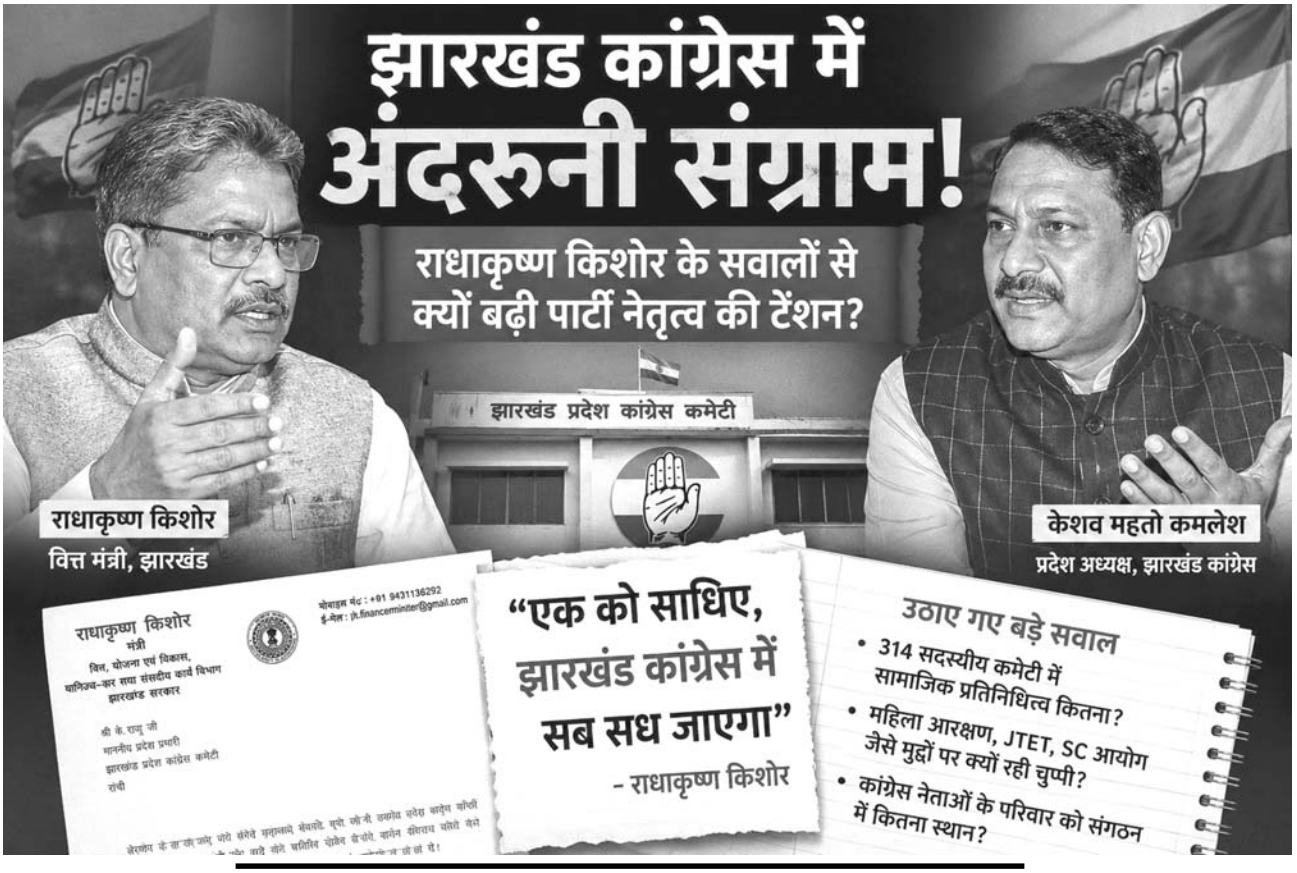

● **भारती मिश्रा**

झारखंड की राजनीति अभी एक अलग ही दिशा में जा रही जहां सत्ताधारी पार्टी आपस में ही एक दूसरे के कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है। और विपक्ष को सवाल उठाने का मौका दे रही है। कुछ दिन पहले महागठबंधन वाली सरकार में सभी पार्टी एक दूसरे के आमने सामने नजर आ रहे थी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था। अब झारखंड कांग्रेस इन दिनों अपने ही नेताओं के बयान और पत्रों की वजह से चर्चा में है, कुछ दिन पहले बड़कागांव की पूर्व विधायक एवं कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव अंबा प्रसाद और पूर्व मंत्री योगेंद्र साव अपने पार्टी और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आए तो वही अब राज्य के वित्त मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राधा कृष्ण किशोर ने जिस तरह लगातार प्रदेश नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं, उससे साफ हो गया है कि पार्टी के भीतर सबकुछ सामान्य नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश द्वारा बनाई गई 314 सदस्यीय प्रदेश कमेटी के बाद यह विवाद और खुलकर सामने आया। राधाकृष्ण किशोर ने कांग्रेस प्रभारी के राजू को पत्र लिखकर संगठन की कार्यशैली, नेतृत्व की सक्रियता और सामाजिक प्रतिनिधित्व तक पर सवाल खड़े कर दिए। सबसे ज्यादा चर्चा उनकी उस पंक्ति की हो रही है जिसमें उन्होंने लिखा, "एक को साधिए, झारखंड कांग्रेस में सब सध जाएगा।"

राजनीतिक हलकों में इसे सीधे तौर पर प्रदेश अध्यक्ष पर निशाना माना जा रहा है। सिर्फ पद बांटने से संगठन नहीं चलता। राधाकृष्ण किशोर का सबसे बड़ा आरोप यह है कि कांग्रेस संगठन जनता के मुद्दों से दूर होता जा रहा है। उनका कहना है कि बड़ी-बड़ी कमेटियां बनाने से पार्टी मजबूत नहीं होती, बल्कि जमीन पर संघर्ष करने से संगठन खड़ा होता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा: "314 की जगह 628 सदस्य भी बना दीजिए तो क्या फर्क पड़ेगा?" उनका साफ संदेश था कि अगर पार्टी राज्य के स्थानीय मुद्दों पर चुप रहेगी तो सिर्फ पद बांटने से कार्यकर्ता सक्रिय नहीं होंगे।

☞ **किन मुद्दों पर उठाए सवाल? :-** राधाकृष्ण किशोर कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के राजू को पत्र लिखा और अपने पत्र में कई ऐसे मुद्दे उठाए जिन पर उनके मुताबिक प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व पूरी तरह मौन रहा। पार्टी पर एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा लगाने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता का हवाला देते हुए जिस तरह से पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू को पार्टी से निकासित किया गया लेकिन रमा खलखो को पार्टी में उच्च पद दिया गया जबकि पूर्व में रमा खलखो ने भी पार्टी कार्य पर सवाल उठाए थे।

☞ **महिला आरक्षण पर भाजपा को नहीं घेर सकी कांग्रेस :-** उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने संसद में महिला आरक्षण बिल पर मजबूती से पक्ष रखा, लेकिन झारखंड कांग्रेस इसे राज्यव्यापी आंदोलन का रूप नहीं दे सकी। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने से महिलाओं तक संदेश नहीं पहुंचता।

☞ **JTET से मगही-भोजपुरी हटाने पर**

चुप्पी :- उन्होंने कहा कि पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, गोड्डा, धनबाद और बोकारो जैसे इलाकों में बड़ी संख्या में लोग मगही और भोजपुरी बोलते हैं। लेकिन श्रज्म्ज् से इन भाषाओं को हटाने पर प्रदेश कांग्रेस ने कोई बड़ा विरोध नहीं किया।

☞ **दलित मुद्दों पर भी सवाल :-** राधाकृष्ण किशोर ने याद दिलाया कि उन्होंने बजट भाषण में अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जाति परामर्शदात्री परिषद को फिर से सक्रिय करने की मांग की थी। उनका कहना है कि प्रदेश नेतृत्व ने इस मुद्दे पर भी कोई रुचि नहीं दिखाई। उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड में करीब 50 लाख अनुसूचित जाति की आबादी है, लेकिन संगठन में उनकी भागीदारी कितनी है, यह सार्वजनिक होना चाहिए।

☞ **हजारीबाग की घटनाओं पर भी नाराजगी :-** उन्होंने हजारीबाग के विष्णुगढ़ में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म और तीन अल्पसंख्यकों की हत्या का मामला भी उठाया। उनका सवाल था कि "ऐसे मामलों में प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व कहां था?" उनका कहना है कि स्थानीय नेता जरूर पहुंचे, लेकिन प्रदेश स्तर पर कोई मजबूत राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं दिखी।

☞ **परिवारवाद और सामाजिक संतुलन पर हमला :-** राधाकृष्ण किशोर ने सबसे तीखा सवाल संगठन में परिवारवाद को लेकर उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश नेतृत्व सार्वजनिक करे कि: कितने नेताओं के परिवार के लोगों को संगठन में जगह मिली? दरअसल नई कमिटी में एक ही परिवार के 2,3 लोगो रखा गया है। 314 सदस्यीय कमेटी में दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग को कितना प्रतिनिधित्व मिला? यह सवाल सीधे तौर पर संगठन के सामाजिक संतुलन पर उठाया गया सबसे बड़ा सवाल माना जा रहा है।

☞ **क्या यह खुली बगावत है? :-** राधाकृष्ण किशोर खुद इसे पार्टी विरोध नहीं मानते। उन्होंने साफ लिखा कि: "अगर पार्टी हित की बात सार्वजनिक रूप से कही जाए तो उसे पार्टी विरोधी नहीं कहा जा सकता।" उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी की विचारधारा के खिलाफ बोलना गलत है, लेकिन संगठन की कमियों की ओर ध्यान दिलाना जरूरी है। यानी वे खुद को "नाराज नेता" नहीं बल्कि "संगठन को सुधारने की कोशिश करने वाला नेता" बताने की कोशिश कर रहे हैं।

☞ **प्रभारी के. राजू का नरम रुख क्यों अहम? :-** इस पूरे मामले में कांग्रेस प्रभारी के. राजू का रुख भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उन्होंने राधाकृष्ण किशोर की बातों को पूरी तरह खारिज नहीं किया। उन्होंने कहा कि "वित्त मंत्री ने जो मुद्दे उठाए हैं, वे पार्टी हित के हैं।" हालांकि सार्वजनिक रूप से पत्र लिखने पर नाराजगी जाहिर की थी। यही वजह है कि अब 20 मई को झारखंड कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक बुलाई गई है। माना जा रहा है कि इसी बैठक में पूरे विवाद पर चर्चा होगी।

☞ **क्या केशव महतो कमलेश पर बढ़ रहा दबाव? :-** प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश फिलहाल सीधे टकराव से बचते दिख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि प्रभारी के निर्देश के बाद ही जवाब देंगे। लेकिन राजनीतिक जानकार मानते हैं कि: यदि सरकार के वरिष्ठ मंत्री सार्वजनिक रूप से सवाल उठा रहे हैं, और प्रभारी भी उन सवालों को पूरी तरह गलत नहीं बता रहे, तो यह प्रदेश नेतृत्व के लिए आसान स्थिति नहीं है।

☞ **क्या मामला राहुल गांधी तक पहुंचेगा? :-** झारखंड में कांग्रेस सरकार का हिस्सा है और पार्टी पहले ही कई राज्यों में कमजोर स्थिति से गुजर रही है। ऐसे में आलाकमान किसी बड़े विवाद को लंबा नहीं खींचना चाहेगा। इसी वजह से माना जा रहा है कि अगर विवाद नहीं सुलझा तो मामला सीधे राहुल गांधी तक पहुंच सकता है।

☞ **आखिर कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? :-** इस पूरे विवाद ने एक बात साफ कर दी है कि झारखंड कांग्रेस में केवल संगठन विस्तार नहीं, बल्कि नेतृत्व शैली और राजनीतिक सक्रियता को लेकर भी असंतोष है। एक तरफ प्रदेश नेतृत्व नई टीम बनाकर संगठन मजबूत करने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ राधाकृष्ण किशोर जैसे वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि पार्टी जनता के मुद्दों से कट रही है, संगठन में संतुलन नहीं है, और जमीन पर संघर्ष कमजोर पड़ रहा है। अब 20 मई की बैठक पर सबकी नजर है। क्योंकि यह बैठक सिर्फ संगठनात्मक चर्चा नहीं, बल्कि झारखंड कांग्रेस के अंदर शक्ति संतुलन तय करने वाली बैठक मानी जा रही है।●

अभी कलम उठाइये

आपके सामने हो रहे भ्रष्टाचार एवं अपराध की खबर की समीक्षा करें और सरकार सहित पुलिस-प्रशासन तक उसको पहुंचाने के लिए केवल सच पत्रिका के साथ जुड़े। खबर की जानकारी इस नम्बर पर दें

सम्पर्क करें:- 9431073769/8340360961

ई-मेल:- editor.kstimes@rediffmail.com पर भेजें।

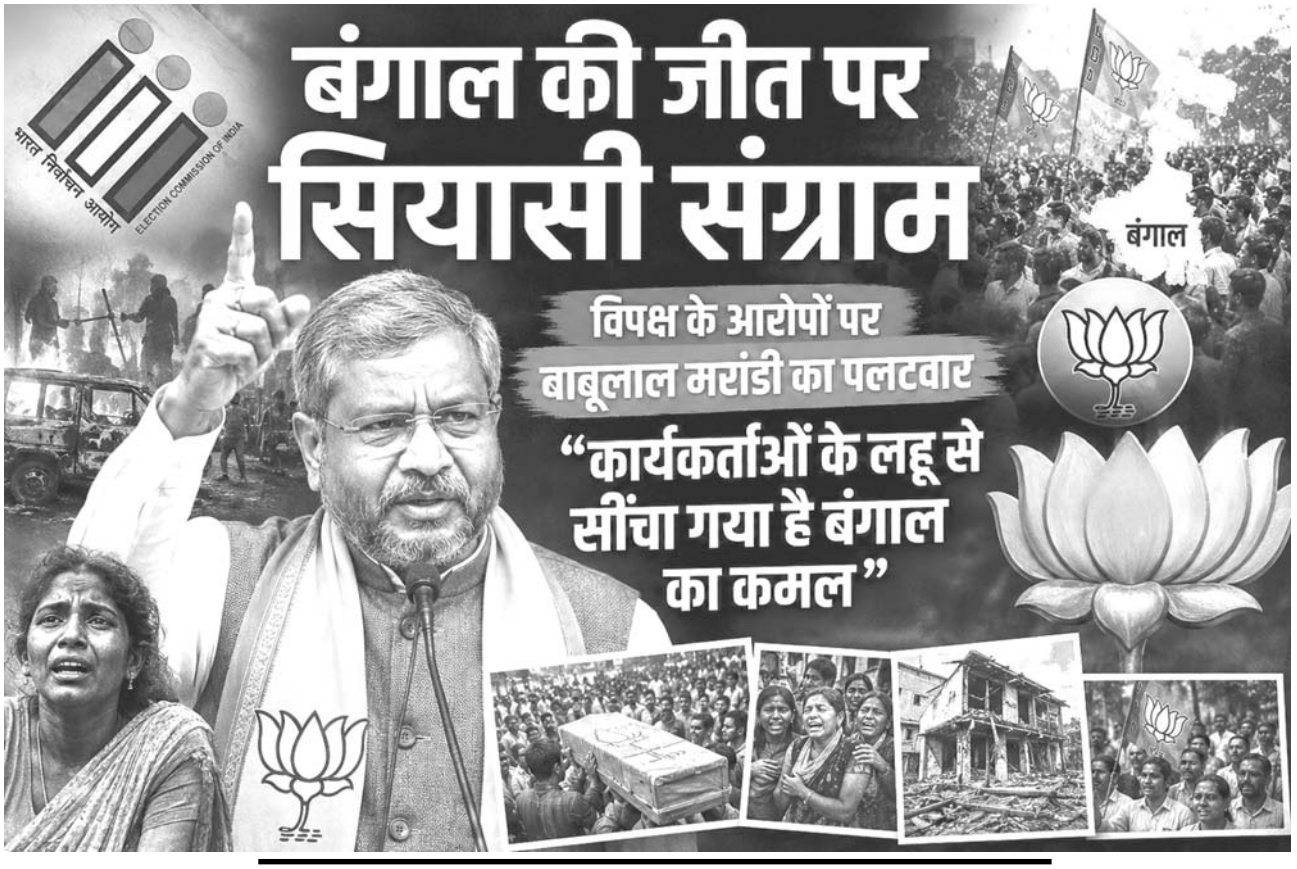

● **भारती मिश्रा**

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के परिणामों ने देश की राजनीति में नया भूचाल ला दिया है। पहली बार बंगाल की सत्ता में कमल खिलने पर भारतीय जनता पार्टी के हासिल करने के बाद जहां भाजपा इसे जनता के आत्मसम्मान और कार्यकर्ताओं के बलिदान की जीत बता रही है, वहीं विपक्षी दल चुनाव आयोग, केंद्रीय एजेंसियों और प्रशासनिक हस्तक्षेप और सहयोग का आरोप लगाकर परिणामों पर सवाल उठा रहे हैं। झारखंड की राजनीति में भी बंगाल के नतीजों की गूंज तेज है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और वामपंथी दलों के कई नेताओं ने भाजपा की जीत को लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल बताते हुए चुनाव आयोग की भूमिका पर संदेह जताया। विपक्ष का आरोप है कि केंद्रीय बलों की तैनाती, चुनावी रणनीति और संस्थागत दबाव के जरिए भाजपा ने बंगाल में बढ़त बनाई। ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ के भी लगाए आरोप। इन्हीं सब आरोपी का जवाब देते हुए झारखंड के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने विपक्ष के आरोपों पर तीखा पलटवार करते हुए लंबा राजनीतिक और भावनात्मक बयान जारी किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए अपने विस्तृत पोस्ट में उन्होंने कहा कि बंगाल में भाजपा की जीत किसी "चुनाव आयोग की मेहरबानी" नहीं, बल्कि "भाजपा कार्यकर्ताओं के लहू, संघर्ष और बलिदान" का परिणाम है।

❖ **बंगाल में कमल बैलेट बॉक्स से पहले खून से खिला :-** बाबूलाल मरांडी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए लिखा कि कुछ लोग अब भी इस भ्रम में जी रहे हैं कि भाजपा को बंगाल की सत्ता चुनाव आयोग के "गिफ्ट" के रूप में मिली है। उन्होंने कहा कि जो लोग म्टड, केंद्रीय बलों या दिल्ली के प्रभाव को भाजपा की जीत की वजह बता रहे हैं, वे बंगाल की राजनीतिक वास्तविकता से अनजान हैं। मरांडी ने कहा, "बंगाल में कमल बैलेट बॉक्स से पहले कार्यकर्ताओं के खून से खिला है।" उन्होंने दावा किया कि पिछले डेढ़ दशक में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हिंसा, राजनीतिक प्रताड़ना और दमन के बीच संघर्ष किया। मरांडी के अनुसार बंगाल में भाजपा का विस्तार केवल चुनावी रणनीति का परिणाम नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की लंबी तपस्या और बलिदान का नतीजा है।

❖ **लाशों का अंबार और जलते आशियाने :-** अपने पोस्ट के पहले हिस्से में बाबूलाल मरांडी ने 2011 से 2025 तक के बंगाल के राजनीतिक माहौल को "रक्तरंजित संघर्ष" करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा समर्थकों को केवल पार्टी से जुड़ने या वोट देने के कारण हिंसा का सामना करना पड़ा। उन्होंने नंदीग्राम, बीरभूम, कूच बिहार और बशीरहाट जैसे इलाकों का जिक्र करते हुए कहा कि कई गांवों में भाजपा समर्थकों के घर जलाए गए, कार्यकर्ताओं की हत्या हुई और महिलाओं को डराने के लिए उनकी अस्मिता तक को राजनीतिक हथियार बनाया गया। मरांडी ने कहा कि बंगाल में लोकतंत्र की बात करने वालों को पेड़ों से लटकाया गया, बम से उड़ाया गया और कई शव क्षत-विक्षत हालत में मिले। उन्होंने हाई कोर्ट की फटकार और ब्ठप् जांचों का हवाला देते हुए दावा किया कि यह सब "राजनीतिक हिंसा" की कहानी कहता है।

❖ **मौत भी जिसे डरा न सकी :-** अपने दूसरे हिस्से में बाबूलाल मरांडी ने भाजपा कार्यकर्ताओं के मनोबल का जिक्र करते हुए कई भावनात्मक उदाहरण दिए। उन्होंने लिखा कि बंगाल में ऐसे हालात भी बने जब किसी बूथ अध्यक्ष की हत्या के बाद उसी दिन उसका बेटा पोलिंग एजेंट बनकर खड़ा हो गया। मरांडी ने कहा "यह हिम्मत म्टड से नहीं, स्वाभिमान से आती है।" उन्होंने यह भी लिखा कि जिन महिलाओं के घर जला दिए गए, वे अगले दिन फिर भगवा झंडा लेकर सड़कों पर उतर आईं। मरांडी ने वामपंथी शासन के 34 वर्षों और तृणमूल कांग्रेस के 15

वर्षों को "दमन, तानाशाही और खौफनाक रक्तरंजित राजनीति" का दौर बताते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने फर्जी मुकदमे, जेल और सामाजिक बहिष्कार सब कुछ झेला, लेकिन पीछे नहीं हटे।

❖ **शून्य से शिखर तक का सफर** :- अपने पोस्ट के तीसरे भाग में बाबूलाल मरांडी ने बंगाल में भाजपा के राजनीतिक विस्तार को संघर्ष की कहानी बताया। उन्होंने 2011 से 2026 तक पार्टी की चुनावी यात्रा को क्रमवार रखते हुए कहा-

☞ 2011 में भाजपा केवल 1 सीट जीत सकी।

☞ 2016 में पार्टी 3 सीटों तक पहुंची।

☞ 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 18 सीटें जीतकर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया।

☞ 2021 विधानसभा चुनाव में 77 सीटें जीतकर भाजपा मुख्य विपक्ष बनी।

☞ 2024 में दमन के बावजूद पार्टी 12 सीटों पर कायम रही।

☞ 2026 में भाजपा ने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया।

मरांडी ने कहा कि यह आंकड़ों की राजनीति नहीं, बल्कि उन परिवारों के संघर्ष की कहानी है जिन्होंने अपनों को खोने के बावजूद लड़ाई जारी रखी। उन्होंने लिखा कि कई माताओं ने बेटों की "तेरहवीं" पर सत्ता परिवर्तन तक संघर्ष जारी रखने की कसम खाई थी।

❖ **यह गिफ्ट नहीं, शहीदों का बलिदान है** :- अपने अंतिम हिस्से में बाबूलाल मरांडी ने विपक्षी दलों पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग भाजपा की जीत को "सेटिंग" या "मेहरबानी" कह रहे हैं, वे उन श्मशानों और कब्रों में जाकर देखें जहां भाजपा का झंडा ओढ़े कार्यकर्ता सो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में हर वोट के पीछे एक शहादत छिपी है और यह जीत लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ने वाले कार्यकर्ताओं को समर्पित है। मरांडी के अनुसार "15 साल तक खून-पसीना बहाने, अपनों की लाशें ढोने और हर जुल्म सहने के बाद बंगाल की जनता ने बदलाव का फैसला किया है।"

❖ **झारखंड की राजनीति में भी गरमाया मुद्दा** :- बंगाल चुनाव के नतीजों ने झारखंड की राजनीति को भी प्रभावित किया है। भाजपा जहां इसे वैचारिक और संगठनात्मक जीत बता रही है, वहीं सत्ताधारी गठबंधन के नेता लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बंगाल का परिणाम केवल एक राज्य का चुनावी नतीजा नहीं, बल्कि पूर्वी भारत की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत है। झारखंड में भाजपा इसे कार्यकर्ताओं के मनोबल को मजबूत करने वाले संदेश के रूप में देख रही है, जबकि विपक्ष इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर बहस का मुद्दा बना रहा है। फिलहाल इतना तय है कि बंगाल की जीत केवल चुनावी आंकड़ों तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने संघर्ष, हिंसा, लोकतंत्र, संस्थाओं की भूमिका और राजनीतिक नैरेटिव को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर नई बहस छेड़ दी है।●

झारखण्ड में 'ब्लू इकोनॉमी' की नई शुरूआत

क्या मत्स्य क्रांति बदल देगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था?

● **भारती मिश्रा**

रांची के रातू में अत्याधुनिक मत्स्य परियोजना के द्वारा कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री नेहा शिल्पी तिर्की जिस तरह झारखंड को मत्स्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की प्रयास कर रही है, वह केवल एक सरकारी घोषणा नहीं बल्कि राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। झारखंड लंबे समय से खनिज आधारित अर्थव्यवस्था और कृषि पर निर्भर रहा है, लेकिन अब सरकार मत्स्य उत्पादन को रोजगार, स्वरोजगार और ग्रामीण विकास के बड़े माध्यम के रूप में विकसित करने की तैयारी में दिख रही है। खास बात यह है कि इस अभियान में पारंपरिक तालाब आधारित मछली पालन के बजाय बायोफ्लॉक, हैचरी, केज कल्चर और एकीकृत मत्स्य मॉडल जैसी आधुनिक तकनीकों को केंद्र में रखा जा रहा है।

☞ **युवाओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह पहल?** :- आज झारखंड का सबसे बड़ा सामाजिक-आर्थिक संकट बेरोजगारी और पलायन

है। बड़ी संख्या में युवा रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर जाते हैं। ऐसे समय में "किंग फिशरीज" जैसी परियोजनाएँ यह संकेत देती हैं कि यदि तकनीक और प्रशिक्षण मिले तो ग्रामीण क्षेत्र में भी आधुनिक उद्यम खड़े किए जा सकते हैं। बायोफ्लॉक तकनीक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कम जगह और सीमित पानी में भी बड़े स्तर पर मछली उत्पादन संभव है। इसका मतलब यह हुआ कि छोटे किसान, बेरोजगार युवा और स्वरोजगार की तलाश कर रहे लोग कम लागत में व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। सरकार द्वारा बायोफ्लॉक तालाब योजना और वित्तीय सहायता की घोषणा से युवाओं के लिए नए अवसर खुल सकते हैं। यदि प्रशिक्षण, बैंक ऋण और बाजार की व्यवस्था सही ढंग से लागू हुई तो मत्स्य पालन केवल पारंपरिक पेशा न रहकर "स्टार्टअप मॉडल" के रूप में उभर सकता है।

☞ **राज्य को क्या होगा फायदा?** :- झारखंड

आज भी अपनी आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त मछली उत्पादन नहीं कर पाता, जिसके कारण दूसरे राज्यों से मछलियों की आपूर्ति करनी पड़ती है। इससे राज्य का बड़ा आर्थिक संसाधन बाहर चला जाता है। यदि राज्य सरकार का आत्मनिर्भरता मॉडल सफल होता है, तो झारखंड न केवल अपनी जरूरत पूरी करेगा बल्कि दूसरे राज्यों को भी मछली आपूर्ति करने की स्थिति में आ सकता है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और स्थानीय बाजारों में नकदी प्रवाह बढ़ेगा। सरकार के अनुसार राज्य में वर्ष 2025-26 में मत्स्य उत्पादन 3.81 लाख मीट्रिक टन तक पहुँच चुका है और पिछले कुछ वर्षों में 40 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। यह आँकड़ा बताता है कि यदि योजनाओं का विस्तार हुआ तो मत्स्य क्षेत्र झारखंड की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

☞ **केज कल्चर और आधुनिक तकनीक का प्रभाव** :- चांडिल, मैथन, तेनुघाट, कोनार, मसानजोर और तिलैया जैसे बड़े जलाशयों में केज कल्चर मॉडल का प्रयोग राज्य के लिए गेमचेंजर साबित हो सकता है। इससे जलाशयों का व्यावसायिक उपयोग बढ़ेगा और स्थानीय लोगों को बड़े स्तर पर रोजगार मिलेगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि मत्स्य उत्पादन को प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज और मार्केटिंग से जोड़ा जाए तो यह केवल खेती आधारित गतिविधि न रहकर एक पूर्ण उद्योग का रूप ले सकता है।

☞ **चुनौतियाँ भी कम नहीं** :- हालांकि योजनाएँ आकर्षक दिखती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कई चुनौतियाँ मौजूद हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी जानकारी की कमी, बैंक ऋण प्राप्त करने में कठिनाई, बाजार और कोल्ड स्टोरेज का अभाव, प्रशिक्षण और मॉनिटरिंग की सीमित व्यवस्था, छोटे मत्स्य पालकों तक योजनाओं की जानकारी न पहुँचना, यदि इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो कई योजनाएँ कागजों तक सीमित रह सकती हैं।

☞ **क्या झारखंड "फिश हब" बन सकता है?** :- झारखंड में जल संसाधनों की कमी नहीं है। राज्य में बड़ी संख्या में तालाब, जलाशय और नदियाँ मौजूद हैं। यदि सरकार, तकनीक और युवाओं की भागीदारी एक साथ काम करती है, तो आने वाले वर्षों में झारखंड पूर्वी भारत के बड़े मत्स्य उत्पादक राज्यों में शामिल हो सकता है। रातू की यह परियोजना केवल एक निरीक्षण कार्यक्रम नहीं बल्कि इस संकेत के रूप में देखी जा रही है कि झारखंड अब कृषि के साथ-साथ "ब्लू इकोनॉमी" की ओर भी तेजी से बढ़ना चाहता है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार की घोषणाएँ जमीनी बदलाव में कितनी सफल होती हैं और क्या वास्तव में यह पहल युवाओं के पलायन को रोककर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ताकत दे पाएगी।●

कांग्रेस के निशाने पर आए मंत्री राधाकृष्ण किशोर

● गुड्डी साव

झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के कामकाज, संगठन और सरकार पर सीधा प्रहार कर पार्टी के निशाने पर आ गए हैं. वित्त मंत्री ने लगातार तीसरे दिन पत्र के माध्यम से अपनी नाराजगी जाहिर की है. इस नाराजगी के मायने क्या हैं, आगे क्या कार्रवाई हो सकती है. यह जानना जरूरी है.

वित्त मंत्री की बातें अपनी जगह पर सही हो सकती हैं, पर सार्वजनिक रूप से पार्टी और सरकार की आलोचना कर वह निशाने पर आ गए हैं. पार्टी के अंदर विरोध शुरू हो गया है. कई लोग प्रदेश अध्यक्ष के पक्ष में आ चुके हैं और मंत्री के बयान को अनुचित और दबाव

की राजनीति बता रहे हैं. पूरे प्रकरण पर कांग्रेस प्रभारी के राजू भी नाराज बताए जा रहे हैं. उन्होंने पूरी रिपोर्ट मांगी है. बात ऊपर तक पहुंच चुकी है. कुछ लोग तो इसी बहाने उन्हें मंत्रिमंडल से हटाने की मांग भी कर रहे हैं. संभव है देर- सबेर उनकी छुट्टी भी हो जाए. इधर वित्त मंत्री भी राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं.यदि उन्होंने सार्वजनिक रूप से प्रदेश अध्यक्ष पर निशाना साधा है तो इसके पीछे भी राजनीति और रणनीति होगी. यूं ही वह कुछ नहीं बोलते हैं. गंभीर राजनीतिज्ञ हैं. इसके भी अपने मायने हैं.

कांग्रेस सूत्रों की माने तो वित्त मंत्री की नाराजगी दो बातों को लेकर अधिक है. वित्त मंत्री अपने बेटे प्रशांत किशोर को राजनीति में लाना चाहते हैं. यह इसलिए कि अब वह विराम लेने वाले हैं, इसलिए बेटे को आगे कर रहे हैं. अगला चुनाव बेटा ही लड़ेगा. वह चाहते थे कि प्रदेश कमेटी में उनके बेटे प्रशांत किशोर को महासचिव बनाया जाए लेकिन उनके बेटे को प्रदेश सचिव बनाया गया. इससे वह नाराज हो गए. उन्होंने बेटे से इस्तीफा दिलवा दिया।●

ऑनलाइन पोर्टल का मंत्री ने किया शुभारंभ

● गुड्डी साव

रांची नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन से झारखंड अनाधिकृत निर्मित भवन नियमितीकरण नियमावली, 2026 के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया ।इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक क्षण है जहाँ राज्य की जनता को एक मौका प्रदान किया जा रहा है कि वे अनाधिकृत तरीके से बने अपने मकानों का नियमितीकरण करा सकेंगे । जो लोग चिंतित थे कि उनके अनियमित मकानों का क्या होगा सरकार इस दिशा में राहत देते हुए भवन नियमितीकरण योजना ले कर आई है। अब लोग पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर अपना मकान नियमित करा सकेंगे।

सुदिव्य कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की प्रबल इच्छाशक्ति थी कि राज्य के लोगों को राहत देते हुए अनियमित मकानों को नियमितीकरण करने का एक मौका जरूर दिया जाना चाहिए। इसी के मद्देनजर नगर विकास विभाग ने बड़े कठिन और अथक प्रयासों के बाद यह योजना तैयार हुई है और अब ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ हो गया है। लोग अब पोर्टल के माध्यम से अपने मकानों के नियमितीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और अपने मकानों को नियमित करा सकेंगे । उन्होंने कहा कि राज्य की जनता का समर्थन और सहयोग जरूरी है ताकि इस योजना को सफल बनाया जा सके।

मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि सरकार की नीतियों का अनुपालन में जनता की भागीदारी महत्वपूर्ण है। भवन नियमितीकरण का उद्देश्य अनियमितीकरण को बढ़ावा देना नहीं है बल्कि जो लोग बिना नक्शा और मास्टर प्लान के अपना मकान बना लिए है ये उन लोगों के लिए एक मौका है। सरकार ने नियमितीकरण नियमावली को बहुत ही सरल और लिबरल बनाया है और नियमित करने में लगने वाली राशि को भी तीन किस्तों में भुगतान का प्रावधान कर लोगों को राहत देने का काम किया है । इसके उद्देश्य को पूरा करना हम सब की जवाबदेही है।

प्रधान सचिव सुनील कुमार ने कहा कि सरकार नगरीय क्षेत्रों के विकास को गंभीरता से ले रही है। शहर की सूरत बदल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जा रहा है। रांची में 3 फ्लाइओवर बन कर तैयार हैं, सिरमटोली कनेक्टिंग फ्लाइओवर भी ऑनगोइंग है । अरगोड़ा, करमटोली और हरमू 3 नए फ्लाइओवर की स्वीकृति मिल चुकी है। जमशेदपुर और धनबाद में भी फ्लाईओवर बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन का निदेश है कि शहरीकरण अव्यवस्थित ढंग से ना हो। रोड, फुटपाथ, टाउनहॉल, नाली सभी व्यवस्थित हों। शहरों में उन्नत बस स्टैंड हो। इस दिशा में काम जारी है। म्युनिसिपल के रेवन्यू बढ़ाने पर भी फोकस है। मानव संसाधन पर भी जोर दिया जा रहा है। टाउन प्लानर, इंजीनियर आदि की नियुक्ति सरकार ने की है। उन्होंने कहा कि भवन नियमितीकरण नियमावली 2026 को हम योजना कह सकते हैं। इससे लोगों को एक बार मौका दिया जा रहा है कि वे अपने मकानों को नियमित करा सकेंगे। उन्होंने इसकी प्रक्रिया की जानकारी दी। कहा कि इसके शुभारंभ से लेकर 2 माह के अंदर ऑनलाइन आवेदन करना है और 6 माह के अंदर नियमितीकरण का निर्णय लिया जा सकेगा ।साथ ही G+2 और

300 वर्गमीटर से कम में बने मकानों का ही नियमितीकरण होगा।

श्री सूरज कुमार डायरेक्टर सूडा ने कहा कि भवन नियमितीकरण नियमावली -2026 सरकार का ऐतिहासिक कदम है । किसी कारण से लोगों ने अपने मकान को बिना नक्शा पास कराए बना लिया है, ऐसे अनाधिकृत रूप से बने भवन का नियमतीकरण का निर्णय सरकार ने लिया है ताकि झारखंड के नागरिकों को राहत पहुंचाई जाय।भवन नियमितीकरण योजना का लाभ सभी लोग उठायें। झारखंड अनाधिकृत निर्मित भवन नियमितीकरण नियमावली, 2026 का लाभ लेने के लिए पोर्टल का शुभारंभ हो गया है। इस पोर्टल में जाकर ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन के लिए 2 माह का समय है। राशि का भुगतान भी किस्तों में कर सकेंगे। सरकार ने लोगों को राहत देने के उद्देश्य से ऐसा प्रावधान किया है।●

मुख्यमंत्री हेमन्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरीये की बैठक

● गुड्डी साव

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के वरीय पदाधिकारियों एवं सभी उपायुक्तों के साथ बैठक कर भीषण गर्मी तथा बढ़ते तापमान की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उन्होंने पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य सेवाओं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक निगरानी को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्मी के इस मौसम में आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो, यह जिला प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए कि अपने. अपने जिलों में पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें, ताकि किसी भी क्षेत्र में जल. संकट की स्थिति उत्पन्न न हो। जलापूर्ति योजनाओं, चापाकलों, टैंकरों और अन्य वैकल्पिक जल. स्रोतों की नियमित निगरानी की जाए तथा जहां भी समस्या की सूचना मिले, वहां त्वरित कार्रवाई की जाए।

मुख्यमंत्री ने बिजली आपूर्ति व्यवस्था की भी समीक्षा करते हुए कहा कि गर्मी के दौरान निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिए कि जिला प्रशासन संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर बिजली कटौती, ट्रांसफॉर्मर की खराबी तथा आपूर्ति बाधित होने जैसी शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करे। स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में मुख्यमंत्री ने सभी जिलों को विशेष सतर्कता बरतने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा अन्य चिकित्सा संस्थानों में हीटवेव और लू से प्रभावित लोगों के उपचार की समुचित व्यवस्था रहे। आवश्यक दवाइयों, ओ. आर.एस., पेयजल, चिकित्सा उपकरणों और स्वास्थ्यकर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण करें और जमीनी स्तर पर व्यवस्थाओं का भौतिक निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपने भ्रमण की जानकारी मुख्यालय को साझा करें, जहां भी जाएं, वहां की तस्वीरें भी भेजें। साथ ही, स्थानीय लोगों से अनिवार्य रूप से मिलकर उनकी समस्याएं सुनें। उन्होंने कहा कि जनता से सीधा संवाद प्रशासनिक जवाबदेही को मजबूत करता है और समस्याओं के त्वरित समाधान में सहायक होता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्मी की इस स्थिति में प्रशासनिक तत्परता, सतत निगरानी और मानवीय संवेदनशीलता अत्यंत आवश्यक है। सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और यह सुनिश्चित करें कि किसी भी नागरिक को पानी, बिजली या स्वास्थ्य. सुविधाओं के अभाव में कठिनाई का सामना न करना पड़े। बैठक में विभिन्न जिलों की स्थिति की समीक्षा की गई और अधिकारियों को आवश्यकतानुसार त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि सभी उपायुक्त राज्य सरकार के निर्देशों का गंभीरता से अनुपालन करते हुए आवश्यक राहत एवं देय सुविधाओं को प्रभावी रूप से प्रबंधित करेंगे।●

मजबूत संगठन ही सफल कार्य का आधार है : रवींद्रनाथ महतो

केंद्रीय कमिटी के निर्देशानुसार 7 मई को नाला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नाला प्रखंड के खैरा (सिधो-कान्हु) भवन में संगठनात्मक बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्य रूप से नाला विधानसभा के झामुमो विधायक रवीन्द्रनाथ महतो उपस्थित रहे। उक्त कार्यक्रम में नाला प्रखंड के 9 पंचायतों के 144 बूथ में बूथ कमेटी बनाने पर मुख्य रूप से चर्चा हुई। उक्त बुथ कमेटी में 15 पुरुष और 10 महिला सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य है, साथ ही बैठक में संगठन विस्तार, आगामी कार्यक्रमों की रणनीति एवं जनसेवा कार्यों को और प्रभावी बनाने पर विस्तृत चर्चा हुई। मौके पर समस्त कार्यकर्ताओं ने सक्रिय सहभागिता करते हुए संगठन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प लिया।● **रिपोर्ट :-गुड्डी साव**

तीन राज्यों में जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न

● गुड्डी साव

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में पार्टी की ऐतिहासिक विजय पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि अब अँधेरा छंट चुका है और भगवामय सूरज का उदय हुआ है। उन्होंने समस्त देशवासियों, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं एवं सम्मानित मतदाताओं को इस शानदार जीत के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने कहा कि यह जीत केवल चुनावी परिणाम नहीं, बल्कि जनता के अटूट विश्वास, कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में विकास और सुशासन की राजनीति पर मुहर लगी है। आदित्य साहू ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल सरकार के 15 वर्षों के कुशासन का अंत हो गया है। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता लंबे समय से तृणमूल सरकार की नीतियों से त्रस्त थी। उन्होंने कहा कि घुसपैठ को बढ़ावा देने, तुष्टिकरण की राजनीति को चरम पर पहुँचाने और भ्रष्टाचार के कारण पूरी व्यवस्था प्रभावित हुई थी। साथ ही, कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि अपराध और अराजकता के माहौल से जनता परेशान थी, आज उसका अंत हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि आज बंगाल की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से इन सभी स्थितियों का जवाब देते हुए बदलाव का मार्ग चुना है और एक नई दिशा की शुरुआत की है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में पार्टी की ऐतिहासिक विजय पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि यह जीत संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत का प्रत्यक्ष प्रमाण है। उन्होंने कहा कि यह विजय केवल चुनावी सफलता नहीं, बल्कि जनता के अटूट विश्वास और विकास व सुशासन की राजनीति के प्रति समर्थन का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में जो जनकल्याणकारी योजनाएँ और विकास कार्य हुए हैं, उसी पर जनता ने अपनी मुहर लगाई है। भाजपा की असली ताकत उसका समर्पित कार्यकर्ता और बूथ स्तर तक मजबूत संगठन है। जब कार्यकर्ता पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ मैदान में उतरते हैं, तब ऐसे ऐतिहासिक परिणाम सामने आते हैं। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस प्रचंड जनादेश के लिए पश्चिम बंगाल की जागरूक जनता-जनार्दन को नमन और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक समर्पित कार्यकर्ता का हार्दिक अभिनंदन किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह के कुशल नेतृत्व में बंगाल में पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। यह जनसमर्थन सुशासन, सुरक्षा और सर्वांगीण विकास के प्रति जनता के अटूट विश्वास का प्रतीक है। तीनों राज्यों में मिली जीत अभूतपूर्व है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में मिली जीत कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम और उनके वर्षों के संघर्ष का परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं ने जिस निष्ठा, समर्पण और सेवा भाव के साथ जनता के बीच काम किया है, यह जीत उसी का प्रमाण है। यह जनादेश हमें और अधिक जिम्मेदारी के साथ जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की प्रेरणा देता है। तीनों राज्यों में मिली इस ऐतिहासिक जीत के लिए सभी कार्यकर्ताओं को बधाई।●

जनगणना-2027 के तहत स्व-गणना की प्रक्रिया पूरी

● गुड्डी साव

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने 1 मई को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में जनगणना-2027 के तहत स्व-गणना की प्रक्रिया पूरी की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने समस्त झारखंड वासियों से जनगणना-2027 की प्रक्रिया में अपनी महती जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए सक्रिय एवं उत्साहपूर्ण भागीदारी की अपील की। मौके पर मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की धर्मपत्नी विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन भी उपस्थित रहीं। इस दौरान मुख्यमंत्री को जनगणना से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों ने ऑनलाइन स्व-गणना पोर्टल पर पंजीकरण करने से संबंधित प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी से अवगत कराया। मुख्यमंत्री के समक्ष जनगणना अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि इस अभियान के तहत 01 मई से 15 मई तक स्व-गणना कार्य प्रारंभ हो चुका है। इसके पश्चात मकान सूचीकरण एवं मकान गणना कार्य दिनांक 16 मई से 14 जून 2026 तक पूरे राज्य में किया जाएगा। इस गहन जनगणना अभियान के दौरान घर-घर जाकर प्रगणक से संबद्ध कर्मी डेटा संग्रह करेंगे। सभी जिलों में इस कार्य के लिए प्रशासनिक तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि जनगणना कार्य सिर्फ आंकड़े जुटाना नहीं बल्कि आमजनों के भविष्य को सही दिशा देने का आधार है। जनगणना से राज्य सरकार की योजनाओं को और ज्यादा प्रभावी तरीके से पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने इस कार्य के दौरान क्षेत्रीय भाषाओं के जानकार पदाधिकारी एवं कर्मियों को सम्मिलित किए जाने की बात जनगणना अधिकारियों से कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना-2027 का कार्य तकनीकी रूप से सराहनीय पहल है। मुख्यमंत्री ने समस्त राज्य वासियों से इस राष्ट्रीय जनगणना अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया।●

हाईजेनिक फिश मार्केट का मंत्री ने किया निरीक्षण

● गुड्डी साव

मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने 5 मई को राजधानी रांची के धुर्वा स्थित शालिमार बाजार में झास्को फिश द्वारा संचालित हाईजेनिक फिश मार्केट एवं फिश फीड मिल का औचक निरीक्षण किया। यह बाजार रांची सहित आसपास के क्षेत्रों के मत्स्य उपभोक्ताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां प्रतिदिन बड़ी मात्रा में ताजी मछलियों की आपूर्ति होती है। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने पाया कि बाजार से उपभोक्ताओं को लाभ तो मिल रहा है, किंतु व्यवस्थाओं में कई सुधार की आवश्यकता है। अव्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को 10 दिनों के भीतर सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के स्पष्ट निर्देश दिए। मंत्री ने संचालन प्रणाली को अधिक पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाने के लिए एक स्पष्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार करने का निर्देश दिया। इसमें विशेष रूप से रेंटल एग्रीमेंट, किराया निर्धारण तथा दुकानदारों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने को कहा गया। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि झारखंड के प्रत्येक जिले में इस प्रकार के आधुनिक एवं सुव्यवस्थित मत्स्य बाजार विकसित किए जाएं, ताकि मत्स्य किसानों और उपभोक्ताओंख्रदोनों को सीधा लाभ मिल सके। साथ ही, प्रत्येक जिले में मत्स्य पालन से जुड़े किसानों के लिए प्रशिक्षण केंद्र (Training Centres) स्थापित करने हेतु अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस बाजार में प्रतिदिन लगभग 6 मीट्रिक टन मछलियों की आपूर्ति होती है, जो गेतलसूद, चांडिल, कोनार, मैथन, पंचेत एवं मसानजोर जैसे प्रमुख जलाशयों से लाई जाती है और यहां से विभिन्न बाजारों में वितरित की जाती है। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने परिसर की साफ-सफाई, रख-रखाव और स्वच्छता मानकों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। साथ ही, बाजार परिसर में संचालित फिश फीड मिल की आपूर्ति एवं वितरण का पूर्ण और अद्यतन लेखा-जोखा प्रस्तुत करने को कहा। मंत्री ने मत्स्य प्रशिक्षण में भाग ले रहे किसानों से भी संवाद किया। किसानों ने बताया कि आगामी 15 से 30 दिनों में फिश फीड की मांग में वृद्धि होने की संभावना है। इस पर मंत्री ने मत्स्य निदेशक को निर्देशित किया कि सभी जिलों से तत्काल मांग का आकलन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें, ताकि समय पर किसानों को आवश्यक फिश फीड उपलब्ध कराई जा सके। अंत में मंत्री ने सभी अधिकारियों को कड़ा निर्देश देते हुए कहा कि कर्तव्य के प्रति लापरवाही किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कार्यों में जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।●

धुमकुड़िया भवन के निर्माण कार्य का हुआ शिलान्यास

खिजरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नामकुम प्रखंड के दिसिकिली (राजा उलातु) में धुमकुड़िया भवन के निर्माण कार्य का शुभ शिलान्यास संपन्न हुआ। इस अवसर पर खिजरी विधायक राजेश कच्छप संग मंत्री चमरा लिंडा की भी उपस्थिति रही। मंत्री ने उपस्थित जनसमूह को 'आदिवासीयत' की गहराई और अपनी जड़ों से जुड़े रहने का एक बेहद प्रेरणादायक संदेश दिया। विधायक राजेश कच्छप ने कहा की धुमकुड़िया केवल एक भवन नहीं, बल्कि हमारी भाषा, संस्कृति और परंपराओं को जीवंत रखने का मंदिर है। हमारा प्रयास है कि विकास के साथ-साथ हमारी गौरवशाली जनजातीय पहचान और भी सशक्त हो। सभी क्षेत्रवासियों को बहुत-बहुत बधाई। **रिपोर्ट :- गुड्डी साव**

अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर सीसीएल में भव्य समारोह का आयोजन

● **गुड्डी साव**

अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, रांची स्थित मुख्यालय के गंगोत्री कन्वेंशन सेंटर के संगम सभागार में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दरभंगा हाउस परिसर स्थित शहीद स्मारक पर वीर शहीद कोल कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हुई। सीसीएल के सीएमडी निलेंदु कुमार सिंह के नेतृत्व में निदेशकगण पवन कुमार मिश्रा हर्ष नाथ मिश्र, चंद्र शेखर तिवारी, अनुप हंजुरा, पंकज कुमार, क्षेत्रीय महाप्रबंधकों, मुख्यालय के महाप्रबंधक, विभागाध्यक्ष, अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने शहीदों को नमन करते हुए उनके योगदान को स्मरण किया। निलेंदु कुमार सिंह, सीएमडी, सीसीएल ने नवनिर्मित वर्किंग वॉशरी मॉडल का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने वॉशरी मॉडल से सम्बंधित कई प्रश्न किए और जानकारियां भी साझा की। इसके पश्चात सभी ने अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस थीम पर बने एक सेल्फी पॉइंट पर समूह चित्र भी खिंचवाया, जो आकर्षण का केंद्र बना रहा। उपस्थित लोगों ने उत्साहपूर्वक इसमें भाग लेते हुए यादगार तस्वीरें खिंचवाई। इसके पश्चात सीसीएल सभागार में सीआईएल कॉरपोरेट गीत के साथ दीप प्रज्वलन कर मुख्य कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें सभी श्रमिक संगठन के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। अपने संबोधन में सीएमडी निलेंदु कुमार सिंह ने सभी कर्मियों को श्रमिक दिवस की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि जब हम वातानुकूलित सभागार में कार्यक्रम कर रहे हैं, उसी समय हमारे कोल योद्धा खदानों में कार्यरत हैं और देश की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कठिन परिस्थितियों में भी अपना योगदान दे रहे हैं, उन्हें मेरा सादर प्रणाम। उन्होंने जानकारी दी कि बी एंड के, बरका-सयाल एवं अरगडा क्षेत्र ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक सर्वाधिक उत्पादन दर्ज किया है। इसके अतिरिक्त कंपनी ने भूमि के बदले 216 रोजगार प्रदान किए हैं तथा राजहरा ओपन कास्ट परियोजना का पुनः संचालन प्रारंभ किया गया है। उन्होंने पर्यावरण, सीएसआर एवं अन्य क्षेत्रों में कंपनी की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला। इसके अलावा सभी निदेशकगण, सीवीओ सर, जेसीएससी के केंद्रीय सचिव ने सभा को संबोधित किया। सभी ने श्रमिकों के समर्पण, साहस और उनके बलिदान को याद किया तथा कंपनी और देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्मियों को पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करने की बात कही। इस अवसर पर ट्रेड यूनियन प्रतिनिधि, सीएमओएआई, जेसीएससी, सेफ्टी बोर्ड, कल्याण विभाग, एसटी एससी ओबीसी काउंसिल, प्रेस प्रतिनिधि, महाप्रबंधक, विभागाध्यक्ष, अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान डी ए वी स्कूल के बच्चों द्वारा गणेश वंदना, गायन तथा आशा भोसले को समर्पित नृत्य प्रस्तुतियों ने वातावरण को भावपूर्ण बना दिया और सांस्कृतिक विविधता को मंच पर सजीव रूप में प्रस्तुत किया। श्रमिक दिवस के अवसर पर एआई अवतार "सीसीएल का ताऊ" लॉन्च किया गया। सीसी एंड पीआर विभाग के विभागाध्यक्ष आलोक कुमार गुप्ता ने बताया कि यह सीसीएल का ।P अवतार कंपनी की नीतियों, परियोजनाओं एवं उपलब्धियों की जानकारी रोचक तरीकों से साझा करने का माध्यम बनेगा। कार्यक्रम में सीसीएल की वार्षिक पत्रिका 'उत्कर्ष' का लोकार्पण किया गया, जिसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 की प्रमुख उपलब्धियों एवं कर्मचारियों की रचनात्मक अभिव्यक्तियों को स्थान दिया गया है। समारोह के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों एवं एरिया इकाइयों को सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनकी निष्ठा, परिश्रम एवं संगठन के प्रति समर्पण का प्रतीक है। महाप्रबंधक (पी एंड आईआर) प्रतुल कुमार ने कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्रम शक्ति के महत्व पर प्रकाश डाला।●

इन्फ्लुएंसर मीट 2026 का हुआ सफल आयोजन

● गुड्डी साव

पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने पतरातू स्थित होटल पर्यटन विहार में 11 मई को पर्यटन विभाग, झारखंड द्वारा राज्य स्तरीय इन्फ्लुएंसर मीट 2026 का सफल आयोजन के दौरान कहा कि झारखंड के पर्यटन स्थलों के प्रचार-प्रसार के लिए बड़े महानगरों के क्रिएटर्स को आमंत्रित किया जा सकता था, लेकिन झारखंड की असली पहचान, यहाँ की सादगी, संस्कृति और लोकजीवन को सबसे बेहतर ढंग से हमारे अपने राज्य के इन्फ्लुएंसर्स ही प्रस्तुत कर सकते हैं। हमारी कोशिश है कि झारखंड के युवा क्रिएटर्स जब किसी पर्यटन स्थल पर कंटेंट निर्माण करें, तो वे गर्व से कह सकें कि वे झारखंड पर्यटन विभाग के साथ जुड़े हुए हैं। इससे न केवल राज्य की ब्रांडिंग मजबूत होगी, बल्कि स्थानीय क्रिएटर्स को भी नई पहचान और अवसर प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विजन एवं पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य झारखंड के पर्यटन स्थलों, कला-संस्कृति, विरासत एवं स्थानीय खानपान को डिजिटल माध्यमों से राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी पहचान दिलाना है। कार्यक्रम के दौरान मंत्री सुदिव्य कुमार द्वारा 'इन्फ्लुएंसर एंगेजमेंट पोर्टल' का शुभारंभ किया गया। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य के कंटेंट क्रिएटर्स एवं इन्फ्लुएंसर्स को पर्यटन विभाग से औपचारिक रूप से जुड़कर कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। यह पहल डिजिटल क्रिएटर्स एवं पर्यटन विभाग के बीच एक सशक्त एवं संरचित साझेदारी स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। कार्यक्रम का उद्देश्य झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत, पर्यटन संभावनाओं एवं स्थानीय पहचान को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से व्यापक स्तर पर प्रस्तुत करना है। कार्यक्रम के दौरान इन्फ्लुएंसर्स के साथ संवाद सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें पर्यटन प्रचार, डिजिटल स्टोरीटेलिंग, कंटेंट निर्माण एवं झारखंड की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंच तक पहुँचाने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।●

सीएमपीडीआई में निदेशक के रूप में आनंद मोहन ने किया पदभार ग्रहण

● गुड्डी साव

श्री आनंद मोहन ने दिनांक 11 मई, 2026 को सीएमपीडीआई के निदेशक (तकनीकी) के रूप में पदभार ग्रहण किया। इससे पहले, उन्होंने कोल इंडिया की अन्य सहायक कंपनियों के साथ-साथ एनसीएल, सीसीएल और ईसीएल में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। श्री मोहन ने वर्ष 1989 में नेशनल इंस्टीच्यूट आफ टेक्नोलाजी कर्नाटका (एनआईटीके), सुरथकल से माइनिंग इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उसी वर्ष अमलोहरी परियोजना, एनसीएल, सिंगरौली से अपना करियर शुरू किया। तत्पश्चात् उन्होंने 2005 में इंडियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद से ओपन कास्ट माइनिंग में एम0टेक की उपाधि प्राप्त की और फर्स्ट क्लास माइन्स मैनेजर्स सर्टिफिकेट आफ काम्पीटेन्सी (डीजीएमएस) भी हासिल किया जो उनकी तकनीकी दक्षता और वैधानिक विशेषज्ञता का प्रमाण है। 36 वर्षों

से अधिक के अपने समृद्ध और विविध कोयला खनन क्षेत्र के अनुभव में श्री मोहन ने कोल इंडिया की विभिन्न सहायक कंपनियों में माइन प्लानिंग, कोर आपरेशन्स, परियोजना प्रबंधन, पुनर्वास, पर्यावरण प्रबंधन और डिजिटल परिवर्तन पहलों में गहरी विशेषज्ञता शामिल है। श्री मोहन ने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से अपने पेशेवर कौशल को समृद्ध किया है, जिनमें ओडीए कार्यक्रम के तहत यूनाइटेड किंगडम के वेल्स विश्वविद्यालय में पर्यावरण आकलन और प्रबंधन का प्रशिक्षण और उन्नत वैश्विक प्रबंधन कार्यक्रम शामिल हैं। इसके तहत उन्होंने तकनीकी अध्ययन के लिए कई यूरोपीय देशों का दौरा किया। वे इंस्टीच्यूशन आफ इंजीनियर्स (इंडिया) के फेलो और एमएमईएआई और एमजीएमआई दोनों के आजीवन सदस्य हैं। पदभार ग्रहण के साथ श्री मोहन सीएमपीडीआई के अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और व्यवसाय विकास प्रभागों के साथ-साथ अन्य प्रमुख विभागों का भी नेतृत्व करेंगे। उनकी व्यापक विशेषज्ञता, वैश्विक अनुभव और रणनीति दूरदर्शिता से न केवल सीएमपीडीआई बल्कि समस्त भारतीय कोयला उद्योग लाभान्वित होगा।●

यूनिफॉर्म पहनकर ही ऑटो एवं टोटो चलायेंगे चालक

● ओम प्रकाश

पुलिस अधीक्षक यातायात, राँची राकेश सिंह की अध्यक्षता में राँची जिला में सुगम यातायात व्यवस्था बनाये रखने हेतु बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वरीय पुलिस उपाधीक्षक-प्रथम, यातायात राँची, पुलिस उपाधीक्षक- द्वितीय, यातायात राँची, परिचारी प्रवर, यातायात राँची एवं सभी थाना प्रभारी, यातायात राँची उपस्थित थे। उक्त बैठक में पुलिस अधीक्षक यातायात, राँची के द्वारा राँची शहर में यातायात व्यवस्था को लेकर उपस्थित सभी पदाधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा किया गया, जो निम्नवत है : ब्लैक शीशा, फैन्सी नम्बर, मोडिफाईड साईलेंसर, प्रेशर हॉर्न, रेस ड्राईविंग एवं नशे की हालत में वाहन चलाने वाले के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई करेंगे। वाहनों पर निर्धारित सीट से अधिक पेसेंजर परिवहन किये जाने एवं नाबालिक के द्वारा वाहन चलाये जाने के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई करेंगे। ऑटो एवं टोटो के चालक यूनिफॉर्म नहीं पहन रहें हैं, उन्हें निश्चित रूप से यूनिफॉर्म धारण करने हेतु आदेशित करेंगे। प्राय: ऐसा देखा जा रहा है कि यातायात पोस्ट में लेफ्ट फ्री रहता है, परन्तु उस रास्ते पर भी वाहन खड़ा कर दिया जाता है, जिसके कारण लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है। सभी यातायात थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि यातायात पोस्ट में प्रतिनियुक्ति पुलिस कर्मियों के द्वारा अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से करते हुए सुगम यातायात व्यवस्था संधारण सुनिश्चित करायेंगे। वाहन नम्बर प्लेट पर लेप एवं गलत तरीके से लिखा हुआ नम्बर प्लेट वाले वाहनों के विरूद्ध विशेष अभियान चलाकर उनके विरूद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई करेंगे। सभी यातायात थाना प्रभारी स्कूल प्रारम्भ एवं समाप्ति अवधि के दौरान अपने-अपने थाना क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर सुगम यातायात व्यवस्था संधारण करायेंगे तथा अपने-अपने क्षेत्र में निरंतर भ्रमणशील रहकर अनावश्यक रूप से चौक-चौराहों पर खड़े कर रहें वाहनों के विरूद्ध कार्रवाई करेंगे। पुलिस अधीक्षक यातायात राँची के द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पुलिस पदाधिकारियों को उपरोक्त विचार-विमर्श पर अनुपालन करने के लिए निर्देशित किया गया।●

नक्सलवाद को बड़ा झटका

27 नक्सलियों ने एक साथ किया सरेंडर

● ओम प्रकाश

झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान को बड़ी सफलता मिली है। राज्य गठन के बाद पहली बार एक साथ 27 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। डीजीपी तदाशा मिश्रा और सीआरपीएफ आईजी साकेत सिंह के समक्ष नक्सलियों ने सरेंडर किया। इनमें 25 भाकपा (माओवादी) और 2 जेजेएमपी संगठन के उग्रवादी शामिल हैं। सरेंडर करने वालों में कई शीर्ष कमांडर, सब-जोनल कमेटी सदस्य, एरिया कमांडर और सक्रिय दस्ता सदस्य शामिल हैं। इन पर कुल 33 लाख रुपये का इनाम घोषित था और विभिन्न जिलों में कुल 426 मामले दर्ज हैं। रांची के धुर्वा स्थित झारखंड पुलिस मुख्यालय में आयोजित विशेष कार्यक्रम में सभी नक्सलियों ने हथियार डालकर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया। इस दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में आधुनिक हथियार और हजारों गोलियां भी पुलिस को सौंपीं। पुलिस अधिकारियों ने इसे झारखंड में नक्सली नेटवर्क के कमजोर होने का बड़ा संकेत बताया है। अधिकारियों का कहना है कि लगातार चल रहे अभियान, जंगलों में दबाव और सुरक्षा बलों की रणनीति के कारण नक्सली संगठन टूट रहे हैं।

❖ **पहली बार इतनी बड़ी संख्या में हुआ सामूहिक आत्मसमर्पण :-** सीआरपीएफ, झारखंड पुलिस और खुफिया विभाग लंबे समय से सारंडा और कोल्हान क्षेत्र में अभियान चला रहे थे। सुरक्षा एजेंसियों को सूचना मिली थी कि कई नक्सली जंगल छोड़ना चाहते हैं। पिछले एक महीने से इन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की प्रक्रिया चल रही थी। पुलिस का कहना है कि यह सिर्फ आत्मसमर्पण नहीं, बल्कि नक्सली संगठन की कमजोर होती पकड़ का संकेत है। अधिकारियों के मुताबिक, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह नक्सलियों के सरेंडर के मामले बढ़े हैं।

❖ **जेजेएमपी के दो उग्रवादियों ने भी डाले हथियार :-** गुमला जिले में सक्रिय जेजेएमपी संगठन के दो उग्रवादियों ने भी आत्मसमर्पण किया। इनमें सचिन बैक और श्रवण गोप शामिल हैं। सचिन बैक पर 5 लाख रुपये का इनाम घोषित था।

❖ **भारी मात्रा में हथियार और गोलियां बरामद :-** सरेंडर के दौरान नक्सलियों ने पुलिस को कई आधुनिक हथियार सौंपे। इनमें 1 इंसास एलएमजी, 5 इंसास राइफल, 9 एसएलआर राइफल, 1 बोल्ट एक्शन राइफल, 1 पिस्टल, 31 मैगजीन, करीब 3000 जिंदा कारतूस, कई वॉकी-टॉकी सेट शामिल हैं। इसके अलावा जेजेएमपी उग्रवादियों ने एक इंसास राइफल और

सरेंडर करने वालों में कई ऐसे नक्सली शामिल हैं, जो लंबे समय से पुलिस के लिए चुनौती बने हुए थे, इनमें शामिल हैं :-

- ☞ गादी मुंडा उर्फ गुलशन :- 5 लाख का इनामी, 48 मामले दर्ज।
- ☞ नागेंद्र मुंडा उर्फ प्रभात मुंडा :- 5 लाख का इनामी, 38 मामले।
- ☞ रेखा मुंडा उर्फ जयंती :- 5 लाख का इनामी।
- ☞ सागेन आंगारिया उर्फ दोकोल :- 5 लाख का इनामी, 123 मामले।
- ☞ दर्शन उर्फ बिंज हांसदा :- 5 लाख का इनामी।
- ☞ सुलेमान हांसदा उर्फ सुनी हांसदा :- 5 लाख का इनामी।
- ☞ करण तियू :- 2 लाख का इनामी।
- ☞ बासुमती जेराई उर्फ बासू :- 1 लाख का इनामी।

इनके अलावा कई सक्रिय महिला और पुरुष कैडर ने भी आत्मसमर्पण किया है।

130 राउंड गोलियां जमा की।

❖ **सारंडा और कोल्हान में कमजोर पड़ रहा नेटवर्क** :- पुलिस अधिकारियों के अनुसार, कोल्हान और सारंडा के जंगलों में लंबे समय से सुरक्षा बलों का दबाव बढ़ा है। लगातार ऑपरेशन के कारण नक्सलियों की आवाजाही और सप्लाई सिस्टम प्रभावित हुआ है। नए युवाओं की भर्ती भी कम हुई है। अधिकारियों का कहना है कि आत्मसमर्पण करने वालों को सरकार की पुनर्वास नीति के तहत आर्थिक सहायता, प्रशिक्षण और रोजगार से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ताकि वे सामान्य जीवन जी सकें।

❖ **डीजीपी ने क्या कहा** :- डीजीपी तदाशा मिश्रा ने कहा कि यह सफलता सुरक्षा बलों की संयुक्त रणनीति का परिणाम है। आने वाले दिनों में नक्सल प्रभावित इलाकों में और अभियान तेज किए जाएंगे, ताकि क्षेत्र में स्थायी शांति कायम हो सके।●

❖ **आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की सूची** :-

★ **भाकपा (माओवादी) संगठन** :-

☞ करण उर्फ डांगुर तियू
☞ गादी मुण्डा उर्फ गुलशन
☞ नागेंद्र मुण्डा उर्फ प्रभात मुण्डा उर्फ मुखिया उर्फ पराउ
☞ रेखा मुण्डा उर्फ जयंती
☞ सागेन आंगारिया उर्फ दोकोल उर्फ याम लाल आंगारिया
☞ दर्शन उर्फ बिंज हांसदा
☞ सुलेमान हांसदा उर्फ सुनी हांसदा उर्फ चंबरा
☞ बैजनाथ मुण्डा
☞ बासुमती जेराई उर्फ बासू उर्फ सरस्वाती
☞ रघु कायम उर्फ गुणा
☞ किशोर सिरका उर्फ दुर्गा सिरका
☞ राम दयाल मुण्डा
☞ वंदना उर्फ शांति
☞ सुनिता सरदार उर्फ बारी
☞ डांगुर बोइपाई उर्फ मुकेश
☞ बसंती देवगम
☞ मुन्नीराम मुण्डा
☞ अनिशा कोड़ा उर्फ रानी
☞ सपना उर्फ सुरू कालुंडिया
☞ सुसारी उर्फ दसमा कालुंडिया
☞ बिरसा कोड़ा उर्फ हरिसिंह
☞ नुअस
☞ बुमली तियू उर्फ दामू चरण तियू
☞ निति माई उर्फ निति हेंब्रम
☞ लादू तिरिया

★ **जेजेएमपी संगठन** :-

☞ सचिन बैक
☞ श्रवण गोप

बिशप हार्टमन अकादमी के छात्रों ने मारी बाजी

● **ओम प्रकाश**

बिशप हार्टमन अकादमी के छात्र-छात्राओं ने आईएससी 12 और आईसीएसई-एक्स 2026 परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।30 अप्रैल 2026 को जारी परिणाम में छात्राओं में काफी उत्साह देखने को मिला। सुबह का वक्त था। रिजल्ट आने से पहले कई घरों में बेचैनी थी। कोई मोबाइल पर वेबसाइट रिफ्रेश कर रहा था, तो कोई चुपचाप भगवान का नाम ले रहा था। जैसे ही ISC और ICSE 2026 का रिजल्ट सामने आया, रांची के अरागेट महिलोंग स्थित BHA यानी बिशप हार्टमन अकादमी के बच्चों के चेहरों पर राहत और खुशी एक साथ दिखी। इस बार स्कूल का रिजल्ट 100% रहा। हर बच्चा पास हो गया। बच्चों ने आईएससी 12 और आईसीएसई-एक्स 2026 परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर न सिर्फ अपने बिशप हार्टमैन अकादमी स्कूल का बल्कि अपने माता-पिता का भी नाम रोशन किया।

☞ **ICSE 12 SCIENCE :-** ICSE 12 साइंस में प्रथम स्थान ज्योति कुमारी 87.00 प्रतिशत, दूसरे स्थान पर नैतिक कुमार सिंह 83. 20% और तीसरे स्थान पर बैजनाथ सिंह मुंडा 82.00 प्रतिशत।

☞ **ICSE 12 COMMERCE :-** कृष कुमार 90.20% , दूसरे स्थान पर शिवम श्रीवास्तव 90.00 प्रतिशत और तीसरे स्थान पर तनुश्री कुमारी महतो 84.70% ।

☞ **ICSE 2026-एक्स** :- इससे में प्रथम स्थान सत्य लकड़ा 96% ,दूसरे स्थान पर तनाष उराघ्व 95.69 घ, तीसरे स्थान पर आलोक कुमार महतो 94 80% ,चौथा स्थान पर तेजस्विनी भारती 92.40% पांचवें स्थान पर सुहाना राय 92.00घ और पांचवें स्थान पर हिमांशु कुमार 92.00% लाकर अपने स्कूल व माता-पिता का नाम रोशन किया।

☞ **प्रिंसिपल ने बच्चों की मेहनत को दिया श्रेय** :- स्कूल के प्रिंसिपल फादर ऑस्वाल्ड मढ़ता ने कहा कि 100% परिणाम विद्यालय के छात्र-छात्राओं के मेहनत का फल है।यह सफलता बच्चों की लगन और शिक्षकों के समर्पण का नतीजा है। उन्होंने कहा कि स्कूल का लक्ष्य सिर्फ अच्छे नंबर लाना नहीं, बल्कि बच्चों को अच्छा इंसान बनाना भी है। वही विद्यालय प्रबंधन एवं शिक्षक शिक्षिकाओं ने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए कामना की है।●

रात के सन्नाटे में पुलिसिंग की रियलिटी चेक

रात करीब 12 बजे का वक्त जब शहर की सड़कें धीरे-धीरे शांत हो रही थीं। ज्यादातर लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे। लेकिन इसी बीच राजधानी रांची की सड़कों पर पुलिस की हलचल अचानक तेज हो गई। राजधानी राँची की सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद करने और रात के समय पुलिस पदाधिकारियों/कर्मियों की सक्रियता जांचने के लिए एसएसपी राकेश रंजन खुद रविवार की देर रात सिविल ड्रेस में अचानक निकल पड़े। एसएसपी राकेश रंजन ने सिटी एसपी पारस राणा के साथ मिलकर राजधानी के कई प्रमुख थानों का औचक निरीक्षण किया। जैसे-जैसे एसएसपी का काफिला एक थाना से दूसरे थाना पहुंचता गया, वैसे-वैसे पुलिस महकमे में हलचल बढ़ती चली गई।

☞ **शहर के थानों में अचानक पहुंचे एसएसपी :-** मिली जानकारी के अनुसार, एसएसपी राकेश रंजन और सिटी एसपी पारस राणा आधी रात के बाद कोतवाली, अरगोड़ा और सुखदेवनगर समेत कई अन्य थानों में अचानक पहुंचे।रात के सन्नाटे में जब एसएसपी शहर के अलग-अलग थानों में पहुंचे तो वहां मौजूद पुलिसकर्मी तुरंत सक्रिय हो गए। किसी थाना में ड्यूटी रजिस्टर देखा गया, तो कहीं गश्ती दल की जानकारी ली गई। एसएसपी ने थाना परिसर, हाजत और रिकॉर्ड रूम तक का निरीक्षण किया। उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि रात के समय पुलिस कितनी सतर्क है और शहर में सुरक्षा व्यवस्था किस तरह संभाली जा रही है। कई जगहों पर उन्होंने ड्यूटी में लगे जवानों से सीधे बात भी की।रात में गश्ती गाड़ियां रूट पर सक्रिय हैं या नहीं, इसकी लाइव लोकेशन और रिपोर्ट भी जांची गई।

☞ **सड़क पर भी दिखी सख्ती :-** निरीक्षण सिर्फ थानों तक सीमित नहीं रहा। एसएसपी ने सड़क पर चल रही पुलिस गतिविधियों को भी देखा। कई चौक-चौराहों पर वाहन जांच अभियान चलाया गया। देर रात घूम रहे लोगों से पूछताछ हुई। संदिग्ध वाहनों की तलाशी ली गई। पुलिस अधिकारियों को साफ निर्देश दिया गया कि रात के समय गश्ती में किसी तरह की ढिलाई नहीं होनी चाहिए। खासकर उन इलाकों में ज्यादा सतर्कता बरतने को कहा गया, जहां पहले अपराध की घटनाएं सामने आ चुकी हैं।

☞ **लंबित मामलों पर भी हुई चर्चा :-** एसएसपी ने निरीक्षण के दौरान थानों में दर्ज मामलों की स्थिति भी जानी। उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि किन मामलों की जांच लंबित है और किस स्तर पर कार्रवाई चल रही है। साफ कहा गया कि पुराने मामलों का जल्द निष्पादन होना चाहिए और जांच में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही थाना प्रभारियों को रिकॉर्ड अपडेट रखने और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।

☞ **पुलिसकर्मियों को दिया स्पष्ट संदेश :-** इस निरीक्षण का सबसे बड़ा संदेश यही रहा कि अब राजधानी में पुलिसिंग को और ज्यादा सक्रिय बनाने पर जोर दिया जा रहा है। एसएसपी ने पुलिसकर्मियों से कहा कि आम लोगों की सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। रात के समय पुलिस की मौजूदगी लोगों में भरोसा पैदा करती है और अपराधियों में डर। उन्होंने साफ कहा कि हर थाना अपने इलाके में लगातार निगरानी रखे और छोटी से छोटी सूचना को भी गंभीरता से ले।● **रिपोर्ट :- ओम प्रकाश**

NAWADA VIDHI MAHAVIDYALAYA

Recognised by Bar Council of India, New Delhi Govt. Of Bihar, Patna

Permanently Affiliated to Magadh University, Bodhgaya
NAAC Accredited Grade 'B'
Website :- nawadavidhi.ac.in | Email ID-nvmnawada@gmail.com

ADMISSION OPEN FOR SESSION 2026-2027

Courses Offered

1. B.A. LL.B. (5 Years IntegratedCourse)
2. B.B.A. LL.B. (5 Years Integrated Course)
3. LL.B. (3 Years Degree Course)
4. LL.B (HONS) 3 Years

Important Dates

>Apply form - 11th May
>Last date to apply - 10th June
>Admission Test - 15th June
>Result Publication- 18th June
>Admission Starts -22nd June

NOTE - Candidates having more than 60% and above marks in any streams are eligible for direct admission. Other conditions will remain same as per BCI New Delhi/ State norms.

CONTACT US - 9955609013, 9431224775, 9065457964
VISIT US AT- www.nawadavidhi.com

(Dr. D.N. Mishra)
Principal

NAWADA VIDHI MAHAVIDYALAYA

NAAC 'B' Grade Accredited Institution
An ISO 21001:2018 Certified Institution
Campus-I : Kendua, Akauna Bazar, Nawada, Pin-805123
Campus-II : Police Line, Jalalpur Sanokhra Road, Nawada, Pin-805112
(Conducted under societies registration Act 1860 u/s 21)

Recognised by Bar Council of India, New Delhi & Govt. of Bihar, Patna | Permanently Affiliated to Magadh University, Bodh-Gaya
Website :- nawadavidhi.org | Email ID-nvmnawada@gmail.com

Walk- In-Interview

Nawada Vidhi Mahavidyalaya invites application for the following posts -

S.No.	Name of Post	Subject	Number of Posts	Eligbility
1.	Assistant Professor	Law	06	Qualification as per the norms of UGC/BCI/Magadh University/Govt. of Bihar
2.	Assistant Professor	Non-Law		Qualification as per the norms of UGC/BCI/ Magadh University/ Govt. of Bihar
		Pol. Science	02	
		History	02	
		Sociology	02	Masters degree in relevant subject along with LL.B degree will be preferred
		English	01	
		Economics	02	
		MBA	02	
		M.COM	01	
3.	Computer Operator	02		Graduation with Diploma/Certificate in Computer Application.
4.	Electrician	02		ITI
5.	Plumber	01		ITI
6.	CareTaker	01		Graduation
7.	Sweeper	04 (Male-02 / Female-02)		Matriculation or Equivalent or Literate
8.	Peon	04 (Male-02 / Female-02)		Matriculation or Equivalent or Literate
9.	Driver	02		Heavy Motor Vehicle Licence for more than 10 years

N.B; Interested Candidates should send their updated Resume with relevant documents through registered post or on our official mail before 25th June 2026. Interview Scheduled on dated 27th June 2026 at College Campus II.

(Dr. D.N. Mishra)
Principal

मेष राशि :- करियर में कुछ शानदार अवसर प्राप्त होंगे,आर्थिक रूप से समय मिला-जुला है और स्वास्थ्य में पैरों या पीठ से जुड़ी कुछ समस्याएं हो सकती है, लेकिन आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा।

वृषभ राशि :- लव लाइफ काफी अच्छी रहेगी करियर के मोर्चे पर काम का दबाव थोड़ा अधिक रह सकता है इसलिए धैर्य बनाए रखने की सलाह दी गई है, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय बहुत मजबूत साबित होगा, महीने की शुरुआत में आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं किंतु बाद में स्वास्थ्य उत्तम रहेगा,स्वास्थ्य संबंधी कारणों से आपकी शिक्षा में व्यवधान आ सकता है. पारिवारिक जीवन में मिला जुला प्रभाव देखने को मिलेगा यानी थोड़ी खुशी तो कभी थोड़ी परेशानी होगी!

मिथुन राशि :- नौकरी करने वालों को इस माह में आमदनी बढ़ेगी जो उनमें प्रसन्नता का संचार करेंगी,आर्थिक दृष्टि से पूरे महीने आपकी स्थिति उतार-चढ़ाव भरी रहने वाली है,स्वरोजगार करने वाले लोगों की आय में वृद्धि होगी, आपको इस माह स्वास्थ्य के लिहाज से सावधान रहना होगा क्योंकि जरा सी असावधानी आपके लिए परेशानियां लेकर आ सकती है,जहां तक पारिवारिक जीवन का सवाल है, समय अच्छा बीतेगा!

कर्क राशि :- कुछ संबंधों में कठिनाई आने से आप मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं, नौकरीपेशा लोगों को वेतन भत्तों में वृद्धि होने की सूचना मिल सकती है जिससे आप आनंदित महसूस करेंगे,कारोबारियों के लिए यह महीना अच्छा मुनाफा देने वाला है,स्वास्थ्य की दृष्टि से आप पूरे माह स्वस्थ रहेंगे जिससे मन प्रफुल्लित रहेगा, छात्र छात्राओं के करियर के लिहाज से माह की शुरुआत कमजोर रहने वाली है, पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव बना रहेगा!

सिंह राशि :- करियर में सफलता मिलेगी, यह माह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है, बस आपको अपनी क्षमता का उत्कृष्ट प्रदर्शन करना है, दफ्तर में आपके काम की तारीफ हो सकती है, आमदनी का कोई अतिरिक्त जरिया भी बन सकता है. कारोबारियों के लिए यह माह आर्थिक दृष्टि से अच्छा रहने वाला है. इस राशि के लोगों को सेहत के लिहाज से बेहद सावधानी के साथ चलने की जरूरत है, माह की शुरुआत विवाहित लोगों के लिए अच्छी नहीं रहेगी, पारिवारिक जीवन में संतुष्टि का अभाव रहेगा!

कन्या राशि :- कार्यस्थल पर समय आनंददायक रहने वाला है, जो भी काम कर रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त होगी. नौकरी के नए अवसर प्राप्त होंगे लेकिन प्रयास करना होगा. आर्थिक दृष्टि से यह माह अच्छा नहीं रहने वाला है, एक तरफ आपकी आय में कमी के आसार हैं तो दूसरी ओर खर्चों की अधिकता रहेगी जो चिंता बढ़ाएगी. स्वास्थ्य कमजोर रहेगा, पारिवारिक जीवन उतार - चढ़ावों से भरा रहेगा!

तुला राशि :- नौकरीपेशा लोगों को परिश्रम करना होगा जिससे अच्छी सफलता मिल सकती है, आय के स्रोत बने रहेंगे, कारोबारियों के लिए आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और लाभ दिखेगा, इस दौरान रुका हुआ धन मिल जाएगा. छात्रों के करियर के लिहाज से समय अनुकूल है, स्वास्थ्य की दृष्टि से महीना मिला जुला असर दिखाने वाला है, माह का प्रारंभ अपेक्षाकृत अच्छा रहने वाला है, पारिवारिक सुख के लिहाज से यह महीना कुछ परेशानी भरा हो सकता है!

वृश्चिक राशि :-अपने टारगेट पर फोकस करें तो सार्थक परिणाम प्राप्त होंगे,नौकरी में आपका खूब मन लगेगा जिससे

आपका राशिफल

पंडित तरुण झा
ज्योतिषचार्य
(ज्योतिष, वास्तु एवं रत्न विशेषज्ञ)
ब्रज किशोर ज्योतिष संस्थान
प्रताप चौक, सहरसा-852201,
(बिहार)
मो० :- 9470480168

उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे,कारोबार के लिहाज से इस माह अच्छा लाभ मिलने वाला है, आय के संसाधनों में वृद्धि होगी,स्वास्थ्य की दृष्टि से समय बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है, छोटी - मोटी परेशानियां बनी रहेंगी, पारिवारिक सुख की दृष्टि से यह महीना आपके लिए औसत से बेहतर रहने वाला है, घर-परिवार में आनंद का वातावरण रहेगा!

धनु राशि :- नौकरी करने वालों के लिए इस माह कार्यस्थल पर अच्छा वातावरण रहने वाला है, कारोबारी लिहाज से सब ठीक रहने वाला है, धन दौलत में वृद्धि होगी और एक से अधिक स्रोतों से आपको आय होगी, युवाओं के करियर के मामले में काफी अच्छा समय रहेगा, इस माह आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है, इस दौरान बीमारियों का मुकाबला करने की क्षमता आपकी बढ़ी रहेगी, पारिवारिक जीवन अच्छा रहने वाला है, घर-परिवार में सुख-शांति की स्थिति बनी रहेगी!

मकर राशि :- कुछ काम बनते-बनते रुक सकते हैं जो तनाव का कारण बन सकते हैं किंतु तनाव लेने की जरूरत नहीं है,नौकरी करने वालों के लिए यह महीना उतार चढ़ाव वाला हो सकता है. कारोबारियों के लिए यह महीना अच्छा है, आय के नए स्रोत खुलेंगे, पुराने स्रोतों से भी आय होती रहेगी किंतु गलत तरीके से धन कमाने की न सोचें. आपकी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का निवारण होने की संभावना है, लेकिन किसी तरह की चोट-चपेट की आशंका है. पारिवारिक जीवन परेशानी भरा रह सकता है, परिवार में किसी बात को लेकर तनाव की स्थिति हो सकती है!

कुंभ राशि :- नौकरी पेशा लोगों के लिए उन्नति मिलने का योग बन रहा है, उन्हें मन लगाकर काम करना चाहिए. कारोबारियों के लिए भी यह समय अच्छा है, कोई पुराना रुका हुआ ऐसा भुगतान प्राप्त हो सकता है जिसे आप डूबा हुआ मान रहे थे, व्यापार में आपके लिए सफलता का समय है. स्वास्थ्य सामान्य रहने वाला है, कोई बड़ी परेशानी नहीं होने वाली है. पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा किंतु काम धंधे के चक्कर में व्यर्थ की भागदौड़ करनी पड़ सकती है!

मीन राशि :-नौकरी करने वालों को अपने कार्यस्थल पर कड़ी मेहनत करनी होगी, सरकारी नौकरी के योग भी बनेंगे लेकिन सफलता के लिए भागदौड़ और कठिन परिश्रम करना होगा. करियर के लिहाज से यह माह अच्छा है, कारोबारियों के लिए आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है लेकिन खर्चे अधिक होंगे, इन बढ़े हुए खर्चों को लेकर आप में चिड़चिड़ापन भी आ सकता है,स्वास्थ्य के लिहाज से यह महीना सामान्य रहने वाला है, आपको सतर्क रहने की जरूरत है, पारिवारिक जीवन परेशानी भरा रह सकता है!

शिवानंद गिरि

(अधिवक्ता)

Ph.- 9308454485

7004408851

E-mail :-shivanandgiri5@gmail.com

★ अगर कोई पुलिस अधिकारी केस दर्ज करने से मना करता है या इसके बदले नाजायज पैसों की मांग करता है तो इसके लिए कानून में क्या प्रावधान है?

अगर कोई पुलिस अधिकारी एफआईआर (FIR) दर्ज करने से मना करता है या इसके बदले नाजायज पैसों (रिश्वत) की मांग करता है या आपसे पुलिस वाले इसके लिए पेपर पेन या चाय ,बिस्कुट, पान, सिगरेट या अन्य किसी भी प्रकार का सामान खरीद कर लाने को कहता है, तो भारतीय कानून में इसके खिलाफ कड़े प्रावधान हैं। 1 जुलाई, 2024 से लागू नए आपराधिक कानूनों के तहत भी आपको कई अधिकार दिए गए हैं :-

❖ अगर पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना करे :-

यदि थाना प्रभारी (SHO) आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करता है, तो आप निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं :- वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित शिकायत:- आप अपनी शिकायत की पूरी जानकारी लिखित में डाक (Registered Post) के जरिए संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक (SP) या डिप्टी कमिश्नर (DCP) को भेज सकते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 173 (3) के तहत एसपी को यह अधिकार है कि वह खुद जांच करे या किसी अधीनस्थ अधिकारी को जांच का निर्देश दे।

☞ **मजिस्ट्रेट के पास आवेदन :** अगर एसपी भी कार्रवाई नहीं करते हैं, तो आप ठछै की धारा 175 (3) (जो पहले CrPC 156(3) थी) के तहत संबंधित मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मजिस्ट्रेट पुलिस को तुरंत एफआईआर दर्ज करने और जांच शुरू करने का आदेश दे सकता है।

☞ **हाईकोर्ट में रिट याचिका :** अंतिम विकल्प के रूप में, आप संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में 'रिट ऑफ मैंडमस' (Writ of Mandamus) दाखिल कर सकते हैं, जिसमें कोर्ट पुलिस को अपना कानूनी कर्तव्य निभाने का आदेश देता है।

ऑनलाइन एफआईआर (e-FIR) : आप राज्य पुलिस की वेबसाइट या मोबाइल ऐप का उपयोग करके भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

❖ अगर पुलिस अधिकारी रिश्वत मांगे :- रिश्वत मांगना भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) के तहत एक गंभीर अपराध है। इसके खिलाफ आप यहाँ शिकायत कर सकते हैं:-

☞ **एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB)/सतर्कता विभाग (Vigilance Department) :-** हर राज्य में भ्रष्टाचार विरोधी शाखाएं होती हैं। आप वहां लिखित शिकायत दे सकते हैं। वे अधिकारी को रंगे हाथों पकड़ने के लिए 'ट्रैप' (जाल) भी बिछा सकते हैं।

☞ **पुलिस शिकायत प्राधिकरण (Police Complaints Authority) :-** राज्य और जिला स्तर पर यह प्राधिकरण पुलिस के दुर्व्यवहार और भ्रष्टाचार की शिकायतों की सुनवाई के लिए बनाया गया है।

❖ **दोषी पुलिसकर्मी को सजा :-** सुप्रीम कोर्ट के 'ललिता कुमारी' मामले के फैसले के अनुसार, संज्ञेय अपराध (Cognizable Offence) में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। कर्तव्य पालन न करने वाले अधिकारी को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 198 (पुरानी IPC 166।) के तहत 6 महीने से 2 साल तक की सजा हो सकती है। एक जरूरी बाते यह भी है कि अपनी शिकायत की एक कॉपी हमेशा अपने पास रखनी चाहिए और उस पर पदाधिकारी का 'रिसीविंग' (पावती) जरूर लेना चाहिए। यदि अधिकारी लिखित में लेने से मना करे, तो उसे डाक के जरिए भेजें ताकि आपके पास प्रमाण रहे।

★ जानिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 (BNSS- 358) का कानून क्या कहता है?

दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 319 (BNSS-358)के तहत, किसी अपराध की जांच या सुनवाई के दौरान, अगर किसी व्यक्ति के बारे में सबूत मिलते हैं कि उसने कोई अपराध किया है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है. इस धारा के तहत, आरोपी के साथ मिलकर मुकदमा चलाया जा सकता है।

❖ सीआरपीसी की धारा 319 (BNSS-358) से जुड़ी कुछ खास बातें :-

☞ इस धारा के तहत, अगर किसी व्यक्ति का नाम एफआईआर में नहीं है, लेकिन उसकी संलिप्तता के पर्याप्त सबूत हैं, तो उसे आरोपी बनाया जा सकता है।

☞ इस धारा के तहत, आरोपी को तलब करने के लिए मजबूत और विश्वसनीय सबूत होने चाहिए।

☞ इस धारा के तहत, समन किए गए व्यक्ति को आरोपी के रूप में शामिल करने से पहले सुनवाई का अवसर देने की जरूरत नहीं होती।

☞ इस धारा के तहत, आरोपी को तलब करने में मशीन की तरह काम नहीं करना चाहिए।

☞ इस धारा के तहत, शक्ति का इस्तेमाल दोषसिद्धि के मामलों में सजा सुनाए जाने से पहले या दोषमुक्ति का आदेश देने से पहले किया जाना चाहिए।

★ अगर समय से क्रिमिनल केस का ट्रायल पूरा नहीं होता है तो उसके लिए क्या कानूनी प्रक्रियाएं हैं?

अगर क्रिमिनल केस का ट्रायल समय पर पूरा नहीं होता, तो नए कानून के मुताबिक, कई तरह की समय सीमाएं तय की गई हैं :-

☞ आरोपी को सात दिन के अंदर अपील करने का अधिकार है।

☞ न्यायाधीश को सात दिन के अंदर सुनवाई पूरी करनी होगी।

☞ ट्रायल पूरा होने और बहस पूरी होने के बाद, अदालत को 30 दिनों में फैसला सुनाना होगा।

☞ लिखित रूप से कारण दर्ज करने पर, फैसला देने की अवधि 45 दिन तक हो सकती है।

☞ सुप्रीम कोर्ट के अपील खारिज करने के 30 दिनों के अंदर दया याचिका दाखिल करनी होगी।

इसके अलावा, नए कानून के मुताबिक, केस में दस्तावेजों की प्रक्रिया को भी 30 दिनों में पूरा करने की समय सीमा दी गई है। नए कानून के तहत, अगर आरोप तय होने के 30 दिनों के अंदर आप अपना गुनाह स्वीकार कर लेंगे, तो सजा कम होगी।

सामाजिक एवं बौद्धिक क्षेत्र में रोजगार का सुनहरा अवसर

केवल सच सामाजिक संस्थान और श्रुति कम्युनिकेशन ट्रस्ट अपने भविष्य के आगामी योजनाओं में सामाजिक एवं बौद्धिक सुधार के क्षेत्र में पुर्नजागरण के शंखनाद हेतु बिहार और झारखण्ड राज्य के मेधावी/सक्षम/योग्य/दक्ष एवं कर्मठ नवयुवकों को अपने टीम में वैतनिक/अवैतनिक रूप से जुड़ने के लिए अवसर प्रदान करना चाहती है। उक्त स्वयंसेवी संस्थान मुख्य रूप से 'अपना घर' (वृद्धाश्रम आवास योजना), परिवार परामर्श केन्द्र, शिक्षा का संक्षिप्त पाठ्यक्रम (मूल रूप से निर्धन/बेसहारा लड़कियों हेतु) और विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता कार्यक्रम पर ध्यान केन्द्रीत करना चाहती है। इन कार्यक्रमों से जुड़कर नवयुवक सामाजिक क्षेत्र में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। उक्त संगठन इसके लिए टीम वर्क के तहत कार्य करना चाहती है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय समन्वयक के अधीन वार्ड/ पंचायत/ प्रखण्ड/ अनुमण्डल/जिला समन्वयकों की नियुक्ति भी करना चाहती है। इस संस्थान से जुड़कर इच्छुक नवयुवक उक्त पदों पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं।

संस्थान

shruti कम्युनिकेशन ट्रस्ट

श्रुति कम्युनिकेशन ट्रस्ट

भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के तहत संचालित

निबंधन संख्या : 22333/2008, आयकर निबंधित : 12 ए ए/2012-13/2549-52 | 80 जी (5)/तक०/2013-14/1073

केवल सच सामाजिक संस्थान

भारतीय सोसायटी एक्ट 21, 1860 के तहत निबंधित

निबंधन संख्या : 1141 (2009-10), आयकर निबंधित : 12 ए ए/2012-13/2505-8 | 80 जी (5)/तक०/2013-14/1060-63

KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN

www.shruticommunicationtrust.org

www.ks3.org.in

Regd. Office:- East Ashok Nagar, House No.-28/14, Road No.-14, kankarbagh, Patna- 8000 20 (Bihar)
Jharkhand State Office:- **Riya Plaza, Flat No.-303, Kokar Chowk, Ranchi**
Mob.- 9431073769

WESTERLIN DRUGS PVT. LTD.
(Serving nation since 1990)

WESTOCITRON
WESTOCLAV
WESTOFERON
WESTOPLEX
QNEMIC

AOJ
AZIWEST
DAULER
MUCULENT
AOJ-D
BESTARYL-M
GAS-40
MUCULENT-D

SEVIPROT
WESTOMOL
WESTO ENZYME
ZEBRIL

WESTERLIN DRUGS PVT. LTD. · Dispersing Happiness

WESTERLIN DRUGS PVT. LTD.

Industrial area, Fatuha-803201
E-mail- westerlindrugsprivatelimited@gmail.com
Phone No.:0162-3500233/2950008